राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 56

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 5 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

ओलिंपिक के बाद शादी करेंगे दहिया

>> 12

रवि ने बिखेरी चमक, लवलीना ने जीता कांस्य

कजाखस्तान के नूरइस्लाम सानायेव को दबोचते रवि (बाएं) • रायटर

- फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने रवि दहिया
- लवलीना फाइनल में जगह बनाने वाली भारत की पहली मुक्केबाज बनने से चूकीं

भारत के अन्य परिणाम

- महिला हाकी टीम को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों 1-2 से हार मिली। भारतीय टीम अब गुरुवार को कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन का सामना करेगी
- गोल्फ में अदिति अशोक पहले दौर में चार अंडर 67 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि दीक्षा डागर 56वें स्थान पर रहीं

दीपक व अंशु की उम्मीदें कायम

पहलवान दीपक पूनिया को पुरुषों के 86 किग्रा भार वर्ग के सेमीफाइनल में अमेरिका के डेविड मौरिस टेलर से 0-10 से हार मिली। अब वह गुरुवार को कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में अंशु मलिक पहले मुकाबले में ही बेलारूस की यूरोपीय चैंपियन इरिना कुराचिकिना से 2-8 से हार गईं। अंशु के पास रेपचेज से कांस्य पदक जीतने का मौका है, क्योंकि कुराचिकिना फाइनल में पहुंच गई।

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: टोक्यो ओलिंपिक में बुधवार को भारत के पहलवान रवि दहिया ने फाइनल में पहुंचकर कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया, जबकि मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई को सेमीफाइनल में हार के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत के अब टोक्यो ओलिंपिक में चार पदक पक्के हो गए हैं। इसके साथ ही एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में क्वालीफाइंग दौर में 32 खिलाड़ियों के बीच शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाकर पदक की उम्मीद बढ़ा दी है।

आखिरी मिनट में रवि ने पलटी बाजी: रवि (पुरुष 57 किग्रा) ने कजाखस्तान के नूरइस्लाम सानायेव को हराकर स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाई। एक समय रवि 7-9 से पीछे थे, लेकिन तभी उन्होंने विरोधी के दोनों कंधे मैट पर लगा दिए, जिसके बाद मैच वहीं खत्म कर दिया गया। रवि ओलिंपिक फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान हैं। उनसे पहले सुशील कुमार 2012 लंदन ओलिंपिक के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा था। अब रवि के पास कुश्ती में भारत को पहला स्वर्ण जिताकर इतिहास रचने का मौका है।

संबंधित खबरें >> पेज 12

नीरज ने 86.65 मीटर पर फेंका भाला

ओलिंपिक पदार्पण कर रहे नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल के लिए क्वालीफिकेशन मार्क 83.50 मीटर था।

अच्छा मुकाबला लवलीना बोरगोहाई। मुक्केबाजी रिंग में आपकी कामयाबी से कई भारतीयों को प्रेरणा मिली है। आपकी दृढ़ता और समर्पण प्रशंसनीय है। कांस्य जीतने पर उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

लवलीना बोरगोहाई • एएनआइ

लवलीना इतिहास रचने से चूकीं: मुक्केबाज लवलीना के पास अपने पहले ही ओलिंपिक में फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने का मौका था, लेकिन चूक गईं। 69 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा।

जागरण विशेष

चादर पर उकेर दी श्रीनगर की मुकम्मल तस्वीर

श्रीनगर: क्या आपने किसी को कपड़े की चादर पर रंगों से वर्तमान और इतिहास उकेरते देखा है। कश्मीर के एक दस्तकार ने यह कर दिखाया है। उसने चादर पर रंगों से श्रीनगर शहर की मुकम्मल तस्वीर बनाकर सबको चकित कर दिया है। (पेज-6)

केरल में कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं होने से बिगड़े हालात

नई दिल्ली: कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने से केरल में महामारी बेकाबू हुई है। केंद्र की ओर से भेजी गई छह सदस्यीय टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। टीम का नेतृत्व नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल के निदेशक डा. एसके सिंह कर रहे थे। रिपोर्ट ने कोरोना प्रबंधन के कथित केरल माडल की पोल खोल दी है। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के अनुसार केरल में न तो कांट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और न ही संक्रमित व्यक्तियों पर निगरानी की कोई प्रणाली है। केरल के मलप्पुरम जिले, जहां कोरोना के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, में एक संक्रमित व्यक्ति पर औसतन केवल 1.5 व्यक्तियों की कोरोना की जांच की जा रही है। जबकि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की गाइडलाइंस में एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 व्यक्तियों की पहचान कर कोरोना की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। (पेज-5)

स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान

कैबिनेट का फैसला

- अगले पांच साल में करीब तीन लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार
- प्ले स्कूल की तर्ज पर सभी सरकारी विद्यालयों में खुलेंगी बाल वाटिका
- 11.60 लाख सरकारी स्कूल, 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षक होंगे लाभान्वित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले किए। इसके तहत अगले पांच साल में स्कूली शिक्षा पर करीब तीन लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र व राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका खुलेंगी। यहां तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों को खिलौनों पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। वहीं, अगले दो सालों में देश के सभी स्कूलों को डिजिटल बोर्ड सहित दूसरे अत्याधुनिक संसाधनों से भी लैस किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई देने के लिए समग्र शिक्षा योजना को नए स्वरूप में लांच किया गया है। योजना एक अप्रैल, 2021 से लागू मानी जाएगी और 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी।

उन्होंने कहा, योजना के स्वरूप में बदलाव से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आएगा। साथ ही स्कूलों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती दी जाएगी। अब तक योजना के तहत स्कूलों पर सालाना करीब 31 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे, जो रकम बढ़कर अब करीब 40 हजार करोड़ रुपये हो गई है। प्रधान ने कहा, सभी सरकारी स्कूलों में अब बाल वाटिका खुलेंगी। फिलहाल 1.84 लाख स्कूलों से इसकी शुरुआत की जा रही है। बाकी के स्कूलों को आंगनबाड़ी से जोड़ा गया है। देश में करीब 11.60 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की योजना है। स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस फैसले से 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे।

नई दिल्ली में मीडिया को कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रेट्र

फैसले की अहम बातें

- 'समग्र शिक्षा योजना' को पांच साल और जारी रखने पर लगी मुहर
- सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं तक किया जाएगा
- मौजूदा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्ट्रीम के बजाय नए विषय जोड़े जाएंगे

निपुण भारत के नाम से नई योजना

स्कूलों में निपुण भारत नाम से एक नई योजना भी शुरू की जाएगी। इसमें बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में ही अनिवार्य रूप से शब्द और संख्या ज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी। इस योजना के अमेरिका ने भी मदद को लेकर रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत सभी स्कूलों को अगले दो साल में डिजिटल बोर्ड सहित पढ़ाई से जुड़ी दूसरी तकनीक से भी लैस किया जाएगा।

योजना के बदले स्वरूप में और क्या

- दूर-दराज के क्षेत्रों से स्कूल आने वाले बच्चों को सालाना छह हजार रुपये का ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। इसके दायरे में फिलहाल सेकेंडरी तक के बच्चे होंगे, जहां स्कूल नहीं है
- प्रत्येक स्कूली बच्चे को अब साल में 10 दिन का एक इंटर्नशिप कोर्स भी करना होगा। इसमें बच्चे की रुचि के मुताबिक किसी स्किल सेंटर या बढ़ई, पेंटर आदि से रूबरू कराया जाएगा
- रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण में लड़कियों को छठी से सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को हर महीने पांच हजार रुपये दिए जाएंगे
- सभी बालिका छात्रावासों में सैनेटरी पैड वेंडिंग मशीन भी लगाई जाएगी
- राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल में यदि किसी स्कूल के दो बच्चे चयनित होते हैं, तो उससे 25 हजार रुपये ज्यादा वित्तीय मदद दी जाएगी

राज्य फिर कर सकेंगे ओबीसी जातियों की पहचान

नई दिल्ली: ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जातियों की पहचान करने और उसकी सूची बनाने के राज्यों के अधिकार की बहाली का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े विधेयक को मंजूरी दी गई। सरकार ने इसे गुरुवार को ही संसद में पेश करने का संकेत दिया है। माना जा रहा है कि संसद में इसका कोई विरोध नहीं होगा। केंद्र सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया है, जिसमें ओबीसी जातियों की पहचान और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार को अवैध बताया था। (विस्तृत खबर पेज-3 पर)

भ्रष्ट निकाय है नोएडा : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा- प्राधिकरण की आंख, नाक, कान और चेहरे तक से टपकता है भ्रष्टाचार

माला दीक्षित, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा में एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर एपेक्स और सियान के मामले में सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण पर तीखी टिप्पणियां कीं। कहा, नोएडा एक भ्रष्ट निकाय है, इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है। कोर्ट ने इस मामले में नोएडा प्राधिकरण की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने मामले में सुपरटेक और नोएडा प्राधिकरण की अपीलों पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2014 में एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए एपेक्स व सियान टावरों को गलत ठहराते हुए ढहाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने सुपरटेक को फ्लैट बुक कराने वालों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था, साथ ही प्लान सैंक्शन (स्वीकृत) करने के जिम्मेदार नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

इस फैसले को सुपरटेक, नोएडा प्राधिकरण और कुछ फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में एपेक्स व सियान टावर गिराने पर रोक लगा दी थी। साथ ही, सुपरटेक से कहा कि जो लोग पैसा वापस चाहते हैं, उन्हें पैसा लौटाया जाए। कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग कांसट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) से दोनों टावरों पर रिपोर्ट मांगी थी। एनबीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोनों टावरों के बीच नियमानुसार जरूरी फासला नहीं है।

सख्त तेवर

- एमराल्ड कोर्ट के एपेक्स व सियान टावर मामले में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित
- सुपरटेक ने कराया है निर्माण, हाई कोर्ट ने दिया था दोनों को गिराने का आदेश

प्राधिकरण के वकील को दिखाया आईना

- आप ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे प्रमोटर हों। आप रेगुलेटिंग अथारिटी हैं, तटस्थ रहें
- आप सुपरटेक की मदद ही नहीं कर रहे, उसके साथ मिले हुए भी हैं
- इमारतों का स्वीकृत प्लान आपने पहले नहीं दिया। बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर दिया

न्यायमित्र ने बताया नियम

सुनवाई में कोर्ट की मदद कर रहे न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने कहा कि फायर सेफ्टी के लिहाज से नियम के मुताबिक, दो इमारतों के बीच दूरी में जो इमारत सबसे ऊंची होगी, उसकी आधी दूरी रहनी चाहिए जैसे कि अगर इमारत 18 मीटर ऊंची है तो दो इमारतों के बीच नौ मीटर की दूरी होनी चाहिए। गौरव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए दो इमारतों के बीच जरूरी दूरी के बारे में व्याख्या करनी चाहिए। रविन्द्र कुमार ने बिल्डिंग सैंक्शन प्लान देने वाले नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने न तो अधिकारियों को पक्षकार बनाया और न ही उनका पक्ष सुना। अधिकारियों ने एनबीसीसी के प्रावधानों की बोनाफाइड व्याख्या की है।

मामले में सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण के वकील रविन्द्र कुमार जब एमराल्ड कोर्ट के एपेक्स व सियान टावर के निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्लान को सही ठहरा रहे थे और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की दलीलों का विरोध कर रहे थे, तभी जस्टिस एमआर शाह ने उनके बहस के तरीके पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह आप फ्लैट मालिकों के खिलाफ केस लड़ रहे हैं वह तरीका उचित नहीं है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले में नोएडा प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि नोएडा का काम हैरान करने वाला है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, जब आपसे रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बिल्डिंग का सैंक्शन प्लान मांगा तो आपने सुपरटेक से पूछा और उसने मना कर दिया तो आपने बिल्डिंग प्लान नहीं दिया। अंत में हाई कोर्ट के आदेश पर आपने हाई कोर्ट में प्लान दिया। आप सुपरटेक की मदद ही नहीं कर रहे, आपकी उसके साथ मिलीभगत है। नोएडा एक भ्रष्ट निकाय है, इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम लोग भी वकील रहे हैं। याचिकाकर्ता, प्रतिवादी और प्राधिकरण सभी की ओर से पेश हुए हैं। सुपरटेक की दलीलें पेज>>2

सीबीआइ के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा पर लटकी कार्रवाई की तलवार

नई दिल्ली: सीबीआइ से जबरन हटाए जाने के ढाई साल बाद पूर्व निदेशक आलोक वर्मा को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने कार्मिक मंत्रालय से वर्मा पर पद के दुरुपयोग व सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई करने को कहा है। (पेज-5)

पत्नी का करें सम्मान, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक पति से कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ सम्मान से पेश आए और अगर वह विफल रहता है, तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। कोर्ट की हिदायत के बाद इस युवा जोड़े के बीच समझौता हो गया। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति उसे प्रताड़ित करता है और उसके साथ कभी सम्मान का व्यवहार नहीं करता। (पेज-5)

दुष्कर्म पीड़िता के स्वजन की फोटो ट्वीट करने पर घिरे राहुल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- एनसीपीसीआर ने कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस व ट्विटर को कार्रवाई का दिया आदेश
- केजरीवाल, वृंदा करात और तृणमूल की महिला नेता पीड़िता के स्वजन से मिलीं

दिल्ली के कैंट इलाके में नौ वर्षीय बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में पीड़िता के माता-पिता की फोटो ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। बुधवार को दिल्ली कैंट की पुराना नांगलराया रोड पर धरने पर बैठे पीड़िता के माता- पिता से राहुल ने मुलाकात की और उनकी फोटो ट्वीट कर दी। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने ट्विटर व दिल्ली पुलिस से राहुल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा, कांग्रेस नेता के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो) और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एनसीपीसीआर कार्रवाई करे।

गाड़ी में राहुल ने की बच्ची के माता-पिता से बात: राहुल गांधी सुबह धरनास्थल पर पहुंचे और विरोध में नारेबाजी शुरू होने पर अपनी गाड़ी में पीड़िता के माता- पिता से बात की। उन्होंने पीड़िता के माता- पिता की फोटो के साथ किए एक ट्वीट में कहा, माता- पिता के आंसू एक ही बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी, इस देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय की इस राह पर उनके साथ हूं।

नई दिल्ली में बुधवार को मृत बच्ची के स्वजन से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाते राहुल गांधी। प्रेट्र

इस बीच, पीड़िता के स्वजन से मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआइ-एम) की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात पहुंचीं। तृणमूल कांग्रेस की महिला नेताओं ने भी पीड़िता के स्वजन से मुलाकात की। पार्टी के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में इस मामले को उठाया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। वहीं, दिल्ली पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। जबकि दिल्ली सरकार ने कहा कि वह घटना की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देगी। दिल्ली महिला आयोग ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है।

बता दें, दिल्ली के कैंट क्षेत्र में एक श्मशान गृह के सामने रहने वाली नौ साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म व हत्या की घटना रविवार को सामने आई थी। मामले में चार लोग गिरफ्तार हैं।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग हुआ सख्त पेज>>2

पेगासस पर जंग तेज, रास में टीएमसी के छह सांसद निलंबित

संसद में संग्राम

- विपक्ष के 18 नेताओं ने गतिरोध के लिए सरकार के अहंकार को ठहराया जिम्मेदार
- दोनों सदनों में घमासान के बीच लोकसभा में दो व राज्यसभा में एक विधेयक पारित

पेगासस जासूसी कांड समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर बुधवार को भी राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विपक्षी दलों की एकजुटता ने संसद में पेगासस जासूसी कांड पर छिड़े सियासी संग्राम की आक्रामकता बढ़ा दी है। बहस की मांग ठुकरा कर सरकार के लगातार दोनों सदनों में बिल पारित कराने के रुख का विरोध करने के लिए विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में हंगामे और नारेबाजी तेज कर दी है। इस बीच राज्यसभा में छह विपक्षी सांसदों को निलंबित भी किया गया।

संसद में लगातार बढ़ रहे घमासान के लिए विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में सरकार के अहंकार को मौजूदा गतिरोध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सरकार से संसद में पेगासस और कृषि कानूनों पर बहस की मांग स्वीकार करने का आग्रह किया है।

पेगासस पर जारी गतिरोध का हल निकलने की धूमिल पड़ चुकी उम्मीद को देखते हुए सरकार दोनों सदनों में हंगामे के बीच पिछले दिनों सात आठ विधेयक पारित करा चुकी है। इससे विपक्षी दलों को बेचैन कर दिया है। इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में विपक्ष के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं।

राज्यसभा में जमकर नारेबाजी : राज्यसभा में बुधवार को पेगासस मामले पर विपक्षी सदस्य वेल में जाकर नारेबाजी कर रहे थे। सभापति ने आसन के सामने तख्तियां और पोस्टर लिए विपक्ष के सदस्यों को अपनी सीट पर जाने का निर्देश दिया। लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इसे अनसुना कर दिया। तब नायडू ने पहले चेतावनी देने के बाद नियम 255 के तहत तृणमूल कांग्रेस के छह सांसदों डोला सेन, अर्पिता घोष, नदीम उल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांति छेत्री और मौसम नूर को सदन की बाकी बची कार्यवाही से निलंबित कर दिया।

सभापति ने इन सदस्यों का सदन में नाम नहीं लिया मगर राज्यसभा सचिवालय ने सदन स्थगित होने के बाद पोस्टर-बैनर दिखाने वाले सदस्यों की पहचान कर उनके दिन भर के निलंबन की सूचना जारी कर दी। दोनों सदनों में दिन भर हंगामा और नारेबाजी होती रही। बार-बार स्थगन के बीच सरकार ने लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक विधेयक को अव्यवस्था की स्थिति में भी पारित कराया और फिर कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।

विपक्ष ने जारी किया संयुक्त बयान : विपक्षी दलों ने संसद के भीतर अपना एतराज जाहिर करने के बाद एक संयुक्त बयान जारी कर सरकार पर हमला बोला। इसमें कहा गया कि विपक्षी दल पेगासस जासूसी कांड पर दोनों सदनों में बहस की मांग और गृहमंत्री से जवाब की अपनी मांग पर एकजुट हैं। विपक्षी दल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन और महंगाई पर भी बहस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विपक्षी दलों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सरकार दुष्प्रचार अभियान चलाते हुए संसद के गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। जबकि असल में इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। (पेज 3 भी देखें)

गौरव

पांच अगस्त : राम मंदिर भूमि पूजन के एक साल, भव्य राम मंदिर-दिव्य अयोध्या का साकार हो रहा स्वप्न, बदलाव के विशद उपक्रम रामनगरी में ले रहे आकार

स्वर्णिम संभावनाओं के शिखर की ओर रामनगरी

श्रीराम

रघुवरशरण, अयोध्या

सदियों के सफर के बाद गुजरा साल रामनगरी के इतिहास का स्वर्णिम वर्ष बनकर बीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल पांच अगस्त को राममंदिर का भूमिपूजन होने के साथ यहां बदलाव के विशद उपक्रम आकार लेने लगे हैं। साथ ही कलेवर बदल रही रामनगरी में भव्य राम मंदिर व दिव्य अयोध्या का स्वप्न तेजी से साकार हो रहा है। इन प्रयासों के बीच अवधपुरी गौरवमयी अतीत के अनुरूप संभावनाओं के शिखर की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होती नजर आ रही है। रामलला के दर्शन मार्ग और वैकल्पिक गर्भगृह को छोड़ कर करीब 70 एकड़ के जिस परिसर में जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां तक आम श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति भले ही न हो, लेकिन तमाम नए प्रकल्प भविष्य की रामनगरी की झलक देते हैं।

केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों ने इसे दुनिया की शीर्ष सांस्कृतिक व पर्यटन नगरी के रूप में आगे बढ़ाया है। दशकों तक उपेक्षित रही राम की पैड़ी यहां अब सदानीरा के जल से हर वक्त जीवंत उत्सव स्थली में बदल चुकी है। सौ करोड़ से अधिक की लागत से न सिर्फ पैड़ी जीवंत है, बल्कि सरयू की ओर कुछ कदम आगे बढ़ते ही दाहिनी ओर 20 करोड़ की लागत से तैयार भजन संध्या स्थल भी रोमांचित कर रहा है। कुछ ही फासले पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में रानी हो के स्मारक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नगरी के नुक्कड़ नयाघाट बंधा तिराहा से भी संभावनाएं प्रशस्त होती हैं। लखनऊ-गोरखपुर फोरलेन से नगरी को जोड़ने वाला पांच सौ मीटर लंबा संपर्क मार्ग भी फोरलेन का बनाया जा चुका है। एक किलोमीटर फैजाबाद की ओर बढ़ने पर बायीं तरफ नया बस स्टेशन भी तैयार दिखता है। नगरी को आधुनिकतम रूप देने को ऐसे तमाम प्रकल्प तेजी से यहां आकार ले रहे हैं, तो वहीं रामघाट स्थित राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में तराश कर रखी गई शिलाओं में श्रद्धालु त्रेतायुगीन वैभव की झलक निहार रहे हैं। इन्हीं में आध्यात्मिक गुरु जय सिंह चौहान भी हैं। वह कहते हैं-'इन शिलाओं का इंतजार थमने को है। यह अवसर स्वर्णिम संभावनाओं का स्वप्न देखने के साथ अपने पीछे की जमीन भी आंख में भर लेने का है।'

अयोध्या-फैजाबाद मुख्य मार्ग से लगी परिसर की सीमा पर पूरे दिन दर्जनों लोडर मंदिर निर्माण की सामग्री लिए खड़े दिखते हैं। इन्हें देखकर मंदिर निर्माण से जुड़ी व्यापक और युद्धस्तर की गतिविधियों का अनुमान सहज ही लग जाता है। परिसर के गेट से कोई तीन सौ मीटर आगे बढ़ने पर हनुमानगढ़ी चौराहा है। श्रद्धालुओं के दबाव के आगे यह चौराहा बहुत छोटा प्रतीत होता है, पर यह अधिक दिनों तक यूं ही नहीं रहने वाला है। प्रशासन ने इस चौराहे को पार करती सड़कों को लगभग दो गुना बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। तब यह चौराहा भी आठ गुना अधिक चौड़ा हो उठेगा। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस विकास रथ के सारथी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वह गुरुवार को भी अयोध्या में होंगे। यह नगर उनकी कितनी प्राथमिकता में है, इसे इससे ही समझा जा सकता है कि पिछले पचास माह में यह उनका 29वां दौरा होगा।

- 70 एकड़ का है रामजन्मभूमि का कुल परिसर
- 5 एकड़ में होगा राम मंदिर का मुख्य परिसर
- 65 एकड़ में सांस्कृतिक नगरी का होगा निर्माण

अयोध्या में राम की पैड़ी रामनगरी की दिव्यता और भव्यता का आभास कराती नजर आती है। जागरण

5337 बच्चों के सिर से दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान माता या पिता या दोनों का साया छिन गया। यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता प्रभसहाय कौर ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 5 अगस्त, 2021

न्यूज गैलरी

दिल्ली में घटी कोरोना जांच की कीमतें

नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना की जांच कराने के लिए अब कम पैसे देने पड़ेंगे। सरकार ने जांच की कीमत में बदलाव किया है। अब निजी लैब में एंटीजन जांच कराने पर 300 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं, आरटीपीसीआर जांच के लिए लैब में जाकर सैंपल देने पर 500 और घर से सैंपल संग्रह कराने पर 700 रुपये देने होंगे। इससे पहले एंटीजन जांच के लिए 400, आरटीपीसीआर के लिए 800 और घर से सैंपल संग्रह कराने पर 1200 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। (जासं)

हिसार के लिए चलेगी अनारक्षित ट्रेन

नई दिल्ली : दिल्ली से हिसार, भिवानी जाने वाले यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए उत्तर रेलवे ने पुरानी दिल्ली-हिसार विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित होगी। पुरानी दिल्ली से यह विशेष ट्रेन सात अगस्त से प्रतिदिन शाम पांच बजे रवाना होगी। रात 10:40 बजे हिसार पहुंचेगी। हिसार से आगे के स्टेशनों पर भी यह ट्रेन जाएगी। वापसी में आठ अगस्त से प्रतिदिन सुबह सवा पांच बजे हिसार से रवाना होकर यह सुबह सवा दस बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। (राब्यू)

डीयू में 65 हजार स्नातक सीटों के लिए 89 हजार पंजीकरण

नई दिल्ली : डीयू स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने के तीसरे ही दिन पंजीकरण का आंकड़ा 89 हजार पहुंच गया। गुरुवार शाम सवा पांच बजे तक 89 हजार से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया। दूसरे दिन तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 65 हजार छात्रों ने पंजीकरण किया था। डीयू में इस बार स्नातक की 65 हजार सीटों के लिए दाखिले होंगे। वहीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 81 हजार 610 छात्रों ने पंजीकरण किया। एमफिल-पीएचडी के लिए 11 हजार 665 पंजीकरण हो चुके हैं। (जासं)

दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए आनलाइन चंदा

नई दिल्ली: दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए आनलाइन प्लेटफार्म शुरू किया गया है और कई बड़ी कंपनियों से बच्चों के इलाज के लिए चंदा देने का आग्रह भी किया गया है। हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष हलफनामा दायर कर यह जानकारी केंद्र सरकार ने दी। केंद्र सरकार ने पीठ को बताया कि <e>http//rarediseases.aardeesoft.com इस लिंक पर चंदा दिया जा सकेगा। पीठ ने लिंक का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया, ताकि लोग अपना सहयोग दे सकें। (जासं)

बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की होगी मजिस्ट्रेटी जांच : केजरीवाल

घोषणा ▶ मुख्यमंत्री ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, 10 लाख की आर्थिक मदद देगी सरकार

कहा– कानून व्यवस्था ठीक करने की जरूरत, केंद्र उठाए ठोस कदम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अनुसूचित जाति की नौ वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। पीड़ित परिवार को सरकार 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार वकील का भी प्रबंध करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए। दिल्ली सरकार इस कार्य में पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो इससे पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होती है।

बुधवार को जब केजरीवाल दिल्ली कैंट पहुंचे तब तक उनसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जा चुके थे। लोगों द्वारा इन दोनों नेताओं के विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सिविल डिफेंस कर्मियों ने एक बड़ा घेरा बनाया हुआ था, ताकि मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कमान संभाली हुई थी। मंच पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बात की। मुख्यमंत्री के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

दुष्कर्म व हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पुराना नांगलराया पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जागरण

आरोपितों का नार्को टेस्ट करा सकती है पुलिस : श्मशान भूमि से जो भी अवशेष मिले थे, उन्हें पुलिस ने डीडीयू मोर्चरी भेजा है। इन अवशेषों का पोस्टमार्टम किया गया। सूत्रों का कहना है कि चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को मोटे तौर पर अपनी राय बताई है। अभी इस मामले में अंतिम नतीजे तक पहुंचने के लिए पुलिस विशेषज्ञों से एक बार और राय लेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह भी पता चल सकेगा कि बच्ची को जब जलाया गया तब वह जीवित थी या नहीं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में पुलिस आरोपितों का नार्को टेस्ट करा सकती है। पालीग्राफ टेस्ट का भी उसके पास विकल्प है।

दरिंदगी के खिलाफ लोगों में बढ़ रहा रोष

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कैंट इलाके में नौ वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली कैंट से सागरपुर की ओर जाने वाली पुराना नांगलराया रोड पर यातायात पूरी तरह बाधित है। मुख्य सड़क धरनास्थल में तब्दील हो गई है। यहां पर इकट्ठा लोग दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग पर अड़े हैं। इस जघन्य घटना के प्रति रोष जाहिर करने वालों का आक्रोश तब और बढ़ जाता है, जब कोई नेता बीच सड़क पर बने धरनास्थल पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचता है।

आदेश गुप्ता बोले- मामले की जांच 15 दिनों के भीतर पूरी हो : आदेश गुप्ता ने नारेबाजी के बीच मंच पर पीड़ित परिवार से बात की। इसके बाद वे मंच के सामने जमीन पर बैठ गए। यहां वे करीब आधे घंटे तक रहे और लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच 15 दिनों के भीतर पूरी हो और दोषियों को सख्त सजा मिले।

आक्सीजन बफर स्टाक पर हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कहा, बफर स्टाक एक या दो सप्ताह में नहीं बनाया जा सकता
- कोरोना महामारी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में लिक्विड मेडिकल आक्सीजन (एलएमओ) का बफर स्टाक बढ़ाने के संबंध में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली में आक्सीजन भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए बफर स्टाक बनाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल स्थिति सामान्य दिखाई दे रही हो रही, लेकिन अप्रैल-मई माह में क्या हुआ हमने देखा है। पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट पेश करने को कहा।

अधिवक्ता राकेश मल्होत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि बफर स्टाक बनाने से बच नहीं सकते, यह महामारी की स्थिति बढ़ने पर एक तरह का बीमा है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि बफर स्टाक बनाने की जरूरत नहीं है या फिर यह काम दिल्ली सरकार का है तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करना चाहिए, जिसने उन्हें बफर स्टाक बनाने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा कि 30 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार को एलएमओ का बफर स्टाक बनाने को कहा था।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह ने कहा कि बफर स्टाक के लिए दिल्ली सरकार ने पर्याप्त काम किया है। उन्होंने बताया कि देशभर में क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या को 1040 से बढ़ाकर 1700 किया गया है और दिल्ली के लिए 26 टैंकर की व्यवस्था की गई है। वहीं, आक्सीजन रिफिलिंग की क्षमता को 187 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 224 मीट्रिक टन किया गया है। वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न स्थानों पर एलएमओ का 420 मीट्रिक टन बफर स्टाक का इंतजाम किया है।

इसके अलावा अस्पताल के पास 724 मीट्रिक टन आक्सीजन भंडारण की क्षमता है। पीठ ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 23 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

राज्य सरकार अब सीधे निर्माताओं से खरीद सकेगी फंगस की दवा

सुनवाई के दौरान फंगस की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंफोटेरिसिन-बी की दवा के संबंध में केंद्र सरकार के अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह ने पीठ को बताया कि इसके आंवटन की केंद्रीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। अब राज्य सरकारें निर्माता कंपनियों से सीधे फंगस की दवा हासिल कर सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फंगस मरीजों की संख्या 27 जून को 28,475 थी, जो कि 30 जुलाई 18,833 रह गई है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग हुआ सख्त

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रेट्र के अनुसार, एनसीपीसीआर ने पीड़िता के स्वजन की पहचान उजागर करने पर ट्विटर के शिकायत निवारण अधिकारी को पत्र भेजकर राहुल गांधी का ट्वीट डिलीट करने को कहा। आयोग ने कहा कि उसे राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली थी और ट्विटर तीन दिन के भीतर उसे एक्शन टेकेन रिपोर्ट भेजे। फोटो में पीड़िता के माता- पिता की पहचान उजागर हो रही है जो पाक्सो एक्ट की धारा 23 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74, भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 228ए और माननीय न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

पात्रा ने गांधी परिवार पर लगाए आरोप: प्रेट्र के अनुसार, संबित पात्रा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। पात्रा ने कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में दलित बच्चियों के साथ अत्याचार का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में दलित बच्चियों के साथ होने वाले अपराध पर आप आंखें बंद कर लेते हो और तभी खोलते हो जब कोई राजनीतिक फायदा दिखता है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में दलित की बेटियां देश की बेटियां नहीं हैं। देश में दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले राजस्थान में हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी से सवाल किया कि राजस्थान कब आएंगे। वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में अपराध पर कांग्रेस नेता क्यों चुप रहते हैं।

नई दिल्ली में बुधवार को प्रेसवार्ता को संबोधित करते भाजपा नेता संबित पात्रा। एनआइ

दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के दो अंशकालिक सदस्यों ने की 'अवैध नियुक्ति'

जागरण विशेष

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

- आयोग के चेयरमैन ने दोनों को हटाने व केस दर्ज कराने को लिखा पत्र
- वेतन-भत्ते का लालच देकर नियुक्त किए गए लोगों से काफी पैसे वसूलने का भी लगाया गया दोनों पर आरोप

दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के दो अंशकालिक सदस्यों पर पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत ने एक लिखित शिकायत में लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आयोग के सदस्य रवि शंकर और अनीता उज्जैनवाल ने 100 लोगों की आयोग की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नियुक्ति की है, जो नियमों के विरुद्ध है।

अपनी शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सदस्यों ने नियुक्त किए गए इन लोगों को वेतन-भत्ते का लालच देकर काफी पैसे भी वसूले हैं। गहलोत ने दोनों सदस्यों को हटाने और इनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए भी लिखा है। शिकायत मिलने पर आयोग के सचिव एवी प्रेमनाथ ने दोनों सदस्यों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। इस मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को फोन कर और वाट्सएप मैसेज भेजकर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका कोई पक्ष नहीं मिला।

आप सरकार ने करीब साढ़े तीन साल पहले रवि शंकर और अनीता उज्जैनवाल को अंशकालिक सदस्य के तौर पर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में नियुक्त किया था। गत दिनों जब आयोग के चेयरमैन का पद रिक्त था, उस दौरान उक्त दोनों सदस्यों ने आयोग की सलाहकार समिति में सदस्यों की नियुक्ति की। गहलोत ने जब विगत जून माह में फिर से चेयरमैन का पद संभाला तो उन्होंने दोनों सदस्यों के खिलाफ आयोग के सचिव को शिकायत दी। इस शिकायत के आधार पर आयोग के उपसचिव डीके सैनी ने फाइल तैयार कर आगे बढ़ाई है और दोनों सदस्यों से जवाब भी मांगा गया है।

> आरोप निराधार हैं। आयोग की बेहतरी के लिए लोगों को आयोग की सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है। मेरे पास इन्हें लगाने का अधिकार है। जो लोग लगाए गए हैं, उन्हें कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा।
> -रवि शंकर, अंशकालिक सदस्य, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग

> कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं किया है। आयोग के प्रविधान के तहत ही लोगों की नियुक्ति की गई है। आयोग के चेयरमैन जो आरोप लगा रहे हैं वह सरासर गलत है।
> -अनीता उज्जैनवाल, अंशकालिक सदस्य, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग

आवश्यक विषयों संबंधी फाइल पर एलजी की अनुमति जरूरी : देव

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली : मुख्य सचिव विजय देव ने सभी अतिरिक्त मुख्य व विभागीय सचिवों को आदेश जारी किया है कि जिन विषयों में उपराज्यपाल (एलजी) की अनुमति आवश्यक है, उन सभी फाइलों पर विषय को चिह्नित कर एलजी की अनुमति के लिए अवश्य भेजें।

मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि उपराज्यपाल कार्यालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। उसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार अगर कोई बोर्ड, कमेटी या कमीशन बनाती है या फिर कोई नियुक्ति की जाती है तो इसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसी प्रकार दिल्ली सरकार से संबंधित कोई नया नियम, रेगुलेशन, स्कीम आदि बनानी है तो एलजी की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा।

इसी तरह दिल्ली फाइनेंस कमीशन से संबंधित विषयों पर, जेल से पैरोल देने के पूर्व एलजी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। कैबिनेट द्वारा निर्णय लेने या मंत्री द्वारा निर्णय लेने के बाद आदेश जारी करने के पहले एलजी की अनुमति लेनी होगी।

सुपरटेक की दलीलें

प्रथम पृष्ठ से आगे

सुपरटेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि सुपरटेक ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। एपेक्स व सियान टावर का पूरा प्रोजेक्ट अलग है और एमराल्ड कोर्ट के टावर एक में रह रहे लोगों का प्रोजेक्ट प्लान अलग है। उन लोगों के ग्रीन एरिया को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि नियम के मुताबिक जितना ग्रीन एरिया छोड़ा जाना था उससे ज्यादा सेंट्रल पार्क में छोड़ा गया है। उसके पास फायर की एनओसी भी है।

क्या है मौजूदा स्थिति : सुपरटेक ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि एपेक्स व सियान टावर में कुल 915 फ्लैट और 21 दुकानें हैं। इसमें शुरू में 633 लोगों ने बुकिंग कराई थी, जिसमे से 248 लोगों ने पैसा वापस ले लिया है। 133 लोगों ने सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया है और 252 लोग अभी बचे हैं जिन्होंने पैसा वापस नहीं लिया है। सुपरटेक को दोनों टावरों से करीब 188 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से उसने 148 करोड़ रुपये वापस कर दिये हैं।

हरियाणा सरकार ने वन क्षेत्र संशोधन कानून रोका, अवैध निर्माण नहीं

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

- संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश से एक मार्च, 2019 को ही लगा दी थी रोक

हरियाणा सरकार ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट (पीएलपीए) 1900 की धारा चार व पांच में अधिसूचित वन क्षेत्र में संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद एक मार्च, 2019 से ही रोका हुआ है। इसकी सूचना वन विभाग की वेबसाइट पर अंकित है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी वन क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण व अवैध निर्माण नहीं रोक पाए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगे लाकडाउन के दौरान अरावली के वन क्षेत्र में खूब अतिक्रमण और अवैध निर्माण हुए। वन क्षेत्र की सरकारी भूमि पर बसी खोरी गांव बस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिनके कार्यकाल में अतिक्रमण या अवैध निर्माण हुए। प्रशासन मानता है कि वन क्षेत्र की भूमि पर सिर्फ तीन ही ऐसे संस्थान हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने गैर वानिक कार्यों के लिए अनुमति दी है। बाकी सूरजकुंड से बड़खल और फरीदाबाद से गुरुग्राम तक अरावली के वन क्षेत्र बने निर्माणों को लेकर निजी व सरकारी एजेंसियों को अब अपने पक्ष में शुक्रवार तक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। फरीदाबाद-गुरुग्राम में ऐसे 450 अवैध निर्माण हैं।

बेहतर रोड कनेक्टिविटी ने किया फार्म हाउस मालिकों को आकर्षित : फरीदाबाद-गुरुग्राम और बड़खल-सूरजकुंड मार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी के बाद इन दोनों मार्गों पर पिछले 20 सालों में लगातार अवैध निर्माण होते रहे। कभी कोई सख्त अधिकारी आया या फिर शासनाध्यक्ष के सख्त आदेश आए तो नाममात्र के लिए तोड़फोड़ अवश्य की पर ऐसे प्रविधान नहीं हुए कि अवैध निर्माण रुक जाएं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद खोरी जैसी बड़ी बस्ती पर कार्रवाई लगभग पूरी हो गई।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रविधान : प्रतिबंधित वन क्षेत्र की परिभाषा पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट (पीएलपीए) 1900 की धारा चार व पांच में अधिसूचित है। इनकी अनुपालना के लिए 25 अक्टूबर, 1980 से लागू वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-दो में साफ तौर पर लिखा है कि वनों के संरक्षण और वन भूमि को वन योग्य बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

'घोटालों के कारण आर्थिक संकट में है देश'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सख्त टिप्पणी

- फ्लैट न देने के आरोपित निदेशकों को जमानत देने से इन्कार
- आरोपितों ने देशभर में 126 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की

करोड़ों रुपये लेने के बाद भी फ्लैट नहीं देने के आरोपित रियल एस्टेट कंपनी के दो निदेशकों को तीस हजारी कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कहा कि सुशांत मुतरेजा व निशांत मुतरेजा के आर्थिक अपराधों को गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि कई घोटालों के कारण देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।

जमानत याचिका खारिज करते हुए जज ने कहा कि अगर ऐसे अपराधों के आरोपितों पर रहम किया गया तो न्यायिक संस्थाओं से लोगों का विश्वास हिल जाएगा। यदि राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले आर्थिक अपराधियों को सजा नहीं दिलाई जाती है, तो पूरा समुदाय व्यथित होता है। उन्होंने कहा कि इन दोनों आरोपितों ने कथित तौर पर 893 पीड़ितों से देशभर में 126 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। इन्होंने न तो निवेशकों को समय पर फ्लैट दिया और न ही उनसे लिए गए रुपये लौटाए। अदालत ने रिकार्ड पर लिया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ निवेशकों की तरफ से कई एफआइआर दर्ज कराई गई थी और उन्हें 2016 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि सुशांत मुतरेजा को 2017 में प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए जमानत दी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका था। पुलिस के अनुसार दोनों निवेशकों ने लोगों से जुटाए गए करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल गाजियाबाद और उत्तराखंड में सब्सिडरी कंपनी के नाम से संपत्ति खरीदने में किया था। इतना ही नहीं, दोनों निदेशकों ने प्रोजेक्ट पर काम करने का कभी प्रयास ही नहीं किया और न ही भूमि उनकी थी।

दूसरी तरफ, आरोपित निदेशकों की तरफ से दलील दी गई कि उनका इरादा किसी को धोखा देने या प्रोजेक्ट में देर करने का नहीं था। वे हमेशा प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते थे, लेकिन बाजार की खराब स्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सके।

प्रतिबद्धता

वायु प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम के उपाय करने के लिए तंत्र बनाने में होगी सहूलियत

दिल्ली और आस-पास की हवा दुरुस्त करने के लिए बिल पास

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा ने बुधवार को शोर-शराबे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं को लेकर बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग गठित करने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध किया गया है।

वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निराकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारणों में यातायात, औद्योगिक प्रदूषण और जैविक कचरे को जलाना आदि शामिल हैं। यादव ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए एक समेकित संस्था जरूरी थी। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

लोकसभा से बिल को मिली मंजूरी। फाइल फोटो

उन्होंने कहा कि इसमें पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही एनसीआर के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है। पेगासस जासूसी मामले पर सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पर्यावरण मंत्री ने सदन से इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने की अपील की।

सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और रिवल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन के कुछ संशोधनों को अस्वीकृत करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक, 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। यह विधेयक इससे संबंधित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2021' का स्थान लेगा।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता चिंता का मुख्य कारण बनी हुई है। वायु प्रदूषण के कारणों की निगरानी करने, उनका समाधान, उन्मूलन तथा वायु प्रदूषण को कम करने संबंधी उपायों की पहचान करने के लिए समेकित दृष्टिकोण विकसित एवं कार्यान्वित करने की जरूरत है। इसमें खेत में फसल कटने के बाद ठूंठ या पराली जलाने, यातायात प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, सड़क की धूल, जैव सामग्री जलाना जैसे विषय शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोगी एवं भागीदारीपूर्ण स्थायी और समर्पित तंत्र की कमी है। ऐसे में वायु प्रदूषण से निपटने और स्थायी समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग स्थापित करना जरूरी समझा गया।

विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि चूंकि संसद सत्र नहीं था और ऐसे विधान की तत्काल जरूरत थी, ऐसे में 28 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश लाया गया। लेकिन उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापित करने के लिए संसद में पेश नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप इसकी मियाद 12 मार्च 2021 को समाप्त हो गई।

इसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 खंड 1 के तहत 13 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

उल्लेखनीय है सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अवसरों पर वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए अभिनव उपायों एवं अनुसंधान में सुधार की बात कही है।

घर जलाने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों पर तय किए आरोप

दिल्ली दंगा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली दंगे के दौरान गोकलपुरी इलाके में चोरी करने के बाद घर जलाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने कहा कि आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। वहीं आरोपितों ने खुद को बेकसूर बताते हुए ट्रायल की मांग की है।

गत वर्ष फरवरी में गोकलपुरी इलाके के भागीरथी विहार मुख्य नाला रोड स्थित सी-ब्लाक में दंगाइयों ने अफजाल सैफी के घर चोरी करने के बाद तोड़फोड़ की थी। उसके बाद दंगाइयों ने उनके घर में आग लगा दी थी। इसमें उनकी मोटरसाइकिल भी जल गई थी। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने आरोपित दिनेश यादव उर्फ माइकल, साहिल उर्फ बाबू और संदीप उर्फ मोगली पर गैर कानूनी समूह बनाने, उपद्रव करने, घातक हथियारों का उपयोग करने, चोरी करने, सरकारी आदेशों का उल्लंघन और आगजनी करने का आरोप तय किया है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमति न होने के कारण आरोपितों को सौहार्द बिगाड़ने का आरोपित नहीं माना है।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच एजेंसी ने मुकदमा दर्ज करने में देरी की। जो वीडियो इस केस में दिखाया गया, वह दूसरे मुकदमे से जुड़ा है। उन्होंने पुलिस के गवाहों पर संदेह जताते हुए कहा कि दोनों कांस्टेबलों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को काल करके नहीं दी थी।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने वीडियो क्लिप को आधार बनाते हुए दंगे में आरोपितों की सक्रियता पर जोर दिया। दोनों की दलील पर कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर पुलिस के गवाहों के बयानों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

2018 से लेकर अब तक पीएम सम्मान निधि के तहत राजस्थान में 73.07 लाख किसानों का चयन किया गया। योजना में जुलाई तक 9,135.9 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए।

राज्य फिर कर सकेंगे ओबीसी जातियों की पहचान

अहम फैसला ▸ कैबिनेट ने इससे जुड़े विधेयक को दी मंजूरी, आज संसद में पेश किया जा सकता है विधेयक

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी जातियों की पहचान और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार को बताया है अवैध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जातियों की पहचान करने और उसकी सूची बनाने के राज्यों के अधिकार की बहाली का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े विधेयक को मंजूरी दी गई। सरकार ने इसे गुरुवार को ही संसद में पेश करने का संकेत दिया है। माना जा रहा है कि संसद में इसका कोई विरोध नहीं होगा।

केंद्र सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया है, जिसमें ओबीसी जातियों की पहचान और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार को अवैध बताया था। कोर्ट का कहना था कि 102 वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ों की पहचान करने और अलग से सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ केंद्र ही ऐसी सूची बना सकता है।

कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में खड़ा हो गया था एक नया विवाद

खास बात यह है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में एक नया विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि मौजूदा समय में केंद्र और राज्य की ओबीसी की अलग-अलग सूची है। राज्यों की ओबीसी सूची में कई ऐसी जातियों को रखा गया है, जो केंद्रीय सूची में नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय सूची में शामिल न होने वाली ओबीसी जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हो गई थीं। इसे लेकर राज्यों में काफी राजनीतिक गर्म है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार से संसद के जरिये राज्यों के अधिकार को बहाल करने का रास्ता चुना है।

चलती रहेंगी 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक अदालतों को दो वर्ष तक जारी रखने को दी मंजूरी

▸ केंद्रीय हिस्से की राशि निर्भया फंड से दी जाएगी

त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा रहीं विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें चलती रहेंगी। केंद्र सरकार ने 389 विशेष पाक्सो अदालतों सहित कुल 1023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की केंद्र प्रायोजित योजना को दो वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। योजना पर कुल 1572.86 करोड़ का खर्च आएगा। केंद्र के हिस्से की राशि निर्भया फंड से दी जाएगी। यह योजना दो अक्टूबर, 2019 को शुरू हुई थी। यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक अदालतें अहम भूमिका निभा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र प्रायोजित 1023 फास्ट ट्रैक अदालतों को 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। इसके लिए कुल 1572.86 करोड़ की राशि तय की गई है, जिसमें केंद्र के हिस्से में 971.70 करोड़ और राज्य के हिस्से में 601.16 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

1023 फास्ट ट्रैक अदालतों में 389 विशेष पास्को अदालतें चल रही हैं। फास्ट ट्रैक अदालतों के फैसला देने की दर नियमित अदालतों की तुलना में बेहतर है। अभी ये अदालतें 28 राज्यों में चल रही हैं। सभी 31 राज्यों में इस योजना का विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

पांच वर्ष के दौरान देश में दुष्कर्म के 1.71 लाख मामले दर्ज हुए

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में 2015 एवं 2019 के बीच दुष्कर्म के करीब 1.71 लाख मामले दर्ज हुए। घृणित अपराध के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश से और इसके बाद राजस्थान से सामने आए। सरकार ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी।

राज्यसभा में एक सवाल का लिखित उत्तर देते हुए गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2015 एवं 2019 के बीच दुष्कर्म के कुल 22,753 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान में 20,937, उत्तर प्रदेश में 19,098 और महाराष्ट्र में 14,707 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में इस अवधि में कुल 8,051 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए।

राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि देश भर में वर्ष 2015 में कुल 34,651, 2016 में 38,947, 2017 में 32,559, 2018 में 33,356 और वर्ष 2019 में 32,033 मामले दर्ज किए गए।

कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में कांग्रेस सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू (बाएं) और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। प्रेट्र

रवनीत और हरसिमरत के बीच तीखी बहस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : कृषि सुधार कानूनों को लेकर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और अकाली नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के बीच संसद भवन के सामने तीखी बहस हुई। दोनों ने जमकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।

बुधवार को कृषि बिलों को लेकर हरसिमरत संसद के बाहर नारेबाजी कर रही थीं तभी रवनीत बिट्टू वहां पहुंच गए। बिट्टू ने कहा कि वह (हरसिमरत) ड्रामेबाजी कर रही हैं। जिस कैबिनेट में यह बिल पास हुआ, उसमें वह बतौर मंत्री मौजूद थीं। कांग्रेस सांसद की टिप्पणी पर हरसिमरत भड़क गईं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जिस समय संसद में कृषि बिल पास हो रहे थे, राहुल गांधी कहां थे।

कृषि कानून को लेकर दो दलों के नेताओं के आमने-सामने होने की यह पहली घटना है। इससे पहले सभी दल अपने-अपने स्तर पर ही बयानबाजी कर रहे थे। जून, 2020 में जब कृषि बिल अस्तित्व में आया था उस समय पंजाब में कांग्रेस ने सबसे पहले इसका विरोध किया था।

दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के नियमों के पालन पर भारत का जोर

▸ विदेश मंत्री जयशंकर ने म्यांमार पर आसियान के कदमों को सराहा

▸ हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में संपर्क का मार्ग बनाए रखने पर दिया जोर

नई दिल्ली में बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 11वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लिया। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत ने रुख स्पष्ट किया है। कहा है कि वहां पर संयुक्त राष्ट्र के समझौतों और नियमों का पालन होना चाहिए। इस समुद्री क्षेत्र को लेकर जो बातचीत हो वह सारे दुराग्रहों को छोड़ते हुए संबद्ध पक्षों के बीच हो।

यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व एशिया सम्मेलन (ईएएस) में अपने वर्चुअल उद्बोधन में कही। इस दौरान उन्होंने हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में संपर्क का मार्ग बनाए रखने पर जोर दिया। इससे अलग जयशंकर ने आसियान-भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में संपर्क और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अच्छे समझौतों के तहत आपसी व्यापार पर जोर दिया, जिसमें संबद्ध पक्षों को लाभ हो सके। ईएएस में विदेश मंत्री ने कहा, दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करते हुए सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। विदित हो कि इस समुद्री क्षेत्र को चीन अपना हिस्सा बताते हुए उस पर कब्जा करने में लगा है। वहां पर चीन ने कई कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं और नौसेना व वायुसेना तैनात कर दी है। चीन प्राकृतिक गैस और तेल भंडार की प्रचुरता वाले इस समुद्री क्षेत्र पर वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनेई और मलेशिया के अधिकार को पूरी तरह से नकारता है। चीन वहां से मालवाही जहाजों के आवागमन पर भी आपत्ति जताता है। इसी मार्ग से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जुड़ते हैं और हजारों करोड़ रुपये का माल आता-जाता है। भारत इस समुद्री क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के समुद्र संबंधी नियमों के तहत आवागमन चाहता है। ईएएस में जयशंकर ने आसियान के म्यांमार के संबंध में पांच बिंदुओं वाली समाधान योजना का स्वागत किया और उसके समर्थन का एलान किया। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के समूह द्वारा म्यांमार के लिए विशेष दूत की नियुक्ति का भी समर्थन किया। भारतीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले में भारत के पूरे सहयोग का भी आश्वासन दिया। उन्होंने ट्राईलेटूल हाईवे और कालादान प्रोजेक्ट की गति बढ़ाने पर भी जोर दिया। ईएएस में दस आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

नागरिकता कानून में किसी और संशोधन का प्रस्ताव नहीं : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत पात्र लाभार्थी, नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद ही नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि नागरिकता कानून में किसी प्रकार के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में राय ने कहा कि पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त नियम अधिसूचित किए जाने के बाद ही नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनसे प्रश्न किया गया था कि क्या सरकार ने सीएए बनने के बाद नागरिकता के लिए नए आवेदन प्राप्त किए हैं? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएए को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ। राय ने कहा कि सीएए के अंतर्गत नियम बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों से नौ जनवरी, 2022 तक का समय विस्तार प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख पंथों से संबंध रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देना है। इस विधेयक के पारित होने के बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे।

नागरिकता के लिए हिंदुओं के 4,046 आवेदन लंबित

नई दिल्ली, प्रेट्र : अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं से भारतीय नागरिकता के लिए कुल 4,046 आवेदन विभिन्न राज्य सरकारों के पास लंबित हैं। राज्यसभा को बुधवार को इसकी जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राय ने एक लिखित उत्तर में कहा कि 2016 से 2020 तक पिछले पांच वर्षों में 4,171 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की नागरिकता के लिए लंबित आवेदनों में से 1,541 राजस्थान सरकार, 849 महाराष्ट्र सरकार, 555 गुजरात, 490 मध्य प्रदेश, 268 छत्तीसगढ़ और 123 दिल्ली सरकार के पास हैं। इसके अलावा, नागरिकता के लिए हिंदुओं के 10 आवेदन केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।

पिछले पांच वर्षों में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वालों का उल्लेख करते हुए, मंत्री ने कहा कि 1,105 विदेशियों को 2016 में भारतीय राष्ट्रीयता दी गई, 2017 में 814, 2018 में 628, 2019 में 986 और 2020 में 638 को भारतीय नागरिकता दी गई। इन लोगों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय राष्ट्रीयता दी गई। अब तक नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत किसी को भी भारतीय नागरिकता नहीं दी गई क्योंकि 2019 के कानून के तहत नियमों को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

राज्यसभा प्रश्नोत्तर

कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनों को लेकर 183 लोग गिरफ्तार किए गए

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने बुधवार को कहा कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 183 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी लोग अभी जमानत पर हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के विरुद्ध दर्ज किसी भी मामले में राजद्रोह या आतंकरोधी कानून के प्रविधानों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। कांग्रेस सदस्य दिग्विजय सिंह के सवाल का लिखित उत्तर देते हुए गृह राज्यमंत्री ने कहा कि मई 2018 से जून 2021 के दौरान जम्मू-कश्मीर में 400 मुठभेड़ों में कुल 630 आतंकी मारे गए। राय ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) कानून (यूएपीए) के तहत 1948 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 34 आरोपितों को दोषी ठहराया गया।

पेगासस मामले की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

▸ विभिन्न लोगों व संगठनों की कुल नौ याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेगासस मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। इनमें एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम व शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ इजराइली फर्म एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस की मदद से सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित लोगों, नेताओं और पत्रकारों की कथित जासूसी की खबरों से जुड़ी नौ अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने एक खबर में दावा किया कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिये जासूसी के संभावित निशाने वाली सूची में 300 भारतीय मोबाइल फोन नंबर शामिल थे। एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि पत्रकारों और अन्य के सर्विलांस की जांच कराने के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया जाए।

गिल्ड ने अपनी अर्जी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे भी याचिकाकर्ता हैं, में कहा है कि उसके सदस्य और सभी पत्रकारों का काम है कि वे सूचना और स्पष्टीकरण मांग कर और राज्य की कामयाबी और नाकामियों का लगातार विश्लेषण कर सरकार के सभी अंगों को जवाबदेह बनाएं।

कोर्ट वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा। उनका नाम उस कथित सूची में शामिल है जिनकी पेगासस की मदद से जासूसी की जा सकती थी। पत्रकार ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि शीर्ष अदालत केंद्र सरकार को जांच से जुड़ी सभी सामग्री सार्वजनिक करने का निर्देश दे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ेगा बेहद प्रतिकूल प्रभाव : ठाकुरता ने अपनी अर्जी में कहा है कि पेगासस की मौजूदगी का भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने कोर्ट से स्पाईवेयर या मालवेयर के उपयोग को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध भी किया है।

पेगासस के दुरुपयोग पर इजरायल में होगी बैठक

यरुशलम, प्रेट्र : इजरायल की शीर्ष रक्षा समिति आक्रामक साइबर हथियारों के इस्तेमाल पर एक विशेष बैठक करने जा रही है। यह बैठक एनएसओ समूह के पेगासस साफ्टवेयर के कथित दुरुपयोग को लेकर हुई अंतरराष्ट्रीय आलोचना के मद्देनजर बुलाई गई है। यह भी आशंका है कि इस तरह के और भी मामले उजागर हो सकते हैं, क्योंकि कई अन्य इजरायली कंपनियों की ओर से भी दूसरे देशों को इस तरह के साफ्टवेयर की आपूर्ति की गई है।

हारेट्स अखबार ने मंगलवार को अपनी खबर में बताया कि विदेश मंत्रालय और रक्षा समिति न सिर्फ एनएसओ और इसके साफ्टवेयर पर चर्चा करेगी, बल्कि हालिया महीनों में चर्चा में रहीं अन्य इजरायली कंपनियों के बारे में भी बातचीत होगी। यह बैठक नौ अगस्त को बुलाने की खबर है। हालांकि, समिति के अध्यक्ष राम बेन बराक ने इससे इन्कार किया है।

बता दें कि अपने निगरानी साफ्टवेयर पेगासस को लेकर विवादों में आई कंपनी एनएसओ समूह के खिलाफ इजरायल में जांच भी शुरू हो गई है। कई देशों की सरकारें इस कंपनी के जासूसी साफ्टवेयर पेगासस की ग्राहक हैं।

सतत प्रक्रिया है आरटीआइ कानून के प्रविधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जाते हैं और कानून के प्रविधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की। सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार की विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट में लंबित कई मामलों के मद्देनजर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की समीक्षा करने की कोई योजना है।

एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि सीबीआइ ने पिछले तीन वर्ष के दौरान 96 उच्चाधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि एक जनवरी, 2018 से 30 जून, 2021 तक सीबीआइ ने 84 मामलों में संघ लोकसेवा आयोग द्वारा चुने गए अधिकारियों समेत केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के तहत 96 उच्चाधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों ने उचित कार्रवाई की है।

लोकसभा प्रश्नोत्तर

पहले छह महीने में 12000 साइबर सुरक्षा की घटनाएं हुईं : इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि इस साल पहले छह महीने के दौरान सरकारी संगठनों से संबंधित करीब 12000 साइबर सुरक्षा की घटनाएं हुईं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) देश में साइबर सुरक्षा की घटनाओं को पकड़ने और नजर रखने का काम करती है।

जोन को कुल्हड़ का इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि जोन और आइआरसीटीसी को कुल्हड़ का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 400 चिह्नित स्टेशनों पर स्थित यूनिटों के माध्यम से यात्रियों की सेवा में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराने का प्रोजेक्ट स्थगित कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि यह वहन योग्य नहीं है।

निचली, अधीनस्थ अदालतों में 3.93 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित

▸ कानून मंत्री ने कहा, अदालतों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : निचली और अधीनस्थ अदालतों में 3.93 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। लोकसभा में बुधवार को एक लिखित उत्तर में कानून मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर इस वर्ष 30 जुलाई तक उपलब्ध सूचना के मुताबिक, निचली और अधीनस्थ अदालतों में कुल 3,93,21,607 मामले लंबित हैं। इनमें दीवानी के 1,05,10,012 और 2,88,11,595 आपराधिक मामले शामिल हैं।

कानून मंत्री ने सदन को बताया कि अदालतों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। निचली अदालत में कुल लंबित मामलों में से 1,02,001 निपटारे के लिए 30 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। इनमें से 37,423 दीवानी के और 64,578 आपराधिक मामले हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है।

मामलों की संख्या कम करने में जुटे हैं मंत्रालय, विभाग

कानून मंत्रालय ने एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि रेलवे और राजस्व विभाग जैसे मंत्रालय और विभाग अदालती मामलों की संख्या कम करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। रेलवे ने सभी स्तरों पर कोर्ट केस की प्रभावी निगरानी के लिए निर्देश जारी किए हैं।

जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिटों को सरकारी मामलों की संख्या कम करने एवं अदालतों पर बोझ घटाने के प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है। इसके साथ ही केस पर होने वाले खर्च में कमी लाने के लिए सभी अदालतों में सभी मामलों के तेजी से निपटारे को कहा गया है।

इसी तरह राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कई निर्देश जारी किए हैं और मुकदमों की संख्या कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

खिसियाहट

न तो बाइडन ने की इमरान से बात और न ही विदेश मंत्री ब्लिंकन पाक एनएसए मोईद से मिले, घरेलू जनता व मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगाने में जुटे विदेश मंत्री व एनएसए

अमेरिका से पाकिस्तान को नहीं मिली तवज्जो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ पड़ोसी मुल्क ने भारत पर खीज उतारी

किसी और की खीज किसी और पर उतारना। पाकिस्तान सरकार की कूटनीति का यही हाल है। अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को तवज्जो देने से इनकार कर दिया है। छह महीने बीत जाने के बावजूद राष्ट्रपति बाइडन ने आश्वासन देने के बावजूद पीएम खान को फोन नहीं किया है। रही सही कसर पिछले दिनों तब पूरी हो गई जब अमेरिका के दौरे पर गये पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मोइद युसूफ से वहां के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने मुलाकात तक नहीं की।

जब पाक के मीडिया व वहां के इंटरनेट मीडिया ने इसे पीएम की बड़ी असफलता के दौर पर गिनाया तो उनकी सरकार ने वही किया जो पूर्व में पाक की सरकारें करती रही हैं। यानी ध्यान भटकाने के लिए भारत पर आरोप लगाने का काम।

बुधवार को पाकिस्तान के सूचना व प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन, विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरैशी और एनएसए मोईद युसुफ ने एक साथ भारत के खिलाफ प्रोपगंडा शुरू किया।आधार बनाया गया कि पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली स्थित विदेशी मीडिया पत्रकारों को गुलाम कश्मीर की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन भारत सरकार ने उसकी मंजूरी नहीं दी। इनमें कोई भारतीय नहीं है। इन सभी पत्रकारों को पांच अगस्त, 2021 को पाक अधिकृत कश्मीर के नए संसदीय सत्र की शुरुआत में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन सभी को वाघा बार्डर के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश करना था।

हुसैन, कुरैशी और युसुफ ने इसकी आड़ में भारत पर प्रेस की आजादी को रोकने व दूसरे संगीन आरोप लगाये। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान ने ही कोरोना के मद्देनजर अप्रैल, 2021 में भारत से होने वाली हर तरह की यात्राओं पर पाबंदी लगा रखी है। यह पाबंदी अभी तक जारी है।

कुरैशी ने यूएनएससी को पत्र लिख कश्मीर का राग अलापा

पाक के विदेश मंत्री कुरैशी की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को बुधवार को एक पत्र लिखा गया है। इसमें कश्मीर का राग अलापते हुए पूरा आरोप भारत के सिर मढ़ा गया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि कश्मीर की समस्या के समाधान की पूरी जिम्मेदारी भारत की है।

जानकारों का कहना है कि घरेलू जनता व मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए यह पाकिस्तान का पुराना तरीका है। हाल ही में मीडिया ने बाइडन की तरफ से छह महीने बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन नहीं किये जाने का मुद्दा उठाया है। एनएसए स्वयं अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से नहीं मिल पाये। एनएसए युसूफ ने ब्रिटिश समाचार पत्र को एक साक्षात्कार में यह बात भी कही है कि अमेरिका से कई बार संकेत आने के बावजूद बाइडन ने उनके पीएम को फोन नहीं किया है।

पांच दलों को प्राप्त कुल राशि से तीन गुना मिला भाजपा को चंदा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) समेत पांच दलों के कुल चंदे से तीन गुना ज्यादा चंदा मिलने का एलान किया है। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने अमरावती नगर निगम से भी चंदा मिलने की जानकारी सार्वजनिक की है, जहां मेयर व डिप्टी मेयर उसी पार्टी से हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 'भाजपा द्वारा घोषित चंदे की राशि, कांग्रेस, राकांपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और तृणमूल द्वारा घोषित चंदे की कुल राशि से तीन गुना (228.03 करोड़ रुपये के मुकाबले 785.77 करोड़ रुपये) से भी अधिक है।' एडीआर की रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चंदे के रूप में प्राप्त 20 हजार रुपये से अधिक की राशि पर गौर किया गया है। इस राशि के बारे में पार्टियों ने खुद ही चुनाव आयोग को जानकारी दी है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

इसकी रफ़्तार ऐसी ही बनी रही तो मैं भी जल्द डूब जाऊंगा!!

2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव किसान यूनियन के बैनर तले नहीं, पंजाब मिशन के बैनर तले लड़ने का एलान किया है संयुक्त किसान मोर्चे के नेता व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी ने। उन्होंने कहा कि जल्द ही मिशन पंजाब का गठन किया जाएगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 5 अगस्त, 2021

उप्र में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रियंका होंगी कांग्रेस का चेहरा : तिवारी

नईदुनिया, रायपुर

- कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी ने किया दावा
- कहा-किसी भी पार्टी से गठजोड़ की बात नहीं चल रही, सभी सीटों पर लड़ेगी पार्टी

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी ने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का चेहरा होंगी। जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनके नेतृत्व में ही अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। जनता के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी प्रियंका को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।

राजेश तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी या अन्य किसी दल से अभी कोई गठजोड़ की बात नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तिवारी ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद बूथ स्तर पर मजबूती से सफलता मिली है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी प्रयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा पदाधिकारी पिछले तीन दिन से छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नेताओं को कांग्रेस के इतिहास से लेकर बूथ मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। इनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रशिक्षण दिया है। राजेश तिवारी ने बताया कि रायपुर के निरंजन धर्मशाला में मास्टर ट्रेनर को बूथ मैनेजमेंट की जानकारी दी गई। पांच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रियंका गांधी भी बुधवार शाम को वर्चुअल रूप से शामिल हुईं। इस दौरान प्रियंका ने अब तक के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। यह मास्टर ट्रेनर अब उत्तर प्रदेश के जिला, विधानसभा और ब्लाक स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे।

कांग्रेस में पीके की बड़ी सियासी भूमिका का खाका तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- प्रशांत किशोर के ब्लू प्रिंट पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा लगभग पूरी
- बड़े ओहदे के साथ सीधे सोनिया गांधी को करेंगे रिपोर्ट

कांग्रेस की राजनीतिक वापसी के रोडमैप को आगे बढ़ाने के लिए चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की सियासी भूमिका का स्वरूप पार्टी ने लगभग तय कर लिया है। प्रशांत किशोर को कांग्रेस संगठन के ढांचे को दुरुस्त करने के साथ चुनाव प्रबंधन से लेकर सियासी गठबंधनों को सिरे चढ़ाने की अहम जिम्मेदारी देकर पार्टी में शामिल किया जाएगा। पीके की इस सियासी भूमिका के लिए पार्टी में एक विशेष सलाहकार समिति के गठन की भी तैयारी है जो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेगी।

इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि शीर्ष संगठन में बड़े बदलावों के लिए लीक से हटकर उठाए जाने वाले कुछ अहम कदमों के साथ प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने का एलान जल्द हो जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए उसके सियासी आधार की वापसी के लिए पीके के दिए गए ब्लू प्रिंट पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच पिछले तीन हफ्ते के दौरान काफी लंबी और गंभीर चर्चा हुई है।

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

पार्टी हाईकमान के निकटस्थ माने जाने वाले दिग्गज नेता पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी, जयराम रमेश और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीके के ब्लू प्रिंट को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ छोटे-छोटे समूहों में चर्चा की है। कांग्रेस कार्यसमिति के कई सदस्यों से भी इस बारे में चर्चा की गई है और उनके फीडबैक लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन चर्चाओं के दौरान कुछ विषयों पर चाहे मतांतर हो, मगर कांग्रेस को मजबूत करने के प्रस्तावों को लेकर नेताओं की ओर से किसी तरह का एतराज नहीं दिखा है। इसके मद्देनजर ही माना जा रहा कि पीके को जल्द ही कांग्रेस में शामिल कर उनकी नई राजनीतिक भूमिका की घोषणा हो जाएगी।

बताया जाता है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए पीके ने जो प्रस्ताव दिया है उसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में पार्टी में एक विशेष सलाहकार समूह का गठन किए जाने की सिफारिश की गई है। इस समूह पर राजनीतिक निर्णयों, गठबंधन, चुनाव और चुनावी अभियानों से जुड़े अहम विषयों पर त्वरित रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी रहेगी ताकि फैसलों में देरी न हो। इस सलाहकार समूह का स्वरूप छोटा रखने की पीके ने सलाह दी है जिसमें छह से आठ नेताओं को ही रखे जाने का प्रस्ताव है। इस सलाहकार समूह का स्वरूप कुछ-कुछ यूपीए सरकार के समय सोनिया गांधी की अगुआई में गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की तरह ही रखे जाने की बात है। इससे साफ है कि प्रस्तावित समूह के राजनीतिक निर्णयों और कदमों पर अंतिम मुहर सीधे कांग्रेस कार्यसमिति में ही लगेगी।

बनाए जा सकते हैं महासचिव

सूत्रों का कहना है कि पीके को इस समूह के संचालन की जिम्मेदारी दिया जाना लगभग तय है और अब पार्टी संगठन में उनको ओहदा देने के स्वरूप पर ही अंतिम दौर की चर्चा चल रही है। पीके को कांग्रेस महासचिव बनाकर इस सलाहकार समूह के समन्वय का जिम्मा सौंपे जाने की संभावना प्रबल बताई जा रही है।

भाजपा में कार्यकर्ताओं का आधिपत्य, किसी परिवार का नहीं : नड्डा

- पार्टी अध्यक्ष ने कहा, जातियों के नाम पर लोगों ने की बहुत राजनीति
- सभी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम मोदी ने किया

नई दिल्ली में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय जनता पार्टी पर किसी परिवार का नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं का आधिपत्य है। वह परिवारों से नहीं, विचारों से चलती है। जातियों के नाम पर लोगों ने राजनीति तो बहुत की, लेकिन सभी वर्गों के जीवन में परिवर्तन लाने का यदि किसी ने काम किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उक्त बातें बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहीं। वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के सांसदों के सम्मान में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद बहुत नेता बने और उनमें कोई दलित नेता, कोई आदिवासी नेता, कोई किसान नेता और कोई पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में जाना गया।

उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने अपनी छवि को उस नाम के साथ जोड़ते हुए नेतृत्व किया, लेकिन किसानों के किसी नेता से अधिक अगर किसी ने काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का लोगों ने राजनीतिक उपयोग तो बहुत किया, लेकिन उन्हें न्याय दिलाने का काम और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कहा कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्रपति से लेकर कई राज्यों के राज्यपाल पद को सुशोभित कर रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ग के सबसे अधिक सांसद और विधायक भी भाजपा के ही हैं।

पीएम किसान योजना में बंगाल के साढ़े नौ लाख किसानों के आवेदन नामंजूर, ममता खफा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में राज्य के करीब साढ़े नौ लाख किसानों के आवेदन के खारिज होने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।

जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने केंद्र को जो सूची भेजी थी, उसमें से करीब साढ़े नौ लाख किसानों के आवेदन को पहली समीक्षा (रिव्यू) में ही नामंजूर कर दिया गया है। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद खफा हैं। इस बाबत नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार के कृषि विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है तथा तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा है कि हमने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र को पत्र लिखा है। केंद्र की गलती से बंगाल के किसान वंचित हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को केंद्र की कुछ तकनीकी त्रुटियों के चलते नुकसान न हो। उन्होंने अविलंब सभी किसानों को इस योजना का लाभ देने का अनुरोध किया। इधर, राज्य सचिवालय नवान्न के सूत्रों ने बताया कि इस पत्र के जरिये राज्य सरकार ने यह भी जानने की कोशिश की है कि आखिर इन किसानों के आवेदन को क्यों नामंजूर किया गया है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य की ओर से 44.8 लाख किसानों के नाम भेजे गए थे। बताते चलें कि बंगाल के करीब सात लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त इस साल मई में मिली थी।

सुवेंदु के करीबी को गिरफ्तार करने पर ममता सरकार ने मांगी माफी

कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर तुरंत रिहा किए गए राखाल बेरा

मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को, तब तक राखाल को नहीं किया जा सकता गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

बंगाल में भाजपा विधायक व नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी के करीबी रहे व्यवसायी राखाल बेरा को जमानत मिलने के बाद तुरंत गिरफ्तार करने के मामले में ममता सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में माफी मांगी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बुधवार को ही राखाल बेरा को रिहा करने का आदेश देते हुए हलफनामा तलब किया, जिसके बाद शाम को बेरा को रिहा कर दिया गया।

कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति शुभाशीष दासगुप्ता की पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। तब तक राखाल बेरा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के वकील पी. चिदंबरम ने अदालत को बताया कि बेरा को किसी राजनीतिक मकसद से गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि संयोग से पूर्व मेदिनीपुर के नंद कुमार थाने की पुलिस ने उन्हें गलतफहमी के चलते गिरफ्तार कर लिया था। यह स्थानीय पुलिस का फैसला था, लेकिन गलत था। इसके लिए हमें खेद है।

हालांकि, उन्होंने सवाल किया कि अगर राखाल को लेकर कानून-व्यवस्था की समस्या हो तो पुलिस क्या करेगी? तो क्या हम गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट की अनुमति का इंतजार करेंगे? कोर्ट ऐसा एकतरफा आदेश नहीं दे सकता। गौरतलब है कि पिछले सोमवार को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राखाल बेरा को रिहा करने और बिना कोर्ट के आदेश के उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था, फिर भी सोमवार को जमानत देने के बाद उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट की पीठ ने इसके लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत के आदेश पर बेरा को फिर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, पी. चिदंबरम ने इस बारे में कुछ नहीं जानने का दावा किया।

बंगाल हिंसा : सुनवाई पूरी होने के बाद भी कई ने हाई कोर्ट में लिखित तौर पर रखी अपनी बात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद भी कलकत्ता हाई कोर्ट की इजाजत पर इस मामले से जुड़े कई पक्षों ने बुधवार को लिखित रूप में अपनी बात रखी। उन्होंने बंद लिफाफे के माध्यम से अदालत के समक्ष अपनी बात पहुंचाई। गौरतलब है कि हिंसा मामले की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर गत मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, पीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को अंतिम मौका देते हुए इस बात की इजाजत दी थी कि अगर उन्हें इस मामले में और भी कुछ कहना है तो बुधवार दोपहर ढाई बजे तक वह लिखित रूप में अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष जमा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार हाई कोर्ट के निर्देशानुसार तय अवधि के भीतर बुधवार को मामले से जुड़े कई पक्षों ने लिखित रूप में अदालत के समक्ष अपनी बात रखी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इसमें किन तथ्यों का उल्लेख किया है, इसका अभी पता नहीं चल सका है।

राजभर ने कहा, चुनाव बाद पिछड़े को सीएम बनाने पर ही भाजपा से गठबंधन

राब्यू, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह से मुलाकात के बाद शुरू हुई अटकलों को विराम देने का पूरा प्रयास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर कर रहे हैं। बुधवार को बलिया में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा से किसी भी प्रकार के समझौते की संभावना को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि मंगलवार को स्वतंत्रदेव सिंह से क्या बात हुई, इस बारे में वह फोन कर खुद एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि किसी पिछड़ी जाति के नेता को सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करे, जातिगत जनगणना कराए और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की शर्त माने तो भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। साथ में जोड़ा कि भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना न के बराबर है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में एआइएमआइएम सहित छोटे दल शामिल रहेंगे और साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

योगी सरकार के पूर्व मंत्री राजभर ने कहा कि वह मोर्चा को मजबूती देने के लिए सात अगस्त को वाराणसी और आठ अगस्त को प्रयागराज में महिला और पिछड़ों का सम्मेलन करने जा रहे हैं। मंगलवार को राजभर ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद अटकलें शुरू हो गई हैं कि राजभर को मनाने का प्रयास चल रहा है।

रीता बहुगुणा का घर जलाने के आरोपित जितेंद्र भाजपा में शामिल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

भारतीय जनता युवा मोर्चा में दागी नेताओं को पदाधिकारी बनाए जाने के आरोपों के दो दिन बाद ही एक और घटनाक्रम ने भाजपा के 'पार्टी विद डिफरेंस' के दावे की समीक्षा सियासी हलकों में करा डाली। जातीय-क्षेत्रीय समीकरणों का संतुलन बनाते हुए संगठन को मजबूत करने में जुटी भाजपा ने बसपा के उन पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को भी पार्टी में भी शामिल कर लिया, जो कि भाजपा सांसद डा. रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपित हैं।

लखनऊ स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने भगवा पट्टिका पहनाकर बसपा और कांग्रेस के कुछ नेताओं को भाजपा में शामिल कराया। दूसरे दलों से आए नेताओं की सदस्यता का सिलसिला तो अब लगातार चल रहा है, लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ एक नाम की वजह से एकदम चर्चा में आ गया। दरअसल, अयोध्या से बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू भी भाजपा की सदस्यता लेने वालों में शामिल रहे। इनके मंच पर आते ही चर्चा शुरू हो गई कि 15 जुलाई, 2009 की रात को सांसद रीता बहुगुणा जोशी के हुसैनगंज स्थित आवास को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर जला दिया था। उसमें जितेंद्र सिंह बबलू भी आरोपित थे।

स्तब्ध हूं, प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष से करूंगी बात : जितेंद्र सिंह बबलू के भाजपा में शामिल होने पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी त्वरित प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह के पार्टी में शामिल होने के समाचार से वह स्तब्ध हैं। जब वह मुरादाबाद में जेल में बंद थीं, तब लखनऊ स्थित उनके आवास को आग लगाने वालों की अगुआई बबलू ने ही की थी। जांच में आरोप सही पाए गए। सांसद ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अग्निकांड के आरोपित ने तथ्य छुपाकर भाजपा की सदस्यता ली होगी। सदस्यता निरस्त कराने के लिए वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह से बात करेंगी। रीता बहुगुणा जोशी ने स्पष्ट तौर कहा कि अगर उन्हें जितेंद्र सिंह के पार्टी में शामिल होने की पहले से जानकारी होती तो वह तभी आपत्ति कर देती। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी आपत्ति पर पार्टी नेतृत्व जितेंद्र की सदस्यता खत्म कर देगा।

मंदिर पर भाजपा के 'तप' से जूझता विपक्ष का 'जप'

जितेंद्र शर्मा, लखनऊ

- कमंडल हाथ में लेकर चले भगवा दल की अब मंडल में भी है गहरी सेंध

'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे...' उत्तर प्रदेश ने यह भी सुना है और जेहन में 'मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जय...' भी होगा। पहला नारा कमंडल वाले भाजपा खेमे का संकल्प था तो दूसरे नारे में मंडल की सियासत से सत्ता हासिल करने वाली सपा-बसपा का दंभ था। वह भी एक दौर था, जिसमें सूबे की राजनीति ने कई उतार-चढ़ाव देखे जिसने कथित सेकुलर दलों का यह भरोसा मजबूत किया कि चुनावी जीत का गणित सिर्फ जातीय समीकरण पर टिका है। मगर, भाजपा के लंबे तप के बाद न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव जब ठीक एक वर्ष पहले पांच अगस्त को रखी गई तो विपक्ष को मंदिर फिर से मुद्दा बनता नजर आने लगा और वह भी राम के जप में जुट गया है।

उप्र में अगले वर्ष विस चुनाव होने हैं। 2014 के लोस चुनाव के बाद से लगातार प्रचंड जीत हासिल कर रही भाजपा के विजय रथ को रोकने को विपक्षी दल हर दांव आजमाना चाहते हैं। जातीय वोटबैंक में जोड़तोड़-सेंधमारी के तमाम प्रयासों के बीच निर्माणाधीन राम मंदिर और प्रभु राम के प्रति आपात-आस्था भी नजर आ रही है। 90 के दशक में जिस मंडल बनाम कमंडल की राजनीति से समाजवादी पार्टी को आधार मिला, उसके मुखिया अखिलेश यादव का सेक्युलरिज्म कुछ नरम पड़ा है। अल्पसंख्यक वोटों के लिए बेहद फिक्रमंद अखिलेश राम भक्तों के लिए परशुराम की वंदना में हैं। पार्टी ने हर जिले में भगवान परशुराम का मंदिर बनवाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में बन भी चुके हैं। इधर, बसपा की बात करें तो इस दल के सियासी पूर्वज राम मंदिर के समर्थन में कभी नहीं रहे, लेकिन मिशन-यूपी में पार्टी राम नाम जपते हुए उतरी है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पिछले दिनों अपनी सोशल इंजीनियरिंग से ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए अयोध्या से ही प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी की शुरुआत की। यही नहीं, बसपा नेता सरकार बनने पर राम मंदिर निर्माण तेज कराने का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस गाहे-बगाहे कह देती है कि राम तो सबके हैं। हालांकि, पिछले वर्ष राम मंदिर का शिलान्यास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तब यह सभी दल उस ऐतिहासिक अनुष्ठान से दूरी बनाए रहे। संभवतः मुस्लिम मत छिटक जाने का डर तीनों दलों को था। अब हालात अलग हैं। तमाम राजनीतिक गुणा-भाग विपक्षी खेमे के रणनीतिकारों के मन में होंगे। वह समझ रहे हैं कि एक दौर में भाजपा ने सिर्फ कमंडल की राजनीति की। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के तहत रथयात्रा निकाल कर 1991 में पहली बार भाजपा की सरकार प्रदेश में बनवा ली। फिर 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस होने पर अपनी सरकार का त्याग तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने किया। 1996 में फिर भाजपा की सरकार बनी, जिसमें राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जातिगत वोट बैंक का तानाबाना सपा-बसपा जैसे क्षेत्रीय दल मजबूत करते गए और भाजपा के लिए राह मुश्किल हो गई। मगर, अब सत्ताधारी भाजपा के हाथ में कमंडल से जुड़े सवर्ण के साथ मंडल के प्रभाव वाले पिछड़े और दलित वोट बैंक में गहरी पैठ है। सपा के पास यादव-मुस्लिम का आधार वोट है तो बसपा को जाटव के साथ मुस्लिम पर कुछ भरोसा है। ऐसे में हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के साथ अन्य जातियों की एकजुटता से आशंकित विपक्षी दलों को भी अब राम ही रामबाण नजर आ रहे हैं। यह भी तब है, जबकि योगी सरकार अयोध्या में विकास तो करा रही है, लेकिन पार्टी के चुनावी एजेंडे में सबका साथ, सबका विकास और सेवा ही संगठन का सूत्र है।

भाजपा के मिशन उत्तर प्रदेश में मददगार हो सकते हैं मांझी

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के पुत्र और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के मायने को महज शिष्टाचार की ओट में नहीं देखा जा सकता। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब उप्र में विस चुनाव करीब है और रामविलास पासवान के निधन के बाद राजग के पास हिंदी पट्टी में अनुसूचित जाति से कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। ऐसे में दो दिनों में भाजपा के दो शीर्ष नेताओं के साथ संतोष की सहज मुलाकात के भावार्थ को समझा जा सकता है। मोदी से मिलने से पहले संतोष सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे।

बिहार में लोजपा के आंतरिक कलह और उप्र में बसपा के दिन-प्रतिदिन कमजोर होती सियासी हैसियत का अहसास भाजपा को है। इसलिए उसे ऐसे चेहरे की दरकार है, जो दोनों राज्यों में समान रूप से असर डाल सके। मौजूदा हालात को मांझी की राजनीति के लिए भी अच्छा संकेत माना जा सकता है। उप्र चुनाव में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वोट बैंक बड़ा फैक्टर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी यह बात बखूबी समझ रहे हैं। बिहार में अब तक जदयू के ज्यादा करीब रहे मांझी उप्र में भाजपा नेतृत्व की प्रशंसा कर अपना झुकाव जाहिर कर चुके हैं। मांझी की पार्टी हम का भले ही उप्र में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, मगर अनुसूचित जाति से चेहरा होने के कारण उसको साथ जोड़े रखने में भाजपा को अपनी भलाई लग रही है। बसपा से रिक्त होने वाली राजनीतिक जमीन को प्राप्त करने के लिए कई बड़े दलों में होड़ है। भाजपा को भी मजबूत चेहरा बनकर उभर रहे अनुसूचित जाति के चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी से सतर्क रहने की जरूरत है। जल्द कोई मजबूत विकल्प नहीं उभारा गया तो इस समुदाय के युवा मायावती को छोड़ किसी और दरवाजे पर जा सकते हैं।

संतोष मांझी ने पीएम को अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण से जुड़ी 10 मांगों वाला अनुरोध पत्र सौंपा। इसमें निजी क्षेत्र व प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, न्यायपालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रविधान करने और पर्वत पुरुष स्व. दशरथ मांझी को भारत रत्न सम्मान देने का अनुरोध किया गया है।

सियासत

अखिलेश के लिए उप्र में रणक्षेत्र सजा रहे लालू

छोटे-छोटे क्षत्रपों को राजी करके सपा के लिए बड़ा फलक बनाया जा रहा

अरविंद शर्मा, पटना

कभी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद के बीच अदावत थी, मगर अब रिश्तेदारी हावी है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा तो लालू रिश्ते का फर्ज निभाने में जुट गए हैं। जैसा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के लिए निभाया था। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली समाजवादी पार्टी (सपा) ने 2020 में राजद को पूरा समर्थन दिया था। अब लालू की बारी है तो अखिलेश के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मुद्दे जुटाए जा रहे हैं और माहौल भी बनाया जा रहा है।

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हाल के दिनों में राजद की सक्रियता और हफ्ते भर में राकांपा प्रमुख शरद पवार के अलावा वरिष्ठ समाजवादी नेताओं से लालू की मुलाकात कुछ इसी ओर संकेत करती है। छोटे-छोटे क्षत्रपों को राजी करके यूपी में अखिलेश के लिए बड़ा फलक बनाया जा रहा है। लालू ने इसकी शुरुआत शरद पवार के उस ऐलान के दो दिन बाद किया, जिसमें कहा गया था कि राकांपा यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। राकांपा की घोषणा के बाद 29 जुलाई को लालू ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात कर उन्हें सपा के साथ आने का फायदा समझाया और गठबंधन का फार्मूला दिया।

राजनीति में फिर सक्रिय हुए लालू। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

बसपा प्राथमिकता में नहीं : फिलहाल लालू की प्राथमिकता में मायावती नहीं हैं, क्योंकि बसपा ने बिहार में राजद का साथ नहीं दिया था। लालू के जेल में रहने के दौरान विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारकर मायावती ने तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। लिहाजा, बसपा को भाव न देकर लालू यूपी में विकल्प की तलाश में हैं। नजर चिराग पासवान पर है, जो यूपी में मायावती से होने वाले नुकसान की एक हद तक भरपाई कर सकते हैं। लोजपा में टूट के बाद से ही राजद चिराग की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। महागठबंधन में बुलाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। लालू द्वारा चिराग की तारीफ किए जाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। एक दिन पहले समाजवादी नेता शरद यादव से मुलाकात के बाद लालू ने चिराग को उभरता हुआ युवा नेता बताकर तेजस्वी के साथ आने की संभावना जताई। यूपी चुनाव से जोड़कर इसका भी भावार्थ निकाला जा रहा है।

कांग्रेस को साथ लेने का जारी है प्रयास

राजद यूपी में कांग्रेस का साथ छोड़ने के पक्ष में नहीं है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के बिना भाजपा का विकल्प बनने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। लालू का प्रयास है कि कांग्रेस-सपा यूपी में पिछली बार की तरह साथ-साथ चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश के राजद अध्यक्ष अशोक सिंह के पास इसके लिए तर्क भी है। वह कहते हैं कि 2017 और 2022 के हालात में फर्क है। अबकी साथ आ गए तो चुनाव परिणाम पक्ष में आएगा।

सुशील मोदी ने लालू-मुलायम की मुलाकात पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, रांची

- मुलाकात से बढ़ी सियासी हलचल
- सीबीआइ को जमानत रद कराने की दी सलाह

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सपा नेता मुलायम सिंह यादव से मिलने पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सीबीआइ को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। सुशील मोदी के बयान पर सीबीआइ क्या कदम उठाती है, यह कुछ दिनों बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सीबीआइ लालू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। सीबीआइ ने ऐसा देवघर कोषागार से जुड़े मामले में किया भी है। लालू को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन उस मामले में अभी तक सुनवाई लंबित है। हालांकि इस बार लालू प्रसाद को जमानत देने के दौरान हाई कोर्ट के आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि लालू प्रसाद किसी राजनीतिक शख्सियत से मिलेंगे या नहीं। ऐसे में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है।

वहीं, लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि सपा नेता मुलायम सिंह यादव उनके समधी हैं और उनके बीमार होने की सूचना पर लालू प्रसाद यादव उनसे मिलने गए थे। इसमें कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने बताया कि सजा की आधी अवधि पूरी करने पर ही झारखंड हाई कोर्ट से लालू यादव को जमानत मिली है।

लालू यादव को किसी बीमारी के आधार पर जमानत नहीं दी गई है। पूर्व में इलाज के लिए मिली औपबंधिक जमानत के दौरान हाई कोर्ट ने लालू की राजनीतिक बयानबाजी पर रोक लगाई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सीबीआइ की याचिका दाखिल करने के सवाल पर लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि सीबीआइ को ऐसा करने का अधिकार है। किसी को याचिका दाखिल करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सीबीआइ की ओर से हाल फिलहाल में अभी तक कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। इससे पहले देवघर मामले में लालू की जमानत के विरोध में सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका जरूर दाखिल की है।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से संबंधित पांच में चार मामलों में सजा मिल चुकी है। सभी चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आधी सजा पूरी करने की दलील पर उन्हें यह राहत मिली है। वहीं, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।

बाढ़ से मप्र, राजस्थान और बंगाल बेहाल, पीएम ने संभाला मोर्चा

कहर ▸ चंबल नदी के किनारे खतरा बढ़ा, सिंध बहा ले गई ग्वालियर-चंबल के चार पुल

बंगाल में बाढ़ की स्थिति पर मोदी ने ममता से की बातचीत, दिया मदद का भरोसा

जागरण टीम, नई दिल्ली

बारिश और बाढ़ से बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान बेहाल हैं। सैकड़ों लोग बाढ़ के चलते जहां-तहां फंसे हुए हैं तो अनेक लोग बेघर हो गए हैं। बारिश जनित हादसों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। कई पुल ढह गए हैं। अलबत्ता, सेना सहित कई संगठन बचाव में जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने के बाद बुधवार को उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टेलीफोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर, ममता व शिवराज ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया।

मध्य प्रदेश में ग्वालियर-चंबल संभाग के कई जिलों में अब भी बाढ़ के हालात भयावह हैं। कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के कारण मुरैना-भिंड में खतरा बढ़ रहा है। यहां के लिए सेना की अतिरिक्त टुकड़ी बुलाई जा रही है। सिंध नदी का रौद्र रूप बरकरार है। बुधवार को दतिया और शिवपुरी जिले में एक-एक पुल ढह गया। भिंड में भी एक पुल के ढहने की आशंका जताई जा रही है। शिवपुरी-श्योपुर में भीषण बाढ़ के बाद हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री का वितरण युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। उधर, करैरा-नरवर में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के लिए बबीना से आई सेना की बाढ़ नियंत्रण टुकड़ी ने बचाव अभियान शुरू कर दिया था। श्योपुर और शिवपुरी की बीच कूनो पुल टूटने से दोनों जिलों के बीच आवागमन बंद है।

दतिया के कोटरा गांव में एयरलिफ्ट होते हुए प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा। वीडियोग्रैब

राजस्थान में बारिश की वजह से हुए विभिन्न हादसों में बुधवार को 10 लोगों की मौत हो गई है। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में मकान गिरने से एक ही परिवार के सात लोग दब गए। इनमें से तीन की मौत हो गई, जबकि चार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। केशवरायपाटन में ही चंबल नदी के पास बनी कच्ची सुरक्षा दीवार एक कच्चे घर पर गिर गई। इसमें सात लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण राज्य के चार जिलों कोटा,बारां,बूंदी और धौलपुर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बूंदी जिले के देहीखेड़ा इलाके में एक रोडवेज की बस बरसाती नाले में फंस गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रस्सों की सहायता से सवारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत कार्य देर रात तक जारी रहे।

उधर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर सेना की मदद ली जाएगी।

उधर, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ को मानव जनित बताते हुए इसके लिए दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पीएम मोदी से उसकी शिकायत भी की है। ममता ने कहा कि राज्य सरकार को सूचित किए बिना डीवीसी ने पानी छोड़ा, जिसके कारण ऐसे विकट हालात पैदा हुए हैं।

'पत्नी का करें सम्मान, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल'

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक पति से कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ सम्मान से पेश आए और अगर वह विफल रहता है, तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। कोर्ट की हिदायत के बाद इस युवा जोड़े के बीच समझौता हो गया। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति उसे प्रताड़ित करता है और उसके साथ कभी सम्मान का व्यवहार नहीं करता।

चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की वर्चुअल सुनवाई करते हुए पति और पत्नी दोनों को आनलाइन आने को कहा। दोनों के बीच समझौता कराने के प्रयास में जस्टिस कांत ने दंपती से हिंदी में बातचीत की। पत्नी ने कहा कि वह अपने पति के साथ रहने को तैयार है, लेकिन वह उसके साथ सम्मान से पेश नहीं आता। इस पर जस्टिस कांत ने हिंदी में पति से कहा कि हम आपके व्यवहार पर नजर रखेंगे। यदि आप कुछ भी गलत करते हैं, तो हम आपको नहीं बख्शेंगे।

जस्टिस कांत ने पति को आगाह किया कि वह अपनी पत्नी के साथ सम्मान के साथ पेश आने के वादे से पीछे न हटे। उन्होंने पति से अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका सहित सभी मामले वापस लेने को भी कहा। चीफ जस्टिस ने पति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश से कहा कि मामलों को वापस लेने के लिए एक हलफनामा दाखिल करें। लेकिन अगर पति गलत व्यवहार करता है, तो हम उसे वापस जेल भेज देंगे। हम अभी मामले को लंबित रख रहे हैं। पति ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और शांति से उसके साथ रहेगा। महिला ने समझौते की शर्त पर जोर देते हुए कहा, बस मुझे टार्चर (यातना) न करे। पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह जमानत के लिए नाटक है, तो हम नहीं छोड़ेंगे। पीठ ने जोर देकर कहा कि जोड़े को अपने रिश्ते को सामान्य करना चाहिए। कोर्ट ने वकील अंजना प्रकाश से कहा कि यह काम कोर्ट की बजाय उन्हें ही करना चाहिए था। कोर्ट की पहल पर पति-पत्नी एक दूसरे के खिलाफ सभी मामले वापस लेने पर सहमत हो गए। उल्लेखनीय है पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस रमना, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, ने एक महिला के साथ तेलुगु में बातचीत कर दो दशक पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत कराया था। चीफ जस्टिस रमना ने महिला को तेलुगु में कानूनी स्थिति के बारे में बताया और कहा कि पति की जेल की अवधि बढ़ाने से दोनों में से किसी को भी मदद नहीं मिलेगी।

शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना घोषित हो दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही सख्त कानून बनाने की संस्तुति की है। कहा है कि पुरुष की इस वर्चस्ववादी मानसिकता से सख्ती से निपटना चाहिए कि 'महिलाएं भोग विलास के लिए हैं', ताकि महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा न हो और लैंगिक असमानता को दूर करने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

दुराचार से महिला के जीवन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे गंभीर शारीरिक व मानसिक पीड़ा से गुजरना होता है। इसलिए शादी करने का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना कानून में दुष्कर्म का अपराध घोषित किया जाना चाहिए।
-इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी

कानपुर के हर्षवर्धन यादव की आपराधिक अपील खारिज करते हुए हाई कोट ने कहा कि अभियुक्त ने शादी का वादा किया, जब पीड़िता ट्रेन से कानपुर जा रही थी तो आरोपित ने मिलने की इच्छा जाहिर की और कोर्ट मैरिज के दस्तावेज तैयार करने की बात कह कर होटल में बुलाकर संबंध बनाए।

कांग्रेस विधायक बृहस्पत ने आदिवासियों को कहा अंगूठा छाप, छग में विरोध

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने एक पत्रकारवार्ता में आदिवासियों को अंगूठा छाप कह दिया है। बृहस्पत खुद आदिवासी वर्ग की आरक्षित सीट से विधायक हैं। इस बयान के बाद सर्व आदिवासी समाज और भाजपा उनके खिलाफ आक्रामक हो रही है। समूचे छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ विरोध जताया गया है।

अंबिकापुर में एक पत्रकारवार्ता में बृहस्पत से सवाल किया गया कि उन्होंने मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या कराने का आरोप लगाया था, लेकिन विधानसभा में माफी क्यों मांग ली। इस पर बृहस्पत ने कहा कि सरगुजा के अनपढ़ आदिवासियों की तरह सवाल न करें। मैंने क्या आरोप लगाया, विधायक दल की बैठक में क्या हुआ और विधानसभा में किसने माफी मांगी, यह सब रिकार्ड में है। बृहस्पत यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर किसके इशारे पर सवाल पूछ रहे हो। उन्होंने पत्रकारों को भी अपनी दिमागी हालत ठीक करने की नसीहत तक दे दी।

हरियाणवी को 50 फीसद नौकरियां दो, प्रति कर्मी 48 हजार सब्सिडी लो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▸ सरकार ने नए उद्योगों के लिए लांच की रोजगार सृजन सब्सिडी योजना

▸ किसान उत्पादक संगठन और एकीकृत पैक हाउस भी उठा सकेंगे योजना का लाभ

सूबे में 50 फीसद रोजगार हरियाणा के युवाओं को देने वाले नए उद्योगों को प्रदेश सरकार सात साल तक हर वर्ष 48 हजार रुपये प्रति कर्मचारी तक की सब्सिडी देगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने रोजगार सृजन सब्सिडी योजना अधिसूचित कर दी है। इस साल पहली जनवरी से योजना का लाभ मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि औद्योगिक रूप से बी, सी और डी श्रेणी खंडों के कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रेणी में हरियाणा के लोगों को 50 फीसद रोजगार देने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को सात साल तक अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के लिए 36 हजार रुपये और सामान्य श्रेणी के लिए 30 हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष की सब्सिडी दी जाएगी।

थ्रस्ट सेक्टर, आयात प्रतिस्थापन, आवश्यक क्षेत्र, जैव ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा उद्यमों और डेटा केंद्र एवं को-लोकेशन सुविधा (एमएसएमई, बड़ी, मेगा परियोजनाओं) के मामले में अनुसूचित जाति व महिला वर्ग के लिए 48 हजार रुपये और सामान्य श्रेणी के लिए 36 हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जाएगी।

पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन व एकीकृत पैक हाउस (ग्रेडिंग, सार्टिंग, पैकेजिंग आदि सुविधाओं वाले) भी योजना के लिए पात्र होंगे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहली जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयां योजना का लाभ उठा सकेंगी। औद्योगिक इकाइयों को पोर्टल पर आइईएम, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र और हरियाणा उद्यम ज्ञापन दर्ज करना होगा।

छोटे उद्योगों के उत्पादों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की बिक्री का मौका मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वालमार्ट वृद्धि तथा हकदर्शक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में एमएसएमई विभाग के महानिदेशक विकास गुप्ता, वालमार्ट वृद्धि की ओर से नितिन दत्त तथा हकदर्शक की ओर से सीईओ अनिकेत डायगर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। वालमार्ट के साथ समझौते से प्रदेश के एमएसएमई के उत्पाद जहां 24 देशों में प्रदर्शित होंगे, वहीं 48 बैनर्स के नीचे 10,500 स्टोर्स में उपलब्ध हो सकेंगे। एमएसएमई को जरूरत के अनुसार, उद्योग विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। हकदर्शक कंपनी की 22 राज्यों में सात हजार कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिससे एमएसएमई को लाभ होगा।

पटना के एक स्कूल के 17 बच्चों को 99.8 फीसद अंक, हुई शिकायत

जागरण संवाददाता, पटना : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं के परीक्षा परिणामों में पटना के लिट्रा वैली स्कूल के 17 बच्चों को 500 में से 499 अंक मिलने पर छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज से शिकायत की हैं। हालांकि, अभी सीबीएसई का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

सीबीएसई के एक अधिकारी के अनुसार स्कूलों को 10वीं के परिणाम को लेकर पूर्व के वर्षों का अंक अपलोड करने को कहा गया था। रिमाइंडर के बाद अंतिम क्षणों में इस स्कूल का परिणाम अपलोड किया गया। रिजल्ट जारी करने के फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमोदन प्राप्त है। ऐसे में स्कूल द्वारा फार्मूले में छेड़छाड़ की गई है तो यह जांच का विषय है। सीबीएसई 10वीं के परिणाम पर बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन डा. डीके सिंह ने कहा कि बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है। कई स्कूलों ने सीबीएसई से मिलीभगत कर मनमाने अंक दिए हैं। उन्होंने स्कूलों के परिणाम की मांग की है।

उप्र के कई कारखानों में ठेके पर काम कर रहे हैं रोहिंग्या

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▸ रोहिंग्या किशोरियों की तस्करी का मामला, एटीएस को सरगना नूर के साथियों की तलाश

त्रिपुरा सीमा से बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिकों की अवैध घुसपैठ कराने वाले गिरोह के तार उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से जुड़े रहे हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की जांच में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं। घुसपैठियों को अलीगढ़, बरेली, कानपुर, मेरठ व अन्य बड़े शहरों में मीट कारखानों व अन्य फैक्ट्रियों में ठेके पर नौकरी दिलाई गई थी। एटीएस अब उनकी छानबीन में जुटी है।

रोहिंग्या किशोरियों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार गिरोह के सरगना मुहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम से पूछताछ के आधार पर ही एटीएस ने बरेली से बांग्लादेश के नागरिक आले मियां व अब्दुल शकूर को गिरफ्तार किया था। दोनों एक मीट कारखाने में काम कर रहे थे। अब दोनों के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इससे पूर्व भी अलीगढ़, उन्नाव, संत कबीरनगर व अन्य शहरों में पहचान बदलकर रह रहे रोहिंग्या पकड़े जा चुके हैं। नूर से पूछताछ में पहले ही यह बात सामने आई थी कि वह बीते कुछ वर्षों में बांग्लादेश व म्यांमार के 100 से अधिक नागरिकों का घुसपैठ करा चुका है। इनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। अब्दुल व आले मियां को भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ किए जाने की तैयारी है। एटीएस ने अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर कई शहरों में अपनी छानबीन तेज की है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने बांग्लादेश निवासी मुहम्मद नूर के साथ उसके साथी म्यांमार के निवासी रहमतउल्ला व शबीउर्रहमान उर्फ शबीउल्लाह को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि एटीएस के हाथ अभी गिरोह के उन मददगारों तक नहीं पहुंच सके हैं, जिनकी मदद से फर्जी दस्तावेज बनवाकर घुसपैठियों की पहचान बदली जाती है। नूर से जुड़े कई अन्य युवकों की जानकारी मिली है, जिनकी तलाश की जा रही है।

धनबाद के जज की हत्या मामले में सीबीआइ ने दर्ज की प्राथमिकी

राज्य ब्यूरो, रांची

धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में झारखंड सरकार की अनुशंसा पर बुधवार को सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए सीबीआइ ने 20 सदस्यीय टीम बनाई है। सीबीआइ की नई दिल्ली स्थित विशेष अपराध शाखा के एएसपी विजय कुमार शुक्ला मामले के अनुसंधान पदाधिकारी बनाए गए हैं। जांच टीम में फारेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। एक दिन पहले ही इस मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआइ को प्राथमिकी दर्ज कर शीघ्र जांच करने का आदेश दिया था। इससे पहले 31 जुलाई को झारखंड सरकार ने जज हत्याकांड की सीबीआइ जांच की अनुशंसा की थी। इससे पूर्व धनबाद के स्थानीय थाना में इससे संबंधित प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज की थी। सीबीआइ जांच का आग्रह करने के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मामले की एसआइटी जांच चल रही थी। एसआइटी ने जज को धक्का मारने वाले आटो के चालक और मालिक समेत कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त आटो को जब्त कर उसके चालक व मालिक को गिरफ्तार किया था। अभी तक की जांच में पुलिस को हत्या की साजिश से संबंधित कोई सुराग नहीं मिल सका है। जज जिन मामलों की सुनवाई कर रहे थे, उनसे जुड़े लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही थी।

यह है मामला

28 जुलाई की सुबह धनबाद में सुबह की सैर के दौरान एक आटो के धक्के से जज की मौत का मामला सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आया है कि न्यायाधीश उत्तम आनंद के पीछे-पीछे चल रहा आटो अचानक तेजी से उनकी ओर मुड़ा और उन्हें टक्कर मार कर गिराने के बाद उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। स्वजन ने जज उत्तम आनंद की हत्या की आशंका जताते हुए धनबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अंतरराज्यीय अपराधी माधव दास के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

राज्य ब्यूरो, पटना : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुख्यात अंतरराज्यीय अपराधी माधव दास और उसके परिवार के खिलाफ खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में दास के अलावा उनकी पत्नी उर्मिला देवी और बहनोई योगेंद्र के नाम शामिल है।

ईडी से मिली जानकारी के अनुसार माधव दास एक कुख्यात अंतरराज्यीय अपराधी है और प्रतिबंधित चरमपंथी समूह का सदस्य भी। उसका बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में कई बैंक डकैती और डकैती का आपराधिक रिकार्ड है। ईडी ने पटना में विशेष प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में माधव दास और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली 1.01 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने और मनी लांड्रिंग के अपराध के लिए आरोपित को सजा देने की मांग की। ईडी ने दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 24 प्राथमिकी का संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया था।

सीबीआइ के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा पर लटकी 'तलवार'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ गृहमंत्रालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्मिक मंत्रालय को भेजा पत्र

सीबीआइ से जबरन हटाए जाने के ढाई साल बाद पूर्व निदेशक आलोक वर्मा को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा सकता है। गृह मंत्रालय ने आलोक वर्मा पर पद के दुरुपयोग और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्मिक मंत्रालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। कार्रवाई होने की स्थिति में आलोक वर्मा का पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को रोका जा सकता है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृहमंत्रालय की अंदरूनी जांच में 1979 बैच के आइपीएस अधिकारी आलोक वर्मा को पद के दुरुपयोग और सेवा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसी के आधार पर कार्मिक मंत्रालय को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। कार्मिक मंत्रालय ने कार्रवाई करने से पहले संघ लोकसेवा आयोग की राय मांगी है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय आइपीएस अधिकारियों के लिए कैडर कंट्रोलिंग अथारिटी है। जबकि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य लाभों की जिम्मेदारी कार्मिक मंत्रालय संभालता है। वहीं कोई भी कार्रवाई करने के पहले, आइपीएस अधिकारियों के चयन और नियुक्ति करने वाले संघ लोकसेवा आयोग की राय ली जाती है। दिल्ली पुलिस में आयुक्त रहने के बाद आलोक वर्मा को एक फरवरी 2017 को दो साल के लिए सीबीआइ निदेशक बनाया गया था। वहीं उनका अपने ही अतिरिक्त निदेशक राकेश अस्थाना से झगड़ा हो गया था। वर्मा और अस्थाना दोनों ने एक-दूसरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीबीआइ के दो शीर्षस्थ अधिकारियों के बीच झगड़े के कारण सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई थी। अंततः सरकार ने दोनों अधिकारियों को सीबीआइ से बाहर कर दिया।

घेरे में आलोक वर्मा। फाइल फोटो

मनी लांड्रिंग मामले में अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में कारोबारी व अवंता ग्रुप आफ कंपनीज के प्रमोटर गौतम थापर को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली व मुंबई में की गई छापेमारी के बाद मंगलवार रात 60 वर्षीय थापर को प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

ईडी थापर की कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर व उनकी पत्नी के बीच कथित लेनदेन की जांच कर रही है। उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की तरफ से दर्ज प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार ईडी ने थापर, प्रवर्तकों व दिल्ली तथा गुरुग्राम स्थित दो निजी कंपनियों पर यस बैंक को अवैध तरीके से 467 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

सीबीआइ ने पिछले साल कपूर और उनकी पत्नी बिंदु के खिलाफ कथित तौर पर 307 करोड़ रुपये की रिश्वत के तौर पर अवंता रियल्टी से दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर 1.2 एकड़ का एक बंगला ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बाजार मूल्य से आधी दर पर खरीदने और बदले में लगभग 1,900 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की सुविधा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। जून में सीबीआइ ने थापर व अन्य के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक से 2,435 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में नया मुकदमा दर्ज किया है।

गौतम थापर पर शिकंजा। फाइल फोटो

पायलट और सह पायलट की तलाश में बारिश बनी बाधा

जासं, पठानकोट : रणजीत सागर बांध में मंगलवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के ध्रुव एएलएच मार्क-चार हेलीकाप्टर के पायलट व सह-पायलट का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा। सुबह बारिश के कारण तलाशी अभियान देरी से शुरू हुआ। दिल्ली से आए गोताखोरों और सेना की चार टीमों ने दिन भर हेलीकाप्टर के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल एएस बाठ और को-पायलट कैप्टन जयंत जोशी की तलाश की। एक विशेष बोट से टीम के सदस्य झील के बीच पहुंचे। दो गोताखोर आक्सीजन व हाइड्रोजन के सिलेंडर और झील के अंदर खुदाई के लिए दो औजार लेकर गए। अंदर पहुंच कर वे एक विशेष यंत्र से बोट में बैठे अपने साथियों को जानकारी देते रहे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक झील से सटे इलाके में टेंट लगा कर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है।

बोम्मई ने किया मंत्रिमंडल का गठन, 29 ने ली मंत्री पद की शपथ

बेंगलुरु, प्रेट्रः कर्नाटक में पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले बासवराज बोम्मई ने बुधवार को मंत्रिमंडल का गठन किया। मंत्रिमंडल में 29 लोगों को मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में आयोजित समारोह में सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्री बने 23 नेता बीएस येदियुरप्पा सरकार में भी मंत्री थे, जबकि छह मंत्री नए चेहरे हैं।

बोम्मई ने जिन पुराने साथियों को मंत्री बनाया है उनमें गोविंद कारजोल, केएस ईश्वरप्पा, आर अशोका, सीएन अश्वथ नारायण, बी श्रीरामुलु, उमेश कट्टी, एसटी सोमाशेखर, के सुधाकर और बीसी पाटिल प्रमुख हैं। मंत्रिमंडल के नए चेहरे वी सुनील कुमार, आरगा जनानेंद्र कुमार, मुनिरत्ना, हलप्पा आचार, शंकर पाटिल मुनेनकोप्प और बीसी नागेश हैं। नवगठित मंत्रिमंडल में आठ लिंगायत, सात वोक्कालिगा, सात पिछड़ा वर्ग, तीन अनुसूचित जाति, दो ब्राह्मण, एक अनुसूचित जनजाति और एक रेड्डी समुदाय के मंत्री हैं। एक महिला (शशिकला जोले) को मंत्री बनाया गया है। बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पिछले हफ्ते बोम्मई भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए थे। 28 जुलाई को उन्होंने शपथ ली थी।

बेंगलुरु में बुधवार को राजभवन में आयोजित समारोह में पारंपरिक पहनावे में मंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रभु चव्हाण को बधाई देते कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई। प्रेट्र

परिसंपत्तियों के बंटवारे पर उप्र व उत्तराखंड की बैठक बुलाए केंद्र

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों के वेतन भुगतान व परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन व रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बंटवारे पर निर्णय के लिए जल्द दोनों राज्यों के परिवहन सचिवों की बैठक बुलाने के आदेश केंद्रीय परिवहन सचिव को दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि एक सप्ताह के भीतर बताएं कि बैठक कब तक कराएंगे।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य के वित्त सचिव अमित नेगी, परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा, परिवहन निगम के एमडी नीरज खैरवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

घर वापसी : शामली में मुस्लिम परिवार ने फिर हिंदू धर्म में की वापसी

जागरण संवाददाता, शामली

▸ शपथ पत्र के साथ एसडीएम से मिला कांधला का मुस्लिम दंपती

▸ बोले-बुजुर्ग हिंदू थे, माता-पिता ने अपनाया था इस्लाम

उप्र में शामली के कांधला में एक मुस्लिम दंपती ने अपने चार बच्चों के साथ हिंदू धर्म में वापसी की है। दंपती ने साफ किया है कि वे पहले हिंदू थे, लेकिन उनके माता-पिता ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। दंपती ने एसडीएम से मुलाकात कर दस्तावेजों में नाम परिवर्तन का भी आग्रह किया।

बुधवार को कांधला के मोहल्ला रायजादगान निवासी राशिद पुत्र उमर व उनकी पत्नी मंजो बानो कलक्ट्रेट पहुंचे। राशिद ने हिंदू धर्म में आस्था जताते हुए आधार कार्ड में नाम बदलने की मांग उठाई। राशिद ने बताया कि करीब 12 वर्ष पूर्व उसके माता-पिता मुस्लिम बन गए थे। उस समय उन्हें इसकी समझ नहीं थी। उन्होंने अपना नाम राशिद से बदलकर विकास रख लिया है। बताया कि उसने, पत्नी मंजू व चारों बच्चों ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। राशिद उर्फ विकास ने बताया कि वह शपथ-पत्र के साथ एसडीएम शामली संदीप कुमार से मिले थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर मदद करने से मना कर दिया कि उन्हें इस मामले में कैराना कोर्ट जाना होगा। राशिद ने स्पष्ट किया कि वह बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना रहा है। पत्नी मंजो बानो उर्फ मंजू ने बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना पुराना धर्म अपनाया है।

सास-ससुर ने धर्म बदला था, लेकिन उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बताया की जब उसकी शादी हुई थी तो ससुराल वाले हिंदू थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही सास-ससुर मुस्लिम बन गए थे। उधर, भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी ने भी प्रकरण में पुनः दंपती को लेकर एसडीएम से मुलाकात की।

भाजपा नेता ने बताया कि एसडीएम ने नियमानुसार प्रक्रिया बताई है। इस बाबत एसडीएम संदीप कुमार से उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर वार्ता करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

प्रशासन करेगा सहयोग : डीएम

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि दंपती अपनी इच्छानुसार पुनः हिंदू धर्म अपना सकता है। इनकी सुरक्षा के लिए एसडीएम, सीओ को निर्देशित किया है। दोनों अधिकारी घर पहुंचकर जानकारी लेंगे। दस्तावेजों में नाम परिवर्तन प्रक्रिया में नियमानुसार मदद की जाएगी।

प्रोटोकाल का पालन नहीं होने से केरल में बिगड़े हालात

रिपोर्ट ▸ केंद्रीय टीम ने कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन का नहीं हो रहा पालन

माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में भी मिली घोर लापरवाही, कोरोना प्रबंधन के केरल माडल की खुली पोल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने से केरल में महामारी बेकाबू हुई है। केंद्र की ओर से भेजी गई छह सदस्यीय टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। टीम का नेतृत्व नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल के निदेशक डा. एसके सिंह कर रहे थे। रिपोर्ट ने कोरोना प्रबंधन के कथित केरल माडल की पोल खोल दी है।

केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के अनुसार केरल में न तो कांट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और न ही संक्रमित व्यक्तियों पर निगरानी की कोई प्रणाली है। केरल के मलप्पुरम जिले, जहां कोरोना के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, में एक संक्रमित व्यक्ति पर औसतन केवल 1.5 व्यक्तियों की कोरोना की जांच की जा रही है। जबकि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की गाइडलाइंस में एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 व्यक्तियों की पहचान कर कोरोना की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। जाहिर है कांट्रैक्ट ट्रेसिंग के अभाव में बिना लक्षण या सामान्य लक्षण वाले संक्रमित व्यक्ति भी आसानी से घूम-फिर रहा है और दूसरे लोगों को संक्रमण फैला रहा है।

मानकों के मुताबिक जांच नहीं : टीम ने कहा है कि जांच में भी लापरवाही बरती जा रही है। आइसीएमआर 70 फीसद आरटी-पीसीआर और 30 फीसद रैपिड एंटीजन टेस्ट का अनुपात बनाने की सलाह दे रहा है। लेकिन केरल के कई जिलों में आरटी-पीसीआर 20 फीसद और रैपिड एंटीजन टेस्ट 80 फीसद हो रहा है। संक्रमित लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखने का प्रयास भी नहीं कर रही है।

सिर्फ गंभीर लक्षण वालों की ही जांच

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केरल में केवल उन्हीं व्यक्तियों की कोरोना जांच हो रही है, जिनमें गंभीर लक्षण दिख रहे हैं। यानी राज्य सरकार बिना लक्षण या सामान्य लक्षण वाले संक्रमितों की पहचान की कोई कोशिश नहीं कर रही है। परिणामस्वरूप जांच के साप्ताहिक आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है और इसकी वजह से संक्रमण दर ज्यादा बनी हुई है। ध्यान देने की बात है कि केरल के 10 जिलों में संक्रमण दर 10 फीसद से ऊपर बना हुआ है।

एक दिन की गिरावट के बाद फिर बढ़े सक्रिय मामले

जेएनएन, नई दिल्ली

केरल में फिर नए मामले 20 हजार को पार कर गए हैं। इसके चलते पूरे देश में पिछले 24 घंटे के दौरान नए मामलों का आंकड़ा 40 हजार को पार कर गया है। एक दिन पहले केरल में 13 हजार मामले मिले थे तो देश का आंकड़ा 30 हजार केस पर आ गया था। नए मामलों के बढ़ने और उसकी तुलना में कम मरीजों के ठीक होने से सक्रिय मामलों में पांच हजार से ज्यादा की वृद्धि हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार को सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चार लाख 10 हजार से ज्यादा हो गई है जो कुल मामलो का 1.29 फीसद है। प्रतिदिन होने वाली मौतें भी पांच सौ को पार कर गई हैं। मरीजों के उबरने की दर में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन मृत्युदर पिछले कुछ दिनों से स्थिर बनी हुई है। दैनिक और साप्ताहिक संक्रमण दर भी तीन फीसद से नीचे ही बनी हुई है।

देश में कोरोना की स्थिति

24 घंटे में नए मामले	42,625
कुल सक्रिय मामले	4,10,353
24 घंटे में टीकाकरण	62.53 लाख
कुल टीकाकरण	48.52 करोड़

बुधवार सुबह 08 बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	42,625
कुल मामले	3,17,69,132
सक्रिय मामले	4,10,353
मौतें (24 घंटे में)	562
कुल मौतें	4,25,757
ठीक होने की दर	97.37 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.31 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.36 फीसद
जांचें (मंगलवार)	18,47,518
कुल जांचें (मंगलवार)	47,31,42,307

संक्रमण से उबरे और दोनों डोज लेने वाले ज्यादा सुरक्षित

नई दिल्ली, एएनआइ : कोरोना संक्रमण से उबरे और कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाने वाले लोग वायरस के डेल्टा वैरिएंट से ज्यादा सुरक्षित हैं। एक अध्ययन में ऐसे लोगों में वायरस के इस घातक वैरिएंट के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा पाई गई है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) द्वारा यह अध्ययन किया गया है। इसमें कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लेने वाले लोगों और कोरोना से संक्रमित होने के बाद इसी वैक्सीन को एक या दोनों डोज लोग लेने वालों में कप्पा और डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ एंटीबाडी का अध्ययन किया गया था। इसमें पाया गया कि पूर्ण टीकाकरण यानी कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद संक्रमित होने वाले और संक्रमण से ठीक होने के बाद टीके लेने वाले लोगों में उन लोगों की तुलना में मजबूत प्रतिरक्षा पाई गई जिन्होंने कोविशील्ड की एक या दोनों डोज लगवाई हैं। विज्ञानी टीकाकरण के बाद संक्रमण के मामले को ब्रेकथ्रू केस कहते हैं, क्योंकि वायरस टीके की वजह से पैदा हुई प्रतिरक्षा प्रणाली को तोड़कर संक्रमित करता है।

कुंभ कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में नोवस लैब के मैनेजर से पूछताछ

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कुंभ में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआइटी ने स्थानीय लैब संचालकों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पहले दिन एसआइटी ने हरिद्वार की नोवस लैब के मैनेजर से घंटों पूछताछ की। रुड़की और देहरादून के लैब संचालकों से भी पूछताछ की जाएगी। नोवस लैब ने कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र के अलावा जिला स्तर पर भी कोरोना जांच की थी।

घोटाले की शिकायत आने के बाद अब तक एसआइटी टीम ने मैक्स कारपोरेट सर्विसेज की ओर से नलवा लैब हिसार व डाक्टर लाल चंदानी लैब दिल्ली के टेंडर की जांच की थी। जबकि इसके अलावा दस अन्य लैब ने कुंभ में टेस्टिंग की थी। जांच में घोटाला पकड़ने के बाद पुलिस ने आरोपित आशीष वशिष्ठ को गिरफ्तार किया था। घोटाले सामने आने के बाद अब दूसरे नंबर में अत्यधिक जांच करने वाली नोवस लैब से पूछताछ शुरू हो चुकी है। इस लैब ने हरिद्वार में 10 जगहों पर करीब 56 हजार जांच की है। बुधवार दोपहर एसआइटी ने लैब की ओर से कुंभ मेले में कामकाज देखने वाले मैनेजर को नोटिस देकर बुलाया और घंटों पूछताछ की। इसके अलावा रुड़की की एक और लैब से एसआइटी पूछताछ कर सकती है। एसआइटी के अधिकारियों का कहना है कि कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग करने वाली सभी लैब की जांच की जा रही है।

भक्तों के लिए 16 अगस्त से खुलेगा पुरी जगन्नाथ मंदिर

जागरण टीम, भुवनेश्वर : श्रीक्षेत्र धाम पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर आगामी 16 अगस्त से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पहले पांच दिन तक पुरी शहर के लोगों को महाप्रभु के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद 23 अगस्त से सभी भक्त महाप्रभु का दर्शन कर पाएंगे। कोविड दिशा-निर्देश के तहत भक्त महाप्रभु का दर्शन करेंगे। यह जानकारी बुधवार को जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक किशन कुमार ने दी।

मुख्य प्रशासक ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण जगन्नाथ मंदिर को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। इस बीच बिना भक्तों के महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा हुई थी। रथयात्रा खत्म होने के बाद जगन्नाथ मंदिर खोलने को लेकर बुधवार को जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक किशन कुमार की अध्यक्षता में छत्तीसा निजोग की बैठक हुई।

निर्णय के मुताबिक 16 अगस्त सोमवार से श्रीमंदिर खोला जाएगा। पहले पांच दिन पुरी शहर के लोगो को दर्शन की अनुमति दी गई है। 16 से 20 अगस्त तक पुरी के लोगों के लिए महाप्रभु का दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। 21 एवं 22 अगस्त को पुरी शहर शट डाउन है, ऐसे में भक्त मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस दो दिनों में मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त से सभी भक्तों के लिए महाप्रभु का द्वार खोल दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में बदलाव के 2 साल

अनुच्छेद 370 से मुक्ति : जम्हूरियत के फलों का स्वाद लेने का दौर आ चुका

मुख्यधारा में शामिल

नवीन नवाज, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिले दो साल बीते चुके हैं। इस दौरान राजनीतिक और संवैधानिक ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव और विकेंद्रीकरण देखने को मिला है। दो साल पहले यह देश का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी मुख्यधारा से अलग-थलग नजर आता था। अलगाववादियों और मौकापरस्त सियासतदानों की चंगुल में फंसा था। लेकिन, अब पूरी तरह राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल है।

दो वर्षों में जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जिस तेजी से हुई है, वह अभूतपूर्व है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बहाल हुई है, नगर निकाय पहले से ज्यादा प्रभावी, स्वतंत्र और क्रियाशील हैं। खुद पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं दिग्गज सियासतदान भी बदलाव को स्वीकार करते हैं। इसका सुबूत यही है कि 30 साल बाद 2021 में पंचायत चुनाव हुए। इससे पहले 2002 में जब पीडीपी-कांग्रेस की सरकार बनी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मुफ्ती मुहम्मद सईद ने सभी पंचायतों को भंग कर दिया। 2011 में पंचायत चुनाव हुए, लेकिन पंच-सरपंच बने और वह भी सीमित अधिकारों के साथ। पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था कभी लागू नहीं हो पाई। अब 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हो चुका है। पंचायतों और नगर निकायों से संबंधित सभी प्रविधान लागू हैं। पंचायतों को सीधा पैसा मिल रहा है। लोग विकास प्राथमिकताएं खुद तय कर रहे हैं। हाल ही में हुए डीडीसी चुनाव ने वास्तव में जम्मू और कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है।

लोकतंत्र की मजबूती में बड़ी बाधा था 370 का प्रविधान : आज पंचायत, ब्लाक विकास परिषद और जिला विकास परिषद (डीडीसी) क्रियाशील हैं तो उसका श्रेय अनुच्छेद 370 हटाए जाने को जाता है। यह प्रविधान लोकतंत्र की मजबूती में बाधा था। इसने अलगाववाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और पारिवारिक शासन को बढ़ावा दिया। केंद्र की जनकल्याण योजनाएं सीमित वर्ग के कल्याण का जरिया बनती थीं। लेकिन, अब लोकतांत्रिक संस्थान मजबूत हुए हैं और सभी केंद्रीय एजेंसियां नियमित निगरानी कर रही हैं। प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी है।

केंद्रीय कानून सीधे लागू नहीं होते थे... : पांच अगस्त, 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर में कोई केंद्रीय कानून सीधे लागू नहीं हो पाता था। वह तभी लागू होता जब विधानसभा उस कानून को स्थानीय सत्ताधारियां और एक वर्ग विशेष के मुताबिक उसमें बदलाव करती। कई बार केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में प्रभाव गंवा बैठते।

बहरहाल, लगभग 106 जन-हितैषी कानून और नौ संवैधानिक संशोधन अब राज्य में लागू हो चुके हैं। शिक्षा का अधिकार, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2001, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम और महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों के लाभ के लिए अधिनियम समेत कई प्रगतिशील कानून अब जम्मू कश्मीर मे लागू हैं।

अब्दुल्ला व मुफ्ती परिवार ने किया कमजोर : नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला चाहे जो कहें, लेकिन आम जनमानस मानता है कि राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए यह परिवार काफी हद तक जिम्मेदार है। 370 की बहाली को अपना एजेंडा बता रहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इसे नहीं नकार सकतीं कि उनके पिता दिवंगत मुफ्ती मुहम्मद सईद ने लोकतंत्र को ताक पर रखकर पंचायतों को भंग किया था। 1951 में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी का नामांकन सही नहीं पाया गया और उन्हें अयोग्य करार दिया गया। गुज्जर-बक्करवाल समुदाय को कभी राजनीतिक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। लेकिन, अब लोकतांत्रिक संस्थान मजबूत दिख रहे हैं।

यह है श्रीनगर का दिल कहलाने वाला लाल चौक। कभी यहां बंद, हड़ताल, पथराव करती भीड़ और उन्हें भगाते पुलिस के बख्तरबंद वाहन ही नजर आते थे, लेकिन दो साल में नजारा पूरी तरह बदल चुका है। अब पांच अगस्त से एक दिन पहले बुधवार को यहां बाजार में खूब चहल-पहल नजर आई। जागरण

दो वर्ष पूरे होने पर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दो वर्ष पूरे होने के दिन पांच अगस्त को आतंकी वारदात की आशंका में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के शिविरों पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। करीब तीन सौ किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई सुरक्षा बलों के शिविर हैं, जिन पर पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं। अक्सर देखा गया है कश्मीर से आतंकी जम्मू की ओर आते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों के शिविरों पर आत्मघाती हमले करते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर औचक नाके लगाकर सुरक्षा बल वाहनों की जांच करने के साथ संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रख रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। शहर की ओर तड़के दूध और सब्जी लेकर आने वाले वाहनों की जांच करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है।

अब पत्थरबाजी नहीं, खेल मैदानों में भविष्य संवार रहा कश्मीरी युवा

नवीन नवाज, श्रीनगर

सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंकते कश्मीरी नौजवान आजकल टीवी चैनलों में नजर नहीं आते। अखबारों में भी ऐसी तस्वीरें नहीं दिखतीं। वाकई में पत्थरबाजी को शगल समझने वाला कश्मीरी नौजवान अब गली-बाजारों से गायब हो चुका है। वह अब पत्थरबाजी में नहीं, बल्कि खेल के मैदानों में पसीना बहा रहा है ताकि खुद का और कश्मीर का भविष्य संवार सके। उसकी इसी उम्मीद को परवाज देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार हर गांव और पंचायत में खेल मैदान विकसित कर रही है। प्रदेश में फुटबाल, हाकी अकादमी भी स्थापित की जा रही हैं। आज जम्मू कश्मीर देश का एक बड़ा खेल केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

जम्मू कश्मीर की समस्या को अक्सर स्थानीय युवाओं की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक आकांक्षाओं के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। बंदूक उठाने वाले युवाओं के समर्थक अक्सर कहते थे कि उनके पास करने को कुछ नहीं है, उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती इसलिए वह बंदूक उठा रहे हैं। लेकिन पिछले दो वर्षों में सबकुछ तेजी से बदल रहा है। पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के बाद अगर सियासत को एकतरफ छोड़ दिया जाए तो कोई भी सहज स्वीकार कर लेगा कि बीते दो वर्षों से खेल ढांचे के साथ-साथ स्थानीय युवा और खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं।

युवाओं की सहभागिता से बना रोडमैप

युवाओं को पूरी तरह मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास कोई अकेले नहीं कर लिया गया, बल्कि पत्थरबाजी और आतंकी हिंसा में लिप्त कई युवाओं से बातचीत के आधार पर खेल ढांचा विकसित करने का रोडमैप बनाया गया। मौजूदा वर्ष के बजट में सिर्फ खेल गतिविधियों के लिए ही 513 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

आज ही हटी थी अनुच्छेद 370 की बाधा, दिवाली जैसा जश्न

- दिवाली की तरह होगी दीपमाला, छतों पर लहराए जाएंगे तिरंगे
- भाजपा ने की व्यापक तैयारी, मंडल स्तर पर होगा आयोजन

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधक रहा अनुच्छेद 370 पांच अगस्त, 2019 को हटा था। इस ऐतिहासिक दिन को इस बार यादगार तरीके से मनाने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने खास आयोजन किया है। उसके कार्यकर्ता मंडल स्तर पर तिरंगा फहराकर उत्सव मनाएंगे। पार्टी ने लोगों से घरों की छतों पर तिरंगे फहराने की अपील की है। पांच अगस्त से शुरू यह जश्न स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक जारी रहेगा। लद्दाख में भी गुरुवार को तिरंगों की धूम रहेगी।

जम्मू में भाजपा ने दिन में तिरंगा लहराने और शाम को दीपमाला करने के साथ पटाखे चलाने की योजना बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना सुबह दस बजे त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय व जम्मू कश्मीर सह प्रभारी आशीष सूद पुंछ में तिरंगा फहराएंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषांगिक संगठनों ने विशेष तैयारी की है। भाजपा ने जिला इकाइयों को निर्देश दिया है कि शानदार आयोजन कर राष्ट्रवादी ताकतों के मजबूत होने का संदेश दें। मंडल स्तर पर तिरंगे भी बांटे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जिला प्रधानों से बाकायदा तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान कोरोना से बचाव की हिदायतों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। भीड़ भाड़ न करने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अपने घरों की छतों पर तिरंगे फहराएं।

कश्मीर में सियासत ही नहीं सोच में भी बदलाव

नवीन नवाज, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू हुए दो वर्ष बीत रहे हैं। इसका असर अब कश्मीर में जीवन के हर पहलू पर नजर आता है। सिर्फ सियासत ही नहीं, सोच में भी बदलाव आया है। अगर लोगों में कुछ नाराजगी बची है तो चेहरे पर खानदानी सियासत, अलगाववादी मानसिकता से मुक्ति की खुशी की लकीरें भी साफ नजर आती हैं। कोई हड़ताल का जिक्र नहीं करता, तिरंगा उतारने की नहीं, लहराने की बात होती है। कल तक जो पाकिस्तान को कश्मीर में अमन के लिए सबसे अहम मानते थे, आज वही सियासतदान कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल तो दिल्ली (हिंदोस्तान) से बंधा है, हमें जो लेना है, दिल्ली से ही लेना है। यह बदलाव दक्षिण कश्मीर में जवाहर सुरंग के साथ सटे काजीगुंड से लेकर गेट-वे आफ मिलिटेंसी के नाम से कुख्यात रहे कुपवाड़ा के अंतिम छोर टंगडार तक साफ महसूस किया जा सकता है।

कुलगाम के रहने वाले जामिन ने बीते दो वर्षों में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी यहां आतंकियों के कुछ समर्थक मिलेंगे, लेकिन अब वह मुखर नहीं रहे हैं। कल तक लोग उनसे डरते थे आज वह खुद डरे हुए हैं। अब लोग किसी आतंकी की मौत पर उसके घर जाने के बजाय उन लड़कों को मुबारक देते हैं जो यूपीएससी, नीट और जेईई में पास होते हैं। आज यहां लोगों के लिए पाकिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि तनवीर अहमद खान हीरो है। एक स्कूल अध्यापक के पुत्र तनवीर ने इंडियन इकानामिक सर्विसीज में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आज कुलगाम में आप किसी नौजवान से बात करो तो वह जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरी की बात नहीं करता, वह यूपीएससी की तैयारी पर जोर देता है।

अब न कोई आजादी का नारा देने वाला, न सुनने वाला : लालचौक में कश्मीरी दस्तकारी की दुकान चलाने वाले जावेद नक्शबंदी ने कहा कि हड़ताल के दिन बीते रे मौला। अब माल कमाने और चैन से सोने का वक्त आया है। उसने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ। आज यहां आजादी और हड़ताल का नारा देने वाला नहीं है, न कोई सुनने वाला है। अनुच्छेद 370 और 35ए समाप्त होने पर जावेद ने कहा कि अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है। हमारी तहजीब की अगर हिफाजत 370 और 35ए से होती तो आतंकवाद नहीं होता।

अब नहीं होती पत्थरबाजी

कश्मीर मामलों की जानकार रमीज मखूदमी ने कहा कि अगर आतंकी हिंसा की घटनाओं को दरकिनार किया जाए तो यहां हालात में बदलाव को महसूस किया जा सकता है। शोपियां और पुलवामा में आजकल स्थानीय लड़कों में आगाज, परवाज, दस्तक जैसी योजनाओं के जरिए अपना मुस्तकिबल रोशन करने की होड़ है। कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि लीवर (पहलगाम) जैसे छोटे से गांव में 25 लड़कों ने सेना में भर्ती के लिए फार्म भरा है। इसी गांव से हिजबुल मुजाहिदीन का नंबर-दो गुलाम नबी खान निकला है, जो इस समय पाकिस्तान में बैठा है।

जम्मू-कश्मीर के व्यापारियों को दोहरे टैक्स की मार से मिली मुक्ति

जासं, जम्मू : जम्मू कश्मीर को 370 और 35ए की बेड़ियों से मुक्ति मिलने के दो साल के अंतराल में कई सुखद बदलाव हुए। इनमें जम्मू-कश्मीर में बाधा मुक्त व्यापार की नींव भी मजबूत हुई है। दो साल पहले जिस जम्मू-कश्मीर में अन्य राज्यों से व्यापारी कारोबार करने नहीं आते थे, वहां आज बाजार का दायरा बढ़ा है, जिससे उपभोक्ताओं को भी बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के प्रवेशद्वार लखनपुर में लगने वाला टोल टैक्स व्यापार के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन था। जब तक जम्मू-कश्मीर में वैल्यू एडिड टैक्स (वैट) प्रणाली लागू थी, तब तक तो किसी तरह कामकाज चल रहा था, लेकिन पहली जुलाई 2017 को केंद्र सरकार ने एक दर्जन से अधिक केंद्रीय व राज्य करों को समाप्त कर वन-नेशन, वन-टैक्स के रूप में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया था, लेकिन जीएसटी लखनपुर पहुंच कर दम तोड़ देता था।

जागरण विशेष

चादर पर उकेरा श्रीनगर का भूगोल, संस्कृति और पर्यटन

दस्तकार मकबूल जान ने कश्मीरी कला पेपरमाशी को दिया नया रूप, अपने शहर के बाद अब चादर पर बना रहे पूरी कश्मीर घाटी की तस्वीर

रजिया नूर • श्रीनगर

इतिहास अमूमन कागज पर लिखा जाता है, लेकिन क्या आपने किसी को कपड़े की चादर पर रंगों से वर्तमान और इतिहास उकेरते देखा है। कश्मीर के एक दस्तकार ने यह कर दिखाया है। उसने कपड़े की चादर पर रंगों से श्रीनगर शहर का मुकम्मल नक्शा उतारकर सबको चकित कर दिया है। नक्शा ऐसा कि चादर पर एक नजर डालते ही इस ऐतिहासिक शहर का भूगोल, यहां की सभ्यता, कला व संस्कृति, पर्यटनस्थल, यहां तक कि प्रसिद्ध डल झील में तैरते शिकारों का हसीन मंजर आपकी आंखों के सामने घूम जाता है।

लगा एक साल का वक्त: श्रीनगर शहर के लालबाजार इलाके के रहने वाले 49 वर्षीय दस्तकार मकबूल जान को चादर पर श्रीनगर की तस्वीर बनाने में एक साल का वक्त लगा। उनका दावा है कि ऐसा करने वाले वह वादी के पहले दस्तकार हैं। अक्सर पेपरमाशी कागज या गत्ते पर की जाती है। उन्होंने इसे कपड़े की चादर पर किया है। आज (पांच अगस्त) को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के दो साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मकबूल का यह तोहफा और भी खास हो जाता है। पूरे श्रीनगर शहर की तस्वीर आसानी से बन सके इसके लिए दस्तकार मकबूल जान ने सात मीटर लंबे और पांच मीटर चौड़े कपड़े से खासतौर पर यह चादर बनवाई। दैनिक जागरण के साथ बातचीत में मकबूल जान ने कहा कि उन्हें यह विचार एक म्यूजियम में मिला। जान ने कहा कि म्यूजियम में किसी ने कपड़े पर श्रीनगर शहर की ऐतिहासिक दरगाह हजरतबल, खानकाह जामिया मस्जिद को सुई-धागे से उकेरा था। कपड़ा बहुत पुराना होने के चलते इस पर दरगाहों की तस्वीरें भी ठीक से दिख नहीं रही थीं। उसी वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पेपरमाशी का दस्तकार हूं। मैं भी कपड़े पर अपने श्रीनगर शहर का नक्शा तैयार करूंगा। मैंने पिछले साल कोरोना लाकडाउन के दौरान जुलाई से काम करना शुरू कर दिया। शहर के नक्शे को कपड़े पर उतारने के लिए मैंने कुछ किताबों की मदद ली और आज मैं 15 लाख आबादी वाले अपने पूरे शहर को इस कपड़े की चादर पर समेटने में कामयाब हो गया।

संसद में कलाकृति पहुंचाने का सपना: जान ने कहा कि मैं प्रतिदिन दो से तीन घंटे अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करता था और मुझे खुशी है कि आज मैं इसे पूरा कर पाया हूं। अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे इस प्रोजेक्ट को देखा है, उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना है कि मेरी यह कलाकृति एक दिन संसद तक पहुंच जाए।

कई बार किए जा चुके सम्मानित: मकबूल जान को पेपरमाशी कला के दिग्गज दस्तकारों में गिना जाता है। इस कला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। जान को वर्ष 2007 में पोटरी व ग्लास पेंटिंग प्रतियोगिता में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए साउथ एशिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

कला को बढ़ावा देना पहला मकसद: मकबूल जान ने कहा कि मेरा अहम मकसद पेपरमाशी की कला को एक नई दिशा देना है। पेपरमाशी हमारी वादी की एक मशहूर पारंपरिक व प्राचीन हस्तकला है और बहुत से दस्तकार इस कला के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी पेपरमाशी की इस नई कला से जुड़े और इसमें अपना भविष्य बनाए।

कश्मीर की पुरानी कला है पेपरमाशी

पेपरमाशी कश्मीर की बहुत पुरानी कला है। इसमें पहले पेपर या गत्ते को पानी में डालकर रख दिया जाता है। बाद में उसे निकालकर सुखाया जाता है। इसके बाद कागज व गत्ते को काट-छांटकर आकार दिया जाता है। फिर उसपर रंगों से खूबसूरत पेंटिंग की जाती है। इससे पेन होल्डर, गमले, ज्वेलरी बाक्स आदि तैयार किए जाते हैं। इस सामान की बिक्री ज्यादातर श्रीनगर के डलगेट इलाके में होती है। इसे तैयार करने वाले ज्यादातर दस्तकार श्रीनगर के लालबाजार और हबल इलाके में रहते हैं।

श्रीनगर के लालबाजार इलाके में रहने वाले दस्तकार मकबूल जान ने चादर पर रंगों से अपने शहर की तस्वीर उकेर दी • जागरण

रंग और ब्रश से यूं संजोया श्रीनगर

चादर पर श्रीनगर की जामिया मस्जिद, शंकराचार्य मंदिर, दरगाहें, झेलम नदी, डल झील, शिकारे, चिनार के पेड़, डाउनटाउन का गुंबद समेत छोटे-छोटे स्थानों को भी उभारा गया है, जिनसे यह शहर पहचाना जाता है। चादर को पेंट करने में हल्के नीले व गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। जान अब कश्मीर को चादर पर उकेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अगला मिशन विश्व का नक्शा होगा। हालांकि दुनिया का नक्शा कपड़े पर उतारना आसान बात नहीं, लेकिन मैंने इरादा कर लिया है और मैं यह एक दिन करके दिखाऊंगा।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

डीआइसीजीसी संशोधन विधेयक राज्यसभा से पास

नई दिल्लीः राज्यसभा ने डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (डीआइसीजीसी) संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद बैंकों में खाताधारकों की पांच लाख रुपये तक की रकम सुरक्षित हो जाएगी, जो सीमा वर्तमान में एक लाख रुपये है। बैंक के बंद होने की स्थिति में ग्राहकों को उनका पांच लाख रुपये तक जमा रकम 90 दिनों के भीतर मिल जाएगी। (प्रेट्र)

देश में कम से कम तीन निजी टेलीकाम कंपनियां होनी ही चाहिए। इस संकटग्रस्त सेक्टर को सरकार से तत्काल मदद की जरूरत है।

– गोपाल विट्टल, सीईओ, भारती एयरटेल

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
54,369.77	16,246.85	₹46,992	₹66,926	₹74.19	$ 72.28
546.41	128.05	₹123	₹766	₹0.09	

हीरों के आभूषण पर तनिष्क दे रही 20 फीसद तक छूट

नई दिल्ली, (वि.): देश की अग्रणी ज्वेलरी रिटेल चेन तनिष्क ने 'लिटिल बिग मोमेंट्स' के तहत आभूषणों की श्रेणी लांच की है। हीरे के इन आभूषणों के मूल्य पर कंपनी 20% तक की छूट दे रही है। यह आफर सीमित समय के लिए शर्तों के साथ है। इस बारे में टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में तनिष्क की एजीएम (मार्केटिंग) अंजनी कृष्णास्वामी ने कहा, लोग अक्सर जिंदगी में बड़ी खुशियों की तलाश में फिरते रहते हैं, जबकि छोटी-छोटी खुशियां उनके आसपास होती हैं और वे उसे पकड़ नहीं पाते। अगर उन मोमेंट्स को पकड़ लें तो जिंदगी उमंग से भर जाती है। इस नई श्रेणी के तहत कंपनी ने उन्हीं छोटी-छोटी खुशियों वाले पलों के लिए हीरे के आकर्षक आभूषण पेश किए हैं। तनिष्क के लिटिल बिग मोमेंट्स के पीछे का मकसद जिंदगी की उन छोटी-छोटी खुशियों को गले लगा सकते हैं, जो उनके आसपास होते हैं और जिन पर नजर नहीं जाती।

वोडा आइडिया के ग्राहकों पर संकट

जियो और एयरटेल के पास इन 27 करोड़ ग्राहकों को संभालने की क्षमता नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदार आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला के पत्र की बातें सामने आने से टेलीकाम सेक्टर में जो खलबली मची है, उसका अंत नजर नहीं आ रहा है। यदि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो उसके 27 करोड़ से अधिक ग्राहकों को बड़ी दिक्कत होगी। बुधवार को भी दूरसंचार विभाग (डीओटी) के भीतर टेलीकाम सेक्टर के लिए एक बड़े राहत पैकेज को लेकर विमर्श का दौर जारी रहा। दैनिक जागरण को यह जानकारी मिली है कि पिछले एक माह के दौरान इस बारे में डीओटी के अधिकारियों की वित्त मंत्रालय के साथ भी बैठक हो चुकी है।

इस पैकेज के तहत कंपनियों के उपयोग में नहीं आने वाला स्पेक्ट्रम वापस लेने, बैंक गारंटी घटाने व दूसरे शुल्कों में कमी जैसे कुछ फैसलों की उम्मीद है, जो वोडाफोन को काफी राहत दे सकती है। साथ ही आरबीआइ के साथ भी विमर्श चल रहा है ताकि टेलीकाम सेक्टर पर 1.6 लाख करोड़ बकाया बैंकिंग कर्ज के भुगतान में राहत दी जाए। पूर्व में केंद्रीय बैंक ऐसी राहत कुछ दूसरे संकटग्रस्त उद्योगों को दे चुका है। इन घटनाक्रमों के बीच वोडाफोन आइडिया की लंदन स्थित मूल प्रमोटर कंपनी वोडाफोन चुप्पी साधे हुए है। कंपनी भारतीय कारोबार में नया निवेश करने की संभावना से इन्कार कर चुकी है। डीओटी के अधिकारियों का कहना है कि वोडाफोन को बचाना बहुत जरूरी है। अधिकारी यह भी मान रहे हैं कि भारत जैसे देश में तीन बड़ी दूरसंचार कंपनियां होनी चाहिए। सरकार जानती है कि वोडाफोन आइडिया के बंद होने की स्थिति में विपक्ष इसे केंद्र की आर्थिक नीतियों की नाकामी के तौर पर प्रचारित कर सकता है।

ग्राहकों को ऐसे होगी दिक्कत

माना जाता है कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के पास इतनी व्यापक ढांचागत व्यवस्था नहीं है कि वे वोडाफोन आइडिया के सभी ग्राहकों को समाहित कर सकें। मौजूदा नियम के मुताबिक, किसी भी सर्किल में किसी एक टेलीकाम कंपनी के पास 50 फीसद से ज्यादा ग्राहक नहीं रह सकते। ऐसे में वोडाफोन अगर बंद होती है तो यह सुनिश्चित करना मुश्किल होगा कि इन दोनों कंपनियों में किसी एक के पास 50 फीसद से कम ग्राहक हों।

कुमार मंगलम बिड़ला ने छोड़ा चेयरमैन पद

नई दिल्ली, प्रेट्र : कुमार मंगलम बिड़ला ने बुधवार को वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआइएल) ने शेयर बाजारों को बताया कि कुमार मंगलम बिड़ला बुधवार को कारोबारी अवधि के बाद से कंपनी के निदेशक और गैर-कार्यकारी चेयरमैन नहीं रहेंगे। उनकी जगह हिमांशु कपानिया को वोडाफोन वीआइएल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कपानिया पहले आदित्य बिड़ला सेल्युलर के एमडी व सीईओ थे। जून के आखिरी दिनों में बिड़ला ने सरकार को पत्र लिख वीआइएल में आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिस्सेदारी उसे सौंपने का आग्रह किया था। उन्होंने लिखा था, मौजूदा वित्तीय दबाव में वह कंपनी को चलाने में सक्षम नहीं हैं।

कुमार मंगलम बिड़ला

चालू खाता नियम 31 अक्टूबर से होगा लागू, बढ़ाई गई अवधि

जाब्यू, नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने बुधवार को अपने उस फैसले को लागू करने की तिथि इस वर्ष पहली अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी, जिसके तहत ग्राहकों को एक ही बैंक में लोन और कर्ज खाता रखने को कहा गया है। इस फैसले के तहत बैंकों को कहा गया है कि वे उन्हीं ग्राहकों का चालू खाता खोलें, जो उनसे कर्ज या ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेते हैं। आरबीआइ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह इस नियम में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं है और बैंकों को इसे लागू करना ही होगा। हालांकि इस नियम पर उद्यमी सवाल उठा रहे हैं।

आरबीआइ ने यह नियम पिछले वर्ष ही जारी किया था, जिसे इस वर्ष जनवरी से लागू किया गया है। बैंकों के स्तर पर इस नियम को लागू करने में काफी कोताही दिखाई गई। भारतीय बैंक संघ (आइबीए) भी अपने स्तर पर आरबीआइ से इसमें बदलाव के लिए बात करता रहा है।

एमएसएमई और बैंकों को दिवालिया कानून से फायदा

वित्त मंत्री ने संशोधित दिवालिया कानून को लचीला, किफायती और अधिक परिणाम देने वाला बताया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्लीः संशोधित दिवालिया कानून से एमएसएमई के साथ बैंकों को भी लाभ मिलेगा। इसके तहत एमएसएमई 10 लाख रुपये से अधिक के डिफाल्ट पर एनसीएलटी में जाने से पहले ही कर्जदाता के साथ मिलकर बंदोबस्त (सेटलमेंट) का खाका तैयार कर सकेंगे, वहीं बैंक भी अपने बकाये की अधिक से अधिक रिकवरी कर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित आइबीसी नियम को लचीला, किफायती और पहले के मुकाबले अधिक परिणाम देने वाला करार दिया है। यह संसद से पारित हो चुका है। अध्यादेश के रूप में यह पहले से लागू था।

नए कानून के तहत 10 लाख से अधिक के डिफाल्ट पर बैंक और वह कंपनी नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में जाने से पहले आपस में यह तय कर लेंगे कि कर्ज चुकाने के लिए किस सामान को किसके हाथों व कितने में बेचना है। यह भी एनसीएलटी में जाने से पहले निर्धारित होगा कि कौन उनकी कंपनी की संपत्ति को खरीदने के लिए तैयार है और उससे कितनी रकम की भरपाई होगी। कर्जदाता और बैंक आपस में एक पैकेज तैयार कर लेंगे कि इस मामले को किस तरह से सेटल करना है। यह सब निर्धारित करने के बाद एमएसएमई और बैंक एनसीएलटी में जाएंगे। चैंबर आफ इंडियन माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के प्रेसिडेंट मुकेश मोहन गुप्ता ने बताया कि निर्धारित समय में सारी प्रक्रिया पूरी होने से एमएसएमई को इसका लाभ मिलेगा और उनकी परेशानी भी कम होगी।

सेंसेक्स पहली बार 54,000 के पार

मुंबई, प्रेट्र : कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों, नए खुदरा निवेशकों में निवेश की बढ़ती भूख और विदेशी बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों के दम पर घरेलू शेयर बाजारों में रिकार्ड का सफर जारी है। पिछले कारोबारी सत्र में रिकार्ड स्तर पर बंद होने वाला बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को भी एक नया बेंचमार्क बनाने में कामयाब रहा। दिन के कारोबार में सेंसेक्स में 546.41 अंक यानी 1.02 फीसद उछाल के साथ 54,369.77 के नए रिकार्ड पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला निफ्टी भी 128.05 अंक यानी 0.79 फीसद मजबूती के साथ 16,246.85 की नई ऊंचाई पर स्थिर हुआ।

देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के लाभ में 55 फीसद से अधिक की वृद्धि को देख निवेशकों ने बैंकिंग और फाइनेंस के शेयरों पर जमकर दांव खेला। सेंसेक्स पैक में बुधवार को सबसे ज्यादा 4.77 फीसद का फायदा एचडीएफसी के शेयरों में दर्ज किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एसबीआइ, एचडीएफसी बैंक व एक्सिस बैंक के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई। तेजी के माहौल में भी टाइटन, नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, मारुति सुजुकी व भारती एयरटेल के शेयर 2.14 फीसद तक टूट गए।

रिकार्ड

- बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टाक्स में बुधवार को निवेशकों ने की जमकर खरीदारी
- 54,369.77 के नए रिकार्ड पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी नई ऊंचाई पर स्थिर हुआ

डिजिटल प्लेटफार्म का हाथ थामे बढ़े छोटे उद्यमी

दुनियाभर में फैली महामारी ने लोगों के जीने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव कारोबार के तरीके में भी देखा गया है। लोकल सर्किल्स के हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक, महामारी के दौर में छोटे उद्यमियों ने तेजी से डिजिटल प्लेटफार्म को अपनाया है। बड़े पैमाने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का मानना है कि डिजिटल होने से उनका कारोबार बढ़ा।

लाकडाउन ने बढ़ाई अहमियत

महामारी के कारण पिछले साल देशव्यापी लाकडाउन लगा था। इस दौरान कई कारोबारी गतिविधियां बंद रही थीं। इस साल अप्रैल-मई में भी कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। ऐसे में किसी कारोबार के संचालन में इस बात की बड़ी भूमिका देखी गई कि वह कितना तेजी से डिजिटल माध्यम अपनाने में सक्षम है।

आनलाइन ने बढ़ाई कमाई

उद्यमियों का कहना है कि आनलाइन प्लेटफार्म पर जाने से पिछले साल के मुकाबले उनकी कमाई बढ़ी है।

- 18% कमाई पिछले साल से कम हुई
- 18% कमाई में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई
- 13% शून्य से 50 फीसद बढ़ी कमाई
- 28% 100 से 500 फीसद बढ़ी कमाई
- 23% 50 से 100 फीसद बढ़ी कमाई

ई-कामर्स की बड़ी हिस्सेदारी

डिजिटल प्लेटफार्म पर एमएसएमई के लिए ई-कामर्स पोर्टल मददगार साबित हुए हैं।

- 8% एमएसएमई ने डिस्ट्रीब्यूटर्स/रिटेलर्स को सामान बेचा और वहां से ग्राहकों तक सामान पहुंचा
- 61% एमएसएमई ने ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से बिक्री की
- 31% ने अपनी वेबसाइट से किया काम

जागरण ग्राफिक्स

चीनी उद्योग पर संकट गहराने के आसार

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली

देश के अग्रणी गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव को देखते हुए गन्ना के उचित व लाभकारी मूल्य में वृद्धि होनी तय मानी जा रही है। चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में भी पिछले ढाई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई है। दूसरी ओर घरेलू बाजार में चीनी का स्टाक पहले से ही बढ़ा हुआ है, जिससे जिस बाजार में इसके मूल्य में सुधार की संभावना कम ही है। चुनावी वर्ष में गन्ना किसानों के भुगतान का संकट भी इससे गहरा सकता है। गन्ने का लगभग 19,000 करोड़ का एरियर चीनी मिलों पर बकाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया लगभग 40 फीसद है। चुनाव से ठीक पहले सरकार पर इसकी भरपाई का दबाव बढ़ सकता है।

गन्ना वर्ष, 2020 में गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी, जिससे चीनी की लागत 1.50 रुपये प्रति किलो बढ़ गई। इसके अलावा स्टील के मूल्य में आई भारी तेजी, मिलों के रखरखाव व अन्य खर्च बढ़ना का सीधा असर चीनी की उत्पादन लागत पर पड़ा है। इसके बावजूद फरवरी, 2019 के बाद चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आगामी पहली अक्टूबर से नया चीनी वर्ष चालू हो जाएगा। चीनी उद्योग को लगता है कि गन्ना एफआरपी में पांच रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत चीनी की एमएसपी में वृद्धि का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है। देश में इस वर्ष पहली अक्टूबर को चीनी का कैरीओवर स्टाक 87 लाख टन रहेगा, जो सामान्य से लगभग 30 लाख टन ज्यादा है। वहीं, आगामी गन्ना वर्ष में 3.10 करोड़ टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

आशंका

- लाभकारी मूल्य का बढ़ना तय, एमएसपी पर असमंजस
- गन्ना एरियर के भुगतान का बढ़ सकता है दबाव
- उप्र के गन्ना किसानों का बकाया लगभग 40 फीसद है

निर्यात नीति की प्रतीक्षा

जानकारों के मुताबिक सरकार को जल्द चीनी निर्यात पर नीतियों का एलान कर देना चाहिए। एशियाई देशों में चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक थाईलैंड है। वैश्विक बाजार में वहां की चीनी जनवरी में पहुंचती है। भारतीय मिलों की चीनी के लिए अक्टूबर से जनवरी तक का समय निर्यात के लिए मुफीद हो सकता है। वैश्विक बाजार में चीनी का भाव बढ़ा हुआ है, जिसका फायदा लिया जा सकता है। वैश्विक बाजार में ब्राजील की चीनी अप्रैल में पहुंचेगी, यह समय भारतीय निर्यातकों के लिए बेहतर होगा।

राष्ट्रीय फलक

वनातु सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े तथ्य सीबीआइ को मुहैया करा दिए

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : प्रशांत महासागर के वनातु द्वीप सरकार ने कोयला और गाय तस्करी के आरोपित तथा तृणमूल कांग्रेस नेता विनय मिश्रा के पासपोर्ट संबंधित तथ्य ई-मेल के जरिये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को मुहैया करा दिए हैं। सीबीआइ का दावा है कि विनय मिश्रा वनातु में छिपा हुआ है तथा उसने वहां की नागरिकता भी ले ली है। विनय मिश्रा के माता पिता भी देश छोड़ चुके हैं। उन्होंने कैरेबियाई देश ग्रेनेडा में शरण ली है।

दरअसल, सीबीआइ ने वनातु प्रशासन से विनय मिश्रा के पासपोर्ट संबंधी जानकारी मांगी थी। इसके बाद ही वहां के प्रशासन ने पासपोर्ट संबंधी तथ्य मुहैया कराकर सीबीआइ की सहायता की है। सीबीआइ ने विनय के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से फिर आवेदन किया है। दिसंबर 2020 में विनय देश छोड़कर चला गया था। गौरतलब है कि वनातु वीजा मुक्त देश है। भारत के साथ उसकी कोई प्रत्यर्पण संधि भी नहीं है।

गन्ना किसानों के बकाए पर केंद्र और 11 राज्यों से जवाब तलब

नई दिल्ली, प्रेट्रः सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार, उप्र,महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु से जवाब मांगा। साथ ही चार कंपनियों बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, इंडियन शुगरमिल्स एसोसिएशन, केन एग्रो एनर्जी (इंडिया) लिमिटेड और इंडियन सुक्रोज लिमिटेड से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व लोकसभा सांसद राजू अन्ना शेट्टी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के समक्ष शेट्टी के वकील आनंद ग्रोवर ने कहा, गन्ना आपूर्तिकर्ताओं को देश भर में आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर उनके बकाए का भुगतान किया जाना चाहिए, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश में भी कहा गया है। पीठ ने ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद कहा, 'नोटिस जारी करें। इसे तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।' ग्रोवर ने उन राज्यों की ओर ध्यान दिलाया जो किसानों का भुगतान करने में बुरी तरह चूक करते रहे हैं। वरिष्ठ वकील ने आरोप लगाया कि चीनी मिलें धन का दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वे किसानों को भुगतान नहीं कर रही हैं और इसलिए किसानों के बकाया की वसूली के लिए उनका चीनी का भंडार जब्त कर लेना चाहिए। ग्रोवर ने कहा कि किसानों का कुल बकाया करीब 18,000 करोड़ रुपये है।

क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कानून : उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति अधिनियम के अनुसार, गन्ना उत्पादकों को 14 दिनों के भीतर उनकी बकाया राशि करना अनिवार्य है। निर्धारित समय अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

तीन मासूम बच्चियों को छोड़ पंजाब चले गए माता-पिता

जागरण संवाददाता, जमुई

बिहार के जमुई जिले का मामला, छह माह पहले की घटना

आज हर क्षेत्र में बेटियां नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। बावजूद, कुछ लोग दकियानूसी सोच के कारण बेटे-बेटी के बीच फर्क करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बिहार के जमुई जिले के दीघरा गांव का है। वहां के अनिल बिंद तीन मासूम बच्चियों को छोड़कर पत्नी सहित देवी व दो बेटों के साथ पंजाब चले गए।

पुलिस के पास मंगलवार शाम को यह मामला पहुंचा। माता-पिता छह माह पूर्व तीन बच्चियों को छोड़कर चले गए थे। तब से तीनों भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हैं। लोगों ने बताया कि अनिल बिंद को पांच पुत्रियां व दो पुत्र हैं। दो पुत्रियों की शादी हो चुकी है। बाकी तीन पुत्रियों में वर्षा (12), आशा (09) व शिवानी (5) समेत इनके दोनों भाई माता-पिता के साथ रहते थे। शराबी पिता अनिल बिंद ने अपनी जरूरत के लिए सारी जमीन बेच दी। घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो छह माह पूर्व तीनों पुत्रियों को छोड़कर वह पंजाब चले गए। वे दोनों पुत्रों को साथ ले गए। मंगलवार की शाम तीनों बच्चियां भीख मांगते-मांगते लक्ष्मीपुर बाजार पहुंच गईं। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

इसके बाद पुलिस तीनों बहनों को थाना ले आई। पूछताछ में बड़ी बहन वर्षा ने पुलिस को बताया कि पापा-मम्मी ने तीनों बहनों को दवा लाने के लिए बाजार जाने को कहा। इसके बाद बाकी लोग पंजाब चले गए। कोई खाना नहीं दे रहा, तो मजबूरी में भीख मांगनी पड़ रही है। बाद में थानाध्यक्ष ने मामले की जानकारी चाइल्डलाइन को दी। तीनों बहनों को चाइल्डलाइन को सौंप दिया गया। चाइल्डलाइन के सदस्य अभिषेक कुमार व ज्योति कुमारी ने बताया कि तीनों बच्चियों को बालिका सुधार गृह, बेगूसराय भेजा जाएगा।

बिहार में 50 बीघा जमीन के विवाद में छह की हत्या

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ: बिहार में नालंदा जिले के छबिलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में देवी स्थान के पास बुधवार की शाम विवादित खेतों को जोतने से मना करने पर छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक ही परिवार के पिता व दो पुत्र शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी हरि प्रसाथ व डीएसपी समेत कई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतकों में लोदीपुर निवासी 60 वर्षीय यदु यादव, उनका 30 वर्षीय पुत्र पिंटू यादव व 25 वर्षीय मधेश यादव, 50 वर्षीय धीरेंद्र यादव तथा 40 वर्षीय शिवल यादव हैं। वहीं घायल 45 वर्षीय वीरेंद्र प्रभाकर उर्फ बिंदा यादव की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। फायरिंग में मारे गए वीरेंद्र प्रभाकर उर्फ बिंदा के पुत्र अतुल को दाएं पैर में गोली लगी है। वहीं इंदु यादव के सिर में गहरी चोट है।

खेल जागरण

भारतीय तेज गेंदबाजों ने कसा इंग्लैंड पर शिकंजा

पहले टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 183 रन पर सिमटी, बुमराह ने चार विकेट झटके

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : जसप्रीत बुमराह की अगुआई में भारतीय तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के आगे नाटिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 183 रन पर ढेर हो गई। बुमराह ने 46 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि मुहम्मद शमी (3/28), शार्दुल ठाकुर (2/41) व मुहम्मद सिराज (1/38) भी विकेट लेने में सफल रहे। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। रूट ने 108 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से सर्वाधिक 64 रन बनाए। इंग्लैंड के चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। भारतीय टीम में एकमात्र स्पिनर के रूप में रवींद्र जडेजा को शामिल किया गया, जिन्होंने सिर्फ तीन ओवर डाले। जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना नुकसान के 21 रन बनाए थे। रोहित शर्मा व केएल राहुल नौ-नौ रन बनाकर डटे थे।

रूट ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बुमराह ने पहले ओवर में ही रोरी बर्न्स (0) को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डोम सिब्ले (18) और जैक क्राउले (27) के बीच 42 रन की साझेदारी हुई, जिसे सिराज ने क्राउले को विकेट के पीछे पंत के हाथों कैच कराकर तोड़ा। भोजनकाल के बाद सिब्ले भी शमी की गेंद पर शार्ट मिडविकेट पर राहुल के हाथों लपके गए। अब क्रीज पर रूट और जानी बेयरस्टो (28) थे। दोनों के बीच 72 रन की अच्छी साझेदारी देखने को मिली। इस दौरान रूट ने 89 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, लेकिन कुछ देर बाद ही शमी ने बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड का स्कोर 138 रन पर चार विकेट कर दिया।

चाय के बाद ओवर की बाकी चार गेंद डालने आए शमी ने अंतिम गेंद पर डैन लारेंस (0) को विकेट के पीछे कैच करवाकर चलता किया। इसके बाद इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। 160 रन टीम ने जोस बटलर (0), रूट, ओली रोबिंसन (0) और स्टुअर्ट ब्राड (4) के विकेट भी गंवा दिए। बटलर और ब्राड को बुमराह ने पवेलियन भेजा, जबकि रूट व रोबिंसन को शार्दुल ने चलता किया। अंत में सैम कुर्रन (नाबाद 27) व जेम्स एंडरसन (1) ने अंतिम विकेट के लिए 23 रन जोड़े, लेकिन बुमराह ने एंडरसन को बोल्ड कर पारी का अंत किया।

संक्षिप्त स्कोर बोर्ड

इंग्लैंड (पहली पारी) : 183 (65.4 ओवर), **रूट :** 64 रन, 128 गेंद, 11 चौके, **बुमराह :**4/46, **भारत (पहली पारी):** 21/0 (13 ओवर)

> मुझे लगता है कि अगर आप अश्विन को खिलाते तो पुछल्ले बल्लेबाज ज्यादा हो जाते। आपको नहीं पता कि कितनी स्पिन गेंदबाजी इस्तेमाल की जाएगी। जडेजा (जडेजा) ने चाय तक 50 ओवर में से तीन में गेंदबाजी की। इसलिए आप जितने ओवर स्पिन में इस्तेमाल करोगे, जडेजा इन ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं। और हमें इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच जाना चाहिए कि जडेजा को एकमात्र स्पिनर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप विदेशों के प्रदर्शन को देखो तो जडेजा बेहतर बल्लेबाज रहे हैं। – **हरभजन सिंह**, पूर्व भारतीय स्पिनर

टी-20 विश्व कप में 24 अक्टूबर को हो सकता है भारत-पाक मुकाबला

नई दिल्ली, प्रेट्र : चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 विश्व कप की भिड़ंत 24 अक्टूबर को होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद टूर्नामेंट का अधिकृत कार्यक्रम कुछ दिनों में जारी करेगी। आइसीसी अंतिम कार्यक्रम पर फैसला करने से पहले सामान्य तौर पर कार्यक्रम के दो से तीन सेट रखती है, लेकिन भारत-पाक मुकाबले की लोकप्रियता को देखते हुए यह मैच हफ्ते के अंत में कराया जा सकता है। आइसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने कहा, 'अभी तक 24 अक्टूबर के विकल्प की संभावना है, क्योंकि पिछले हफ्ते के क्वालीफाइंग मैच 17 अक्टूबर से ओमान के मस्कट में शुरू होंगे। इसलिए जब मुख्य राउंड रविवार के मुकाबले खेले जाएंगे तो भारत-पाक मैच से शुरुआत करना अच्छा होगा, जो टीआरपी के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा।' भारत और पाकिस्तान को ग्रुप-दो में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है।

12 और 13 साल की लड़कियों ने जीते ओलिंपिक पदक

ओलिंपिक डायरी

टोक्यो, एपी : ओलिंपिक में पहली बार खेली जा रही स्केटबोर्डिंग स्पर्धा में कई छोटे-छोटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। यही कारण है कि 12 वर्ष की कोकोना हिराकी रजत पदक जीतने के साथ जापान की सबसे युवा ओलिंपिक पदक विजेता बनीं तो इसी स्पर्धा का कांस्य पदक ब्रिटेन की 13 वर्ष की स्काय ब्राउन ने अपने नाम किया। ब्राउन भी ब्रिटेन के लिए ओलिंपिक पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। 1896 में एथेंस में शुरू हुए आधुनिक ओलिंपिक में 10 वर्ष की उम्र में ग्रीक के दिमित्रियोस लाउंड्रास ने जिम्नास्ट स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था।

स्केटबोर्डिंग की महिलाओं के पार्क इवेंट का स्वर्ण पदक 19 वर्षीय जापान की साकुरा योसोजुमी ने 60.09 अंक के साथ जीता और 60 अंक पार करने वाली वह अकेली खिलाड़ी रहीं। 59.04 अंक के साथ दूसरे स्थान पर कोकोना तो तीसरे स्थान पर 56.47 अंक के साथ ब्राउन रहीं।

ब्राजील की मार्सेला ने महिला मैराथन तैराकी का स्वर्ण जीता : ब्राजील की मार्सेला कुन्हा ने ओलिंपिक में महिला 10 किमी मैराथन तैराकी स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया। मार्सेला ने एक घंटा 59 मिनट और 30.8 सेकेंड का समय लिया। उन्होंने नीदरलैंड्स की गत चैंपियन शेरोन वेन रोवेनडाल को सिर्फ 0.9 सेकेंड के अंतर से पछाड़ा। शेरोन ने एक घंटा 59 मिनट और 31.7 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया। कांस्य पदक आस्ट्रेलिया की केरीना ली के नाम रहा, जिन्होंने एक घंटा 59 सेकेंड और 32.5 सेकेंड का समय लिया। अपने तीसरे ओलिंपिक में पहला पदक जीतने वाली मार्सेला पांच साल पहले रियो ओलिंपिक में 10वें, जबकि 2008 बीजिंग खेलों में पांचवें स्थान पर रही थीं।

अमेरिका की सिडनी ने विश्व रिकार्ड से जीता स्वर्ण

अमेरिका की सिडनी लाफलिन ने अपना ही विश्व रिकार्ड तोड़ते हुए ओलिंपिक की महिला 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकार्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। लाफलिन ने 51.46 सेकेंड का समय लिया। उनकी हमवतन दलीलाह मुहम्मद ने 51.58 सेकेंड के साथ रजत पदक जीता। लाफलिन ने जून में 51.90 सेकेंड का विश्व रिकार्ड बनाया था। इससे पहले दलीलाह ने 2019 में दो बार विश्व रिकार्ड बनाया था और उसी साल विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता था। नीदरलैंड्स की फेम्के बोल ने 52.03 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।

बेलारूस की धाविका क्रिस्टसीना विएना हुई रवाना : बेलारूस की ओलिंपिक धाविका क्रिस्टसीना सिमानोस्काया विएना रवाना होने के लिए बुधवार को टोक्यो से फ्लाइट में सवार हो गईं। क्रिस्टसीना और टीम के अधिकारियों के बीच सार्वजनिक टकराव देखने को मिला था। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि क्रिस्टसीना आस्ट्रिया में ही रहेंगी या नहीं। कई देशों ने इस खिलाड़ी को मदद की पेशकश की थी। पोलैंड ने मानवीय आधार पर उन्हें वीजा जारी किया है। क्रिस्टसीना ने कहा था कि उनकी टीम के अधिकारियों ने कहा था कि स्वदेश लौटने पर उन्हें सजा भुगतनी होगी।

फ्लाइट में खिलाड़ियों ने मचाया उत्पात : आस्ट्रेलिया के रग्बी और फुटबाल खिलाड़ियों ने टोक्यो से सिडनी लौटने वाली फ्लाइट में जमकर शराब पी और बदसलूकी भी की, जिसकी देश के ओलिंपिक दल प्रमुख इयान चेस्टरमैन ने जमकर निंदा की है।

खेलों से नीरस जीवन सरस बनता है

बेलगाम हंगामा

संसद का मानसून सत्र जिस तरह विपक्षी दलों के हंगामे का शिकार है, उससे यही लगता है कि विपक्ष की संसद चलाने में कहीं कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। यदि विपक्ष अपने रवैये का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर उचित यह होगा कि संसद के इस सत्र को समय से पहले समाप्त करने पर विचार किया जाए, क्योंकि हंगामे से बाधित संसद सरकारी धन की बर्बादी का कारण बन रही है। विपक्षी दलों को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे संसद को ठप करके सरकारी धन को बर्बाद करें। इससे विचित्र और कुछ नहीं कि विपक्षी दलों के सांसद संसद में पहले ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि सदन न चलने पाए और जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वे उस पर हंगामा मचाते हैं। गत दिवस राज्यसभा में ऐसा ही हुआ। जब आसन के समक्ष हंगामा मचाने और तख्तियां लहराने के कारण तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को दिन भर के लिए निलंबित किया गया तो उन्होंने सदन के प्रवेश द्वार के पास विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह चोरी और सीनाजोरी का शर्मनाक उदाहरण है। इसी तरह का उदाहरण तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद शांतनु सेन ने दिया था, जिन्हें आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने के कारण संसद के इस सत्र से निलंबित किया गया था। वह अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय अपने साथ हुए कथित अन्याय का रोना रो रहे थे।

विपक्षी सांसदों के व्यवहार से यही पता चलता है कि उनमें संसद की गरिमा और उसके नियम-कानूनों के प्रति कहीं कोई सम्मान नहीं रह गया है। कायदे से ऐसे सांसदों के खिलाफ और अधिक कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि कोई नजीर कायम हो सके और उस तरह के असंसदीय-अशोभनीय दृश्य देखने को न मिलें, जैसे मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में लगातार देखने को मिल रहे हैं। इससे दयनीय और दुखद और कुछ नहीं हो सकता कि विपक्षी सांसद हंगामा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए अतिरिक्त श्रम कर रहे हैं। वे किस्म-किस्म के नारे लिखी तख्तियां सदन के भीतर ले जाते हैं और फिर यह कोशिश करते हैं कि वे टीवी कैमरों में कैद हो जाएं। संसद की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की शुरुआत करते समय यह सोचा गया था कि इससे संसद सदस्य सदन के भीतर कहीं अधिक गंभीरता और जिम्मेदारी का परिचय देंगे, लेकिन अब ठीक इसके उलट देखने को मिल रहा है। सांसद आम जनता से जुड़े अथवा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को सदन में उठाने की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन अपनी सारी ऊर्जा नारेबाजी करने या फिर तख्तियां लहराने में खपा देते हैं।

जातियों में बंटते महापुरुष

देश के यशस्वी-प्रतापी सम्राट रहे मिहिरभोज के नाम पर फरीदाबाद, हरियाणा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने प्रश्न उठा दिया है। यद्यपि उन्हें कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि महापुरुष किसी जाति-समुदाय विशेष के नहीं होते, वे समस्त राष्ट्र के होते हैं, समस्त समाज के होते हैं। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों पर आपत्ति जताई है, जिसमें महापुरुषों को जातीय परिधि में सीमित कर दिया जाता है। मिहिरभोज को गुर्जर समुदाय अपना पूर्वज मानता है। इसी तरह अन्य महापुरुषों को लोग अपने जातीय गौरव से जोड़ लेते हैं। लेकिन यह प्रश्न भी तो उठता है कि सम्राट मिहिरभोज के नाम पर अब तक समाज के सभी वर्गों ने मिलकर कोई आयोजन क्यों नहीं किया? अन्य समुदायों के लोग जो महापुरुषों के नाम पर जातीय गौरव के लिए कार्यक्रम करते हैं, सबपर प्रश्न उठना चाहिए। नयनपाल रावत ने पहल तो अच्छी की है, लेकिन इसके लिए उन्हें व्यापक स्तर पर प्रयास करने होंगे, अन्यथा स्वयं उनपर प्रश्न उठ जाएंगे। यह तो समाज को भी सोचना होगा कि वह सभी महापुरुषों की जयंती का मिलकर आयोजन करे। आयोजक मंडल में केवल वही लोग न हों, जो संबंधित महापुरुष को अपनी जाति से जोड़ते हों। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राजनीतिक दलों के नेता स्वजातीय सम्मेलनों में सगर्व जाते हैं और बड़ी बड़ी क्रांतिकारी उद्घोषणाएं करते हैं। उनका लक्ष्य अपने स्वजातीय मतदाताओं को मत प्राप्त करना होता है, जिसके बल पर वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। ऐसे आयोजनों पर भी प्रश्न उठने चाहिए और किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को नहीं, उस समुदाय की तरफ से ही उठने चाहिए, जो कार्यक्रम कर रहा है। अन्यथा बात नहीं बनने वाली। आप जब तक स्वयं नहीं उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तब तक आप दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन सकते। अच्छा तो यह होगा कि समाज सभी लोग महापुरुषों की जयंती मिलकर मनाए और आयोजन समितियों में सभी वर्ग के लोग हों।

महापुरुष समस्त समाज और राष्ट्र के होते हैं, उन्हें जाति में बांटना नितांत अनुचित है, यह प्रथा बंद होनी चाहिए

अंग्रेजी के आगे भी भविष्य है

एम वेंकैया नायडू

यदि हम अपनी भाषा को नजरंदाज करते हैं तो हम न सिर्फ ज्ञान की एक बहुमूल्य निधि को खो देंगे, बल्कि भावी पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से भी काट देंगे

हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम से ही होती है। हाल में आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कालेजों ने आगामी सत्र से अपने यहां चुने हुए पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए लिया गया ऐसा ऐतिहासिक फैसला है, जिस पर भावी पीढ़ियों का भविष्य टिका है। इसके साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआइसीटीई द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही बीटेक पाठ्यक्रमों को 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, असमिया, पंजाबी और उड़िया भाषाओं में बीटेक विद्यार्थियों के लिए अवसरों का एक नया संसार खोलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा था कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को महत्व दिए जाने से गरीब, ग्रामीण और जनजातीय पृष्ठभूमि से आए मेधावी छात्रों में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। उन्होंने विद्या प्रवेश नाम के नए प्रोग्राम का भी जिक्र किया, जिसका शुभारंभ भी इसी अवसर पर किया गया। इन सराहनीय कदमों का स्वागत होना चाहिए और आगामी कुछ वर्षों में इनका विस्तार भी किया जाना चाहिए, जिससे अपनी मातृभाषा में ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने का लाखों विद्यार्थियों का सपना पूरा हो सके।

प्रगतिशील और दूरदर्शी नई शिक्षा नीति, 2020 में प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा को मातृभाषा में ही दिए जाने पर जोर दिया गया है, जिससे बच्चे की शिक्षा और समझ में सुधार हो। कितने ही अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि वे बच्चे जिनकी अपनी शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में होती है, वे उन बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी अन्य भाषा में हुई हो। यूनेस्को और अन्य संस्थाएं इस पर बल देती रही हैं कि मातृभाषा में सीखना, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने के लिए तथा बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए भी आवश्यक है। दुर्भाग्य से कुछ अभिभावक और शिक्षक बिना जाने-बूझे अंग्रेजी के वर्चस्व पर ही बल देते हैं। परिणामस्वरूप बच्चे की अपनी ही मातृभाषा स्कूल में दूसरी या तीसरी भाषा बन जाती है।

प्रख्यात भौतिकशास्त्री और नोबल पुरस्कार से सम्मानित सर सीवी रमन ने कहा था, हमें विज्ञान को मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, अन्यथा वह एक गर्व या घमंड का विषय बन जाएगा। वह ऐसा विषय नहीं बन सकेगा जिसमें हर कोई शिरकत कर सके। हमारे शिक्षा तंत्र में अभूतपूर्व प्रसार हुआ है, लेकिन पिछले कई वर्षों में हमने अपने ही विद्यार्थियों की प्रगति के रास्ते में शैक्षणिक बाधाएं खड़ी कर दी हैं। हम अंग्रेजी माध्यम के चंद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के एक छोटे से बुलबुले को बनाकर ही संतुष्ट हैं, जबकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हमारी अपनी ही भाषाएं पिछड़ रही हैं। उच्चतर शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित रीति-नीति पर नजर डालें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं? दक्षिण कोरिया में 70 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में शिक्षण कोरियन भाषा में ही होता है। अंग्रेजी के प्रति अभिभावकों में बढ़ते आग्रह को देखते हुए 2018 में दक्षिण कोरियाई सरकार ने स्कूलों में कक्षा तीन से पहले अंग्रेजी की पढ़ाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि विद्यार्थियों की कोरियाई भाषा में प्रवीणता कम हो रही थी। इसी प्रकार जापान में भी विश्वविद्यालयों में अधिकांश पाठ्यक्रम जापानी भाषा में ही पढ़ाए जाते हैं। यही स्थिति चीन में भी है। फ्रांस और जर्मनी की शिक्षा पद्धति हमें सिखाती है कि राष्ट्र अपनी भाषा को कैसे संरक्षित रखते हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में यह अजीब है कि भारत में अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, विधि में तो स्थिति और भी खराब है, जहां स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम न के बराबर हैं। सौभाग्य से अब हम अपनी भाषा में ही अपनी आवाज पा सकेंगे। इस विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा मार्गदर्शन करती है, जिसमें हमारी भाषाओं के संरक्षण के साथ-साथ अच्छी शिक्षा भी सभी की पहुंच में हो, इसका खाका तैयार किया गया है।

अवधेश राजपूत

हालांकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 14 कालेजों द्वारा लिया गया कदम सर्वथा सराहनीय है, लेकिन हमें और भी ऐसे ही प्रयास चाहिए। निजी विश्वविद्यालयों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। स्थानीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा लेने के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि छात्रों को स्तरीय पुस्तकें नहीं मिल पातीं, खासकर तकनीकी शिक्षा में। इस कमी का समाधान जल्द करना जरूरी है। आज के डिजिटल युग में भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों को दूरस्थ स्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। डिजिटल माध्यम में उपलब्ध पाठ्य सामग्री प्रायः अंग्रेजी में ही होती है, जिससे बड़ी संख्या में हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। इस दिशा में एआइसीटीई और आइआइटी, मद्रास के सहयोग से स्वयं पाठ्यसामग्री को तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, मराठी, मलयालम और गुजराती आदि भाषाओं में अनुवाद कर उपलब्ध कराया जाना सराहनीय कदम है। इससे इंजीनियरिंग के छात्रों को बड़ी सहायता मिलेगी।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने का अर्थ यह नहीं कि हम कटकर अलग-थलग हो जाएं। हर व्यक्ति को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन जरूरी है कि मजबूत नींव मातृभाषा में ही पड़े। मैं मातृ भाषा बनाम अंग्रेजी की वकालत नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भी का हिमायती हूं। आज हम परस्पर निर्भर और आपस में जुड़े हुए विश्व में रह रहे हैं। ऐसे में विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता वृहत्तर विश्व के नए द्वार ही खोलेगी। यदि हम अपनी भाषा को नजरंदाज करते हैं तो न सिर्फ ज्ञान की एक बहुमूल्य निधि को खो देंगे, बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से भी काट देंगे और उन्हें सामाजिक एवं भाषाई धरोहर से वंचित कर देंगे।

(लेखक उपराष्ट्रपति हैं)

response@jagran.com

नई सुबह की ओर जम्मू-कश्मीर

प्रो. रसाल सिंह

अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति से जम्मू-कश्मीर में विकास का सपना साकार हो रहा है

आजादी से लेकर पांच अगस्त, 2019 तक जम्मू-कश्मीर प्रदेश का अधिसंख्य समाज कश्मीर के नेतृत्व वाली सरकार की कश्मीर-केंद्रित भेदभावपूर्ण नीति का शिकार रहा था। यह भेदभाव विकास योजनाओं से लेकर लोकतांत्रिक भागीदारी तक और एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों और बहन-बेटियों के न्यायसंगत अधिकारों की अवहेलना तक व्याप्त था। पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा 35ए की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर के वर्षों से उपेक्षित वंचित वर्गों को न्याय देने की परियोजना प्रारंभ हुई। इससे प्रदेश में अनेक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई है। इससे जम्मू-कश्मीर की एकात्मता और विकास का सपना साकार हो सका है।

पिछले दो वर्षों की अल्पावधि में ही जम्मू-कश्मीर में जमीनी बदलाव नजर आने लगा है। कुछ काम हो गया है और बहुत काम होना बाकी है। 28 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद यहां पिछले साल से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह लागू हो गई है। स्थानीय निकायों को वे सभी अधिकार और संसाधन मिल गए हैं, जो देशभर में मिलते हैं। जम्मू-कश्मीर में एसटी वर्ग (गुज्जर बक्करवाल, गद्दी, सिप्पी आदि) को राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिला है, जिससे इस वर्ग के विकास के रास्ते खुले हैं। अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देकर सामाजिक-न्याय सुनिश्चित किया गया है। संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर का यही सपना था कि भारत में समतामूलक और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। कहीं भी जाति-धर्म, क्षेत्र और लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। यह संतोष की बात है कि कुछ देर से सही, उनका यह स्वप्न देश के अन्य भागों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी साकार हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में अधिकारों से वंचित बहनों-बेटियों को न्याय मिला है। इससे पहले जिनका विवाह प्रदेश से बाहर हो जाता था, उन्हें उनके जन्मजात अधिकारों तक से वंचित कर दिया जाता था। स्वाधीन भारत में लैंगिक भेदभाव का यह शर्मनाक उदाहरण था, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं था।

हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय 'एक व्यक्ति-एक मत' का प्रविधान करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पहले महिलाओं को मताधिकार देकर प्रगतिशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था का परिचय दिया था। किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ही उनके मार्गदर्शक सिद्धांत थे। जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद 370 और धारा 35ए के तहत मिले अस्थायी विशेषाधिकारों की आड़ में इन सिद्धांतों की अवहेलना करता आ रहा था। अब वहां भारत का संविधान पूरी तरह लागू होने से आमूलचूल सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का राह खुल गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता और भेदभाव किसी भी समाज के लिए अभिशाप हैं। जम्मू-कश्मीर अब इस अभिशाप-मुक्ति की दिशा में बढ़ चला है। इसी के चलते प्रदेश में बसे हुए लाखों दलितों विशेषकर वाल्मीकि समाज, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखा और गुलाम कश्मीर के विस्थापितों को सम्मान, समान अवसर और मतदान जैसे मूल अधिकार और सुविधाएं मिली हैं। इनके अलावा नई औद्योगिक नीति लागू होने और निवेशक सम्मेलनों के आयोजन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई है। नई भाषा नीति लागू करके डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को राजभाषा (शासन-प्रशासन की भाषा) का दर्जा देकर स्थानीय लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी हुआ है। अभी तक आतंकवाद और भेदभाव के शिकार रहे पर्यटन उद्योग को पुनः विकसित किया जा रहा है। इस कड़ी में श्री वेंकटेश्वर भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण, देविका नदी और शिवखोड़ी गुफा जैसे पवित्र-स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। आतंकवादियों के पनाहगार बने दर्जनों सरकारी कर्मी बर्खास्त किए जा चुके हैं और सैकड़ों के खिलाफ जांच चल रही है। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों और अलगाववादियों की नकेल कसने और हवाला फंडिंग रुकने से राष्ट्रविरोधी हिंसक गतिविधियों में निर्णायक गिरावट आई है। पांच अगस्त, 2019 के बाद से प्रदेश में आतंकवादी वारदातें 59 प्रतिशत तक कम हुई हैं। जम्मू-कश्मीरवासियों को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के अंतर्गत कश्मीरी विस्थापितों के लिए रोजगार और आवास की व्यवस्था हो रही है। ई-फाइलिंग के जरिये अर्धवार्षिक 'दरबार-मूव' की खर्चीली कवायद को समाप्त किया गया है। विभिन्न कार्यों के समयबद्ध निपटारे और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिटिजंस चार्टर लागू किया गया है। इससे निष्क्रिय और टालू सरकारी कर्मी हरकत में आ रहे हैं। रोशनी एक्ट और शस्त्र लाइसेंस घोटाले में धर-पकड़ हो रही है।

जम्मू-कश्मीर में मिल रहा बहनों-बेटियों को न्याय। फाइल

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करके उन्हें संतुलित और न्यायसंगत बनाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पहले इस आयोग का बहिष्कार करने वाले नेशनल कांफ्रेंस जैसे दल भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर इसे समग्र और समावेशी बना रहे हैं। 'एक विधान, एक निशान, सबको समता और सम्मान' न सिर्फ जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में देश के नीति-नियंताओं का पाथेय बने, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में इसे अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। गुलाम कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं है। पाकिस्तानी फौज द्वारा वहां के लोगों पर ढाए जा रहे जुल्मो-सितम से निकलने वाली करुण-पुकार को लंबे समय तक अनसुना नहीं किया जा सकता है।

(लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता, छात्र कल्याण हैं)

response@jagran.com

बड़ा आदमी

यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी अपने बचपन से सुनते आए हैं। बड़ा आदमी बनो का आशीर्वाद बचपन में प्रिय माना जाता है। कुछ बड़े होने पर यह माता-पिता का सपना बन जाता है। उस आशीर्वाद और सपने को मनुष्य जीवन भर भारी बोझ की तरह अपने कंधों पर ढोता रहता है। उसे लगता है कि इस दौड़ में शामिल रहना चाहिए, भले ही कितना ही पीछे क्यों न हो। जिसके पास धन है वह बड़ा आदमी है। जिसके पास बल और अधिकार हैं वह बड़ा आदमी है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या बड़ा हो जाना ही मानव जीवन की सार्थकता है? यदि किसी के पास धन, शक्ति और अन्य संबल नहीं हैं तो क्या उसे छोटा मान लिया जाना चाहिए? क्या छोटा होना अयोग्यता है? दरअसल बड़ा होना नहीं, खरा होना मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। बड़ा बनने के लिए बाह्य आधार चाहिए। खरा बनने के लिए अंतर का उन्नयन चाहिए। भीतर की अशुद्धियां जितनी निकलती जाती हैं, सोना उतना ही खरा होता जाता है। शुद्धता ही सोने का मूल्य है। मनुष्य के अवगुण छूटते जाएं, गुण समाते जाएं उनसे ही उसकी श्रेष्ठता तय होती है। मोंगरे के फूल बहुत छोटे होते हैं, किंतु सिंगार उन्हीं से किया जाता है। चमेली के फूल स्वयं ही नहीं महकते, अपने आस-पास को भी सुगंध से भर देते हैं। कोई महल बहुत बड़ा और सुंदर होने से ही आदरणीय नहीं हो जाता। एक छोटे से मंदिर में यदि आराध्य की मूर्ति स्थापित हो तो शीश झुकाने वालों की कतार लग जाती है। वह मंदिर विशाल महल से भी अधिक विशालता पा लेता है।

जो बड़ा माना जाता है, वह गर्व का अनुभव करता है। यह गर्व कब अहंकार में बदल जाता है उसे पता ही नही चलता। अहंकार आते ही बड़ा होना एक रोग बन जाता है, जो मानव जीवन को पतन की ढलान पर डाल देता है। जाहिर है बड़ा बन जाना सरल है, किंतु बड़ा बने रहना एक बड़ा संघर्ष है। स्पष्ट है कि बड़ा होना पल भर का छलावा है। आंतरिक शुद्धता पाना ही जीवन में ऊंचा उठना है।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

भिक्षावृत्ति उन्मूलन की जरूरत

देवेंद्रराज सुथार

भिक्षावृत्ति के पीछे बेरोजगारी और निर्धनता की अहम भूमिका है। इसलिए देश में उत्पादन के साधनों को बढ़ाना होगा

गत दिनों सर्वोच्च अदालत ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए भिखारियों और बेघरों को सड़कों से हटाने का आदेश देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा आभिजात्य आदेश नहीं दे सकते। लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं। यह स्थिति शिक्षा और रोजगार में अवसरों की कमी से पैदा होती है। देखा जाए तो कई कारण हैं जो देश में भिक्षावृत्ति को जन्म देते हैं। गरीबी और बेरोजगारी इसकी प्रमुख वजह हैं। अंधों, अपाहिजों तथा रोगियों के कल्याण के लिए देश में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अतः वे भीख मांगने को मजबूर हैं। पिछड़ी जातियों की विधवाएं या परित्यक्त महिलाएं भीख मांगती हैं। कई मानसिक रोगी आवारा बन जाते हैं और भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। बाढ़, भूकंप या अकाल आदि आपदाओं के कारण हजारों लोग बेघर और असहाय हो जाते हैं और अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने लगते हैं। कमाने वाले की मौत भी कभी-कभी घर की महिलाओं और बच्चों को भिखारी बना देती है।

केंद्र सरकार के अनुसार देश में कुल 4,13,670 भिखारी हैं, जिनमें से 2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा भिखारी बंगाल में हैं। वहां भिखारियों की संख्या 81,000 है। केंद्र शासित प्रदेशों में भिखारियों की संख्या सबसे कम है। इस सूची में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां भिखारियों की संख्या 65,835 है। जबकि आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है। वहां 30,218 भिखारी हैं। बिहार की बात करें तो वहां 29,723 भिखारी हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम में सबसे ज्यादा 22,116 और मिजोरम में सबसे कम 53 भिखारी हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में सालाना लगभग 215 करोड़ रुपये की भिक्षावृत्ति का कारोबार है। पूरे देश में पिछले लगभग 60 वर्षों से भिक्षावृत्ति निरोधक कानून चला आ रहा है, लेकिन भीख मांगने पर रोक लगाने में इस कानून को कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस कानून को लाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि भिक्षावृत्ति को एक व्यवस्थित व्यवसाय न बनने दिया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक आदि कारकों ने मिलकर इस समस्या को बहुत गंभीर बना दिया है।

भिक्षावृत्ति की पृष्ठभूमि में बेरोजगारी और निर्धनता की अहम भूमिका है। इसलिए देश में उत्पादन के साधनों को बढ़ाना होगा। योजनाओं के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करनी होगी, ताकि हर कुशल और अकुशल श्रमिक को नौकरी मिल सके। शहरों और महानगरों में गुप्त तरीके से काम करने वाली कई ऐसी संस्थाएं हैं, जो बच्चों को पकड़कर, पीटकर, धमकाकर या अपंग बनाकर बेवजह भीख मंगवाती हैं। ऐसे संगठनों का पता लगाया जाना चाहिए और ऐसे संगठन चलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

मेडिकल में आरक्षण

'संवैधानिक दायरे में सियासी लाभ' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में ए. सूर्यप्रकाश ने मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की मोदी सरकार की पहल के बहाने पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक प्रविधानों, विभिन्न सरकारों के इस दिशा में प्रयासों, मंडल आयोग, कर्पूरी फार्मूला, आर्थिक पिछड़ेपन की वास्तविकता आदि विषयों पर गंभीर टिप्पणी की है। केवल बौद्धिक पहलू की बात करें तो सरकार का मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देनेवाला फैसला प्रतिगामी प्रतीत होता है, लेकिन जैसा कि लेखक ने भी आगे साफ कर दिया है कि यह मामला उतना सीधा है नहीं, जितना कि दिखता है। मंडल के पक्ष-विपक्ष में हुई लामबंदी ने पहले से ही विभाजित हिंदू समाज में विभाजन की खाई को और चौड़ा कर दिया। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए क्षेत्रीय एवं जातिवादी नेताओं ने ऐसे आचरण किए, जिसने आग में घी डालने का ही काम किया। परिणाम यह हुआ कि न सिर्फ सदियों से चली आ रही सामाजिक एकता खंड-खंड हुई, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता भी कमजोर होती चली गई। मजबूत सरकारों का दौर स्वप्न सरीखा हो गया। ऐसे ही जटिल दौर में मोदी के नेतृत्व में देश ने एक प्रबल राजनीतिक आंदोलन को देखा, जिसमें स्पष्ट रूप से सामाजिक चेतना के तत्व भी उतने ही मजबूत थे। निःसंदेह वर्तमान सरकार देश और समाज की भावी जरूरतों को समझती है, लेकिन इसके साथ ही वह उसकी वर्तमान कठोर वास्तविकताओं को भी जानती-समझती है। उसने बड़ी समझदारी से देश की जाति और क्षेत्र केंद्रित दलों को उनकी ही मांद में चुनौती दी है। मेडिकल में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के सरकार के हालिया फैसले को इसी संदर्भ में देखा जाना उचित होगा।

chandankarn9470@gmail.com

अब जल्द हो समाधान

संपादकीय पेज पर प्रकाशित राजीव सचान का लेख पेट पर लात मारने वाला आंदोलन लगातार चलते किसान आंदोलन की असलियत बताने वाला लेख है। वास्तव में किसानों की आड़ में आढ़ती, स्वार्थी राजनीतिक दल और देश विरोधी ताकतें, यहां तक कि खालिस्तान समर्थक भी अपना हित साध रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थलों पर तो एक दिन का कब्जा भी बेहद गलत है। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति ने बहुत पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। बावजूद इसके मामले को नहीं निपटाया जा रहा है। कथित किसान नेताओं द्वारा दिल्ली के बार्डरों पर कब्जा से स्थानीय लोगों से लेकर राहगीर तक को परेशानी हो रही है। डेढ़ साल से कोरोना से कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। उस पर सीमाओं को घेरना, धरना प्रदर्शन आग में घी डालने जैसा है। कांग्रेस, आप और अकाली दल इस आंदोलन को शुरू हवा दे रहे हैं। अगर से राजनीतिक दल इनका साथ नहीं देते तो ये प्रदर्शन कब का खत्म हो गया होता। प्रदर्शन के नाम पर ये कई बार हिंसक कृत्यों को अंजाम दे चुके हैं। अब समय की मांग है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस आंदोलन को जल्द समाप्त करने के लिए त्वरित कार्यवाही करें।

सीपी बंसल, दिल्ली

डेल्टा प्लस से बचाना प्राथमिकता

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सरकार को चेताया है कि अब डेल्टा प्लस के विस्तार का अंदेशा बढ़ गया है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर विनाशकारी रूप में अपना दुष्प्रभाव छोड़ सकती है। सार्वजनिक परिवहन से धीरे धीरे प्रतिबंध हटाए जाने से शारीरिक दूरी के मापदंडों का भी उल्लंघन होने लगा है। चरणबद्ध तरीके से शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण औद्योगिक संस्थानों में आर्थिक गतिविधियां गति पकड़ने लगी हैं। अब यदि डेल्टा प्लस के संक्रमण से आमजन को बचाव करना है तो वैक्सीनेशन, मास्क व सैनिटाइजेशन के अतिरिक्त भी अन्य सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * [illegible] हवाई शुल्क अतिरिक्त।

67 प्रतिशत अभिभावक जल्दी स्कूल खोलने के पक्ष में हैं, जबकि आनलाइन शिक्षा के पक्ष में केवल 19 प्रतिशत अभिभावक ही हैं, लोकल सर्कल्स द्वारा बीते दिनों 24 राज्यों के 294 जिलों में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार।

पठन-पाठन

आनलाइन में समस्याएं आफलाइन का इंतजार

कोरोना महामारी जनित कारणों से स्कूलों के बंद होने से शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित रखने के लिए देश भर में आनलाइन शिक्षा का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन करीब डेढ़ साल का लंबा समय बीतने पर आनलाइन शिक्षा व्यवस्था के संबंध में अनेक अभिभावकों और छात्रों के समक्ष विभिन्न चुनौतियां सामने आ रही हैं। कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चों की पढ़ाई की राह में तो ये चुनौतियां बड़ी बाधाएं साबित हो रही हैं। ऐसे में बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के स्कूलों को आफलाइन आरंभ करने की दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया है

स्कूली बच्चों के लिए आफलाइन शिक्षा का विकल्प आनलाइन शिक्षा कतई नहीं हो सकती। फाइल

नरपतदान चारण
वरिष्ठ शिक्षक,
शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

विश्व के 160 से अधिक देशों में चरणबद्ध रूप से स्कूलों के आरंभ होने की खबरों के बीच हमारे देश में भी विभिन्न राज्यों में इस माह से स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है, लिहाजा इस बारे में हमें नए सिरे से रणनीति बनाने में अभी से ही जुट जाना होगा।

चूंकि भारत में संक्रमण के मामले काफी हद तक कम हुए हैं, ऐसे में आफलाइन स्कूल संचालन को लेकर काम किया जाना चाहिए। दरअसल आनलाइन शिक्षा धरातल पर पूरी तरह कारगर और कामयाब साबित नहीं हो पा रही है। इसमें कई पेचीदगियां हैं। 'लोकल सर्कल्स' द्वारा 24 राज्यों के 294 जिलों में किए गए सर्वे में सामने आया है कि 67 फीसद अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। जबकि आनलाइन शिक्षा के पक्ष में महज 19 फीसद अभिभावक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आनलाइन शिक्षा व्यवस्थित न होने से अभिभावकों द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है। हालांकि आनलाइन शिक्षा की जद्दोजहद के लिए समय समय पर अलग अलग दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने घर-आधारित शिक्षण में माता-पिता की भागीदारी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें आनलाइन शिक्षा के समय अभिभावकों को बच्चों के सहयोग के लिए बताया गया है।

वहीं, दूसरी तरफ अदालत ने निजी स्कूलों को कोविड से प्रभावित शिक्षा सत्र के लिए आनलाइन शिक्षा के आधार पर भी बच्चों से विकास और वार्षिक शुल्क वसूलने के आदेश यथावत रखे हैं। इस तरह की बातों से यह विसंगति कायम है कि आनलाइन शिक्षा का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं होने के बावजूद इसे बच्चों पर थोपा जा रहा है, क्योंकि सही रूप में देखा जाए तो आनलाइन शिक्षा व्यवस्था और उसके वास्तविक प्रदर्शन व प्रतिफल से हम काफी दूर हैं। इसलिए यह आनलाइन शिक्षा महज 'इमरजेंसी रिमोट टीचिंग' साबित हो रही है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो आनलाइन एजुकेशन और इस इमरजेंसी रिमोट टीचिंग में बहुत फर्क है। आनलाइन शिक्षा अच्छी तरह से तैयारी और अनुसंधान के बाद अभ्यास में लाई जाती है। लेकिन इस समय यह धरातलीय वास्तविकता जाने बगैर मजबूरी में लागू की गई है। इसमें कई खामियां है। एक तो यह महंगी है, दूसरा स्कूली संसाधनों का उपयोग न करने के बावजूद निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस वसूला जाना और तीसरा, तकनीक की पहुंच हर छात्र तक नहीं होना काफी अव्यावहारिक है।

यह भी समझा जाना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक स्मार्टफोन होना ही आनलाइन एजुकेशन नहीं होता है। इसके लिए व्यापक प्लेटफार्म और तकनीकी यंत्रों की महती भूमिका होती है। चूंकि बच्चों की सेहत का खयाल रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्कूल को बंद रखा जाना जरूरी था। ऐसे में बच्चे घर पर ही मोबाइल या लैपटाप, टेबलेट, टीवी आदि के माध्यम से डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूरस्थ इलाकों में सुलभ इंटरनेट सेवा नहीं होने, टैबलेट, प्रोजेक्टर आदि की उपलब्धता न होने या ई-कंटेंट की अनुपलब्धता के कारण स्कूली बच्चे डिजिटल शिक्षा से महरूम हैं।

हालांकि आनलाइन शिक्षण का विचार कोई नया नहीं है और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भारत में इसका प्रयोग पहले से चल भी रहा है। लेकिन वृहद रूप से देखा जाए तो अभी हमारे स्कूली शिक्षण संस्थानों में इसका चलन नहीं के बराबर है। इसी बीच सर्वेक्षणों में यह जानकारी सामने आई है कि मात्र एक तिहाई अभिभावक ही अपने बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर सकते हैं। लिहाजा इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जरूरत यह बात ध्यान रखने की है कि यह आनलाइन शिक्षा व्यवस्था कम लागत में, सस्ती और सर्वसुलभ रूप में निर्बाध रूप से संचारित हो। अब चूंकि सरकारी स्कूल में तो सरकार का यह दायित्व है कि वह बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रही है, लिहाजा डिजिटल शिक्षा हेतु आवश्यक उपकरण भी निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। लेकिन बड़ी समस्या निजी शिक्षा संस्थानों को लेकर है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि निजी शिक्षा संस्थानों का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। निजी स्कूलों में आफलाइन शिक्षा पहले ही इतनी महंगी है कि हर कोई वहां पढ़ नहीं पाता। ऐसे में डिजिटल शिक्षा के दौर में आवश्यक उपकरण जुटाना काफी महंगा है।

शुरुआती दौर में स्कूलों में आनलाइन शिक्षा प्रदान करने के रास्ते में अनेक व्यावहारिक बाधाएं आई हैं, जैसे सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटाप या टैबलेट की सुविधा न होना, इंटरनेट, ब्राडबैंड का सुचारू रूप से उपलब्ध न होना, डाटा स्पीड नहीं मिलना, आनलाइन शैक्षिक टूल्स की जानकारी न होना, पुस्तकालयों का डिजिटल न होना, ई-कंटेंट का उपलब्ध न होना आदि। चूंकि डिजिटल शिक्षा को पाने के लिए लोगों को कई उपकरणों को लेना होता है, जो काफी महंगे पड़ते हैं। ऐसे में घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने के लिए टैबलेट, पीसी, प्रोजेक्टर, इंटरनेट और विशेषकर सस्ता डाटा और हाई स्पीड इंटरनेट की बहुत जरूरत होती है। वर्तमान में ये सभी सुविधाएं काफी महंगी साबित हो रही हैं। यही कारण है कि डिजिटल शिक्षा देने वाले अधिकांश स्कूल नियमित स्कूलों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। इसी कारण डिजिटल शिक्षा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पारंपरिक किताबी शिक्षा से घर हो या स्कूल कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। जबकि डिजिटल शिक्षा के लिए न केवल स्कूल में, बल्कि घर में भी सस्ते ब्राडबैंड में उचित आधारभूत संरचना की जरूरत होती है। वहीं डिजिटल शिक्षा के तहत सीखने के लिए बेहतर प्रबंधन और कठोर योजनाओं की जरूरत होती है। यह जरूर संभव है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या का कुछ प्रतिशत समय की मांग को देखते हुए भविष्य में कंप्यूटर, लैपटाप इत्यादि संसाधन खरीद भी ले, क्योंकि स्मार्टफोन के ही द्वारा पढ़ाई करना संभव नहीं है। लेकिन एक बड़ी समस्या उन विद्यार्थियों की है जो कमजोर आय वर्ग से आते हैं। उनके अभिभावकों के लिए उनकी फीस भर पाना ही किसी चुनौती से कम नहीं होता, ऐसे में महंगे उपकरण खरीद पाना सबके सामर्थ्य की बात नहीं।

डिजिटल शिक्षा का बच्चों पर एक और दुष्प्रभाव सामने आ रहा है। दरअसल आनलाइन पढ़ाई करने के बहाने से बच्चे स्मार्टफोन या टैबलेट में तरह तरह के गेम व अन्य गलत कंटेंट भी देखने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि सभी माता-पिता इस बात को समझ ही जाएं। ऐसे में बच्चों का पढ़ाई के प्रति अच्छा विकास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह भी आनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा नुकसान है। वहीं स्वास्थ्य पर इसका व्यापक दुष्प्रभाव भी सामने आ रहा है। आनलाइन शिक्षा से छात्रों की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी दृष्टि खराब होती है। न केवल आंखें खराब होती हैं, बल्कि मस्तिष्क और चेहरे पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बड़ी समस्या है। इसलिए हमारे नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि आनलाइन माध्यम किसी भी रूप में आफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता है।

शिक्षा के प्रसार के बीच संकुचित होता समाज

ज्योति रंजन पाठक

भारत में शिक्षा का इतिहास मानव समाज और सभ्यता के विकास के इतिहास का सहगामी रहा है। आज का समाज पहले के मुकाबले कहीं अधिक शिक्षित है, फिर भी आज समाज बहुत ही सिमटा हुआ दिखाई पड़ता है। लोग निजी तत्व का हवाला देकर एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, जिससे लोगों में अवसाद और अकेलापन व निराशा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

देश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के कारण तमाम क्षेत्रों में दक्ष पेशेवर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें इस बारे में आत्ममंथन करना होगा कि क्या जिस शिक्षा व्यवस्था को हमने अपनाया है वह वास्तव में समाज के समग्र विकास में सहायक हो पा रही है या नहीं। शिक्षा के बूते पेशेवर जीवन में बेहद सफल होने के बावजूद आज अधिकांश लोग सामाजिक रूप से विकसित नहीं कहे जा सकते। शायद यही कारण है कि लोगों में एकाकीपन और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। शहरों व महानगरों में रहने वाले अधिकांश शिक्षित लोगों ने अपने आस-पड़ोस से अनभिज्ञ स्वयं को समाज से अलग कर लिया है।

पढ़ा-लिखा होने का यह मतलब तो नहीं कि आप समाज से दूरी बना लें? हम अगर समाज में रहते हुए एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो कहीं न कहीं हम अपनी मनुष्यता को खो देंगे। हालांकि कोरोना जनित संक्रमण के कारण पिछले करीब डेढ़ वर्षों से आपस में मिलने-जुलने का सिलसिला समाज में पहले से थोड़ा कम अवश्य हो गया है, लेकिन डिजिटल उपकरणों ने वर्चुअल तरीके से मिलने-जुलने की प्रक्रिया को निश्चित तौर पर बनाए रखा है। फिर भी आपसी रिश्ते की मजबूती के लिए इंसान का भौतिक रूप से आपस में मिलना-जुलना बेहद जरूरी है। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हो रही हैं जो लोगों को अकेलापन की तरफ धकेल रही है।

आज इंसान अधिकांश समय अपने बारे में ही सोचता है। खुद को अहमियत देने की सोच अहंकार को भी जन्म देती है और अहंकार अक्सर लोगों के स्वभाव को अड़ियल बना देता है। इससे उसकी व्यावहारिक सोच प्रभावित होती है और उसकी सामाजिकता का दायरा सीमित हो जाता है। अहंकार ग्रस्त व्यक्ति के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है जो अपनी खामियों को नहीं देख पाता है और न तो वह अपनी आलोचना सुन पाता है। शिक्षा के बढ़ते दायरे के बीच इंसान के सामाजिक दायरे का संकुचित होना एक अलग प्रकार की नई समस्या को जन्म दे रहा है।

वैसे इंटरनेट मीडिया के वर्चस्व के बीच वर्चुअल तरीके से लोग सामाजिकता के दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड सर्किल के नाम पर दोस्त बनाए जा रहे हैं। लाइक और कमेंट की आभासी प्रशंसा एक ऐसे काल्पनिक समाज का निर्माण कर रही है जिसका दुष्प्रभाव वास्तविक समाज में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमें शिक्षा व्यवस्था को ऐसा स्वरूप देना होगा जो हमारी विकृत होती सामाजिक व्यवस्था को सही रास्ते पर ला सके।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

कायम रहेगी गिद्ध प्रवृत्ति

प्रदीप कुमार दीक्षित

गिद्ध भले लुप्तप्राय श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन गिद्धपना अनंत काल तक कायम रहेगा। इस मामले में गिद्धों को इंसानों पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम उनकी प्रवृत्ति को कभी लुप्त नहीं होने देंगे। दरअसल, गिद्ध प्रवृत्ति इंसानों में इस तरह हस्तांतरित हो चुकी है कि उनके स्वयं के अस्तित्व में रहने या न रहने का प्रवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

गिद्धों का सबसे प्रिय पात्र नेता होता है, क्योंकि वह बारह महीने, बत्तीस घड़ी कुर्सी पाने के लिए अहर्निश गिद्ध दृष्टि जमाए रखता है और मौका मिलते ही हवा में कलाबाजियां खाने लगता है। बस जैसे गिद्ध को मांस की गंध आती है, नेता को सत्ता की गंध भर आना चाहिए। फिर तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को विभिन्न तरीकों से जिंदा ही नोच कर खत्म कर सकता है। बल्कि इस संबंध में वह गिद्धों से एक कदम आगे है, क्योंकि वह गिद्ध की तरह सामने वाले के मरने की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि स्वयं ही पहले मारने का प्रबंध रचता है, फिर उसे नोचने का उत्सव मनाता है।

गिद्धों को अफसर भी कम प्रिय नहीं हैं। उन्होंने देखा है कि अफसर किस तरह बजट पर अपनी दृष्टि गढ़ाए रखते हैं। इससे तो कई बार गिद्धों को भी शर्म महसूस होती है। उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों की दृष्टि उनसे भी तेज है। अफसर कहीं से भी रुपये खाकर हजम कर सकते हैं। उनका हाजमा गिद्धों से भी बेहतर है। जिस मद में पैसा खर्च करने की गंध आती है, अफसर वहां अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ा देते हैं। मजाल है उनका हिस्सा मिले बगैर कोई काम आगे खिसक भी सके। काम कैसा भी हो, नुकसान कितना भी हो, उन्हें तो अपना हिस्सा चाहिए।

कुछ समय से कुछ नए पात्र गिद्धों के प्रिय हो गए हैं। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से गिद्धों को बहुत आशाएं हैं। स्कूल, कालेजों और अस्पतालों की गिद्ध दृष्टि जिस तरह पालकों और मरीजों की जेब पर गड़ी रहती है, उसका तो कहना ही क्या। शिक्षा की मंडी सजी है और बच्चों के भविष्य की बोलियां लग रही हैं। इधर, मरीजों की जिंदगी और मौत को मुद्रा की तराजू पर तौला जा रहा है। गिद्ध इन्हें देख सर्वाधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि ये सच्चे प्रतिनिधि हैं।

ट्वीट-ट्वीट

हम देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते, यह समाज, सरकार, सिस्टम सबकी असफलता है। मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

मैं अपने घर पर इस बार के ओलिंपिक पर कई सकारात्मक बदलाव देख रही हूं। टीवी हर वक्त आन रहता है। हम ढेर सारे खेल बड़े चाव से देखते हैं। वे खेल भी, जिनमें कोई भारतीय खिलाड़ी भाग नहीं लेता। क्रिकेट के प्रति उन्माद छोड़ने का यह सही समय है। हमें दूसरे खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

जिस समय टोक्यो में भारत की महिला हाकी टीम खेल रही थी उसी समय इंग्लैंड के साथ टीम इंडिया का टेस्ट मैच भी चल रहा था, पर दर्शकों की निगाहें क्रिकेट के बजाय बेटियों के खेल पर टिकी थीं। यह भी भारतीय हाकी की एक बड़ी उपलब्धि है। बरखा दत्त@BDUTT

रवि दहिया ने क्या रोमांचक वापसी की। कुश्ती में कजाखस्तान के पहलवान से हारते-हारते अंतिम कुछ क्षणों में अपने कौशल और ताकत से बाजी पलट दी। यह बताता है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अंत तक संघर्ष करने का यही जज्बा हमें अपने खिलाड़ियों में भरने की जरूरत है। किरण मजूमदार शा@kiranshaw

कश्मीर पर भारत के शाश्वत आलोचक इस बार गलत साबित हो गए हैं। कहते हैं कि इतिहास सिर्फ कुछ 'जुनूनी' पुरुष या महिला बनाते हैं, बाकी लोग उसका उसका अनुसरण करते हैं। जम्मू-कश्मीर में 370 के खात्मे के संबंध में इतिहास हमेशा के लिए सुधारा जा चुका है। आरती टिक्कू सिंह@AartiTikoo

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ओलिंपिक में भारत का अब तक का प्रदर्शन संतोषजनक कहा जा सकता है?

सभी आकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका गहरा रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जीते जश्न मना रहे हारे को हरिनाम,
स्वर्ण गया तो क्या हुआ लिखो कांस्य पर नाम।
लिखो कांस्य पर नाम दिखाओ दिल से खेला,
आज तुम्हारे नाम लगा भारत में मेला।
वर्ष बहुत से यार बिना पदकों के बीते,
कम से कम इस बार लग रहा कुछ तो जीते!
– ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

कांग्रेस में थम नहीं रहा खींचतान का दौर

संजय मिश्र
स्थानीय संपादक,
नवदुनिया, भोपाल

करीब 15 साल के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करके 15 माह में ही उसे गंवाने वाली कांग्रेस फिलहाल सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी में गुटबंदी अब भी कायम है। जमीनी कार्यकर्ता असमंजस में हैं, क्योंकि बड़े नेता ही एक-दूसरे की काट करने में लगे हैं। अभी साल भर पहले ही कद के हिसाब से पद व महत्व न मिलने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थकों सहित कांग्रेस का हाथ झटककर भाजपा का दामन थाम लिया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे पार्टी की रीति-नीति में बदलाव आएगा और उन नेताओं की पूछ होगी जो हाशिये पर हैं, लेकिन एक साल बाद भी ऐसा नहीं हुआ। न तो संगठन में कोई बदलाव आया और न ही बड़े नेताओं के व्यवहार में कोई अंतर। प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष दोनों पदों पर कमल नाथ बने हुए हैं।

संगठन में महत्व न मिलने के कारण कई बड़े नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पार्टी के अंदर गहरा रहा यह अंतर्विरोध पिछले दिनों सामने आ गया, जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार अरुण यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ द्वारा बुलाई गई बैठक से किनारा कर लिया।

यह भी एक तथ्य है कि हाल ही में हुए दमोह विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़े अंतर से जीत मिलने के बाद कमल नाथ का मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस तरह दमोह उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई थी, उसी तर्ज पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र एवं पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भी उनकी रणनीति सफल हो सकती है। इसीलिए वह प्रत्याशी चयन को लेकर निश्चिंतता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदर ही अंतर्विरोध गहरा रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पदों पर आसीन : कमल नाथ। फाइल

खंडवा लोकसभा सीट भाजपा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन से रिक्त है। कांग्रेस नेता अरुण यादव को हराकर चौहान ने यह सीट जीती थी। यही कारण है कि अरुण खुद को कांग्रेस का स्वाभाविक उम्मीदवार मानकर काफी समय से चुनाव क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह मानकर चल रहे हैं कि पार्टी उनके ऊपर ही दांव लगाएगी, लेकिन इसी बीच बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की कमल नाथ से हुई मुलाकात ने नई चर्चा को जन्म दे दिया। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ द्वारा बुलाई बैठक से एक दिन पहले सुरेंद्र सिंह शेरा कमल नाथ से मिलने पहुंचे और खंडवा लोकसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर दी। इस घटनाक्रम से यादव नाराज हो गए और वे कमल नाथ द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे। चर्चा यह भी होने लगी कि कुछ भाजपा नेताओं ने उनसे संपर्क भी साधा है, जिसका उन्होंने ट्वीट के जरिये खंडन किया और स्वयं को कांग्रेसी बताते हुए दावा किया कि वे सिंधिया नहीं हैं कि स्वार्थ के लिए दल बदल लें। हालांकि यादव को लेकर अब भी कमल नाथ सहज नहीं हैं। इसका संकेत उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई एक पत्रकारवार्ता में यह कहकर दिया कि उनसे अरुण ने चुनाव के संबंध में कोई चर्चा नहीं की है।

दरअसल अरुण यादव को लेकर कमल नाथ की अप्रसन्नता को हिंदू महासभा के नेता व नाथूराम गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पैदा हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। कमल नाथ के सरकारी आवास पर चौरसिया को ग्वालियर के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। अरुण ने कांग्रेस में उनके प्रवेश का मुखर विरोध किया था। चौरसिया की सदस्यता रद करनी पड़ी थी। बाद में स्थिति सामान्य होने का दावा किया गया था, पर जो घटनाक्रम सामने आया है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह शेरा के माध्यम से कमल नाथ ने अरुण की घेरेबंदी का संदेश दे दिया है।

लोकसभा की खंडवा सीट एवं विधानसभा की पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव सीट के उपचुनाव से भले ही सत्ता के समीकरण प्रभावित न हों पर इससे बनने वाला माहौल कांग्रेस और भाजपा, दोनों के लिए काफी अहम है। कांग्रेस जहां दमोह उपचुनाव की जीत को भुनाना चाहेगी, वहीं भाजपा जीत दर्ज कर अपनी ताकत दिखाना चाहेगी। भाजपा ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती है, जिससे सत्ता विरोधी माहौल निर्मित हो। यही वजह है कि दोनों दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। केवल चुनाव कार्यक्रम और प्रत्याशियों के नाम घोषित होना शेष है।

हिमाचल प्रदेश डायरी

खड़ा पहाड़, क्या बस आंख का ही धोखा है

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक,
हिमाचल प्रदेश

अब तो किसी का भी गिरना, न गिरना अप्रत्याशित हो गया है... लेकिन बचपन में जब गिरते थे तो घर के लोग समझाते थे, 'गिर गए तो क्या हुआ, पहाड़ की तरह खड़े रहना सीखो।' सुनने को मिलता था, 'अमुक आदमी का दिल पहाड़ की तरह है।' पहाड़ के हौसले के बारे में भी बताया जाता। फिर सारे जहां से अच्छा... भी गाते थे स्कूल में। एक पंक्ति में हिमालय पर्वत यूं संदर्भित होता था, 'वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा!'

....अब, पहाड़ के हौसले से आगे पहाड़ पर और पहाड़ से टूट रहे पहाड़ जैसे दुख के जिक्र का समय है। भूस्खलन शब्द आज से कुछ वर्ष पहले ही अगस्त की एक रात को पुराना पड़ गया था, जब मंडी जिले के कोटरोपी में करीब 50 लोग बसों समेत मलबे में दब गए थे। आज वहां आइआइटी मंडी के छात्रों द्वारा तैयार किए सेंसर आगाह करते हैं कि पहाड़ पर हलचल है। सड़क वैसी ही है। यह भूस्खलन नहीं था, इसे पहाड़ टूटना कहते हैं।

आज जब शिलाई-हाटकोटी राजमार्ग पर पहाड़ टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे वर्षों से बिना थके ड्यूटी पर तैनात कोई व्यक्ति अचानक टूट कर गिर गया हो। यह अचानक है, न अकारण। इस राजमार्ग पर जहां पहाड़ गिरा, उससे नीचे कभी चूना पत्थर की खानें थी। घटनास्थल का दौरा करने आए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दल ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि पहाड़ के कमजोर होने के पीछे यहां हुआ चूनापत्थर का खनन भी है। यह वही क्षेत्र है जहां खनिजों का हर प्रकार से इतना दोहन किया गया है कि अब खड़ा पहाड़ भी आंख का धोखा ही प्रतीत होता है।

वर्ष 1980 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून क्षेत्र या दून घाटी में खनन पर रोक लगा दी तो प्राकृतिक खजाने का दोहन करने बड़े हाथ पांवटा साहिब होते हुए हिमाचल प्रदेश आ गए। वर्ष 1980 में गिनी चुनी खानें थीं और 1987 तक इनकी संख्या 70 हो गई। फिर पहाड़ बचाने एक महिला सामने आई। नाम था किंकरी देवी। उसने इस अंधाधुंध लूट के खिलाफ आवाज बुलंद की। शिमला में धरना दिया, उच्च न्यायालय में अर्जी लगा दी।

टूटते पहाड़ों की समस्या को समझने और उनका निदान करने का समय। फाइल

तब के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीडी देसाई और न्यायाधीश आर ठाकुर ने सख्त फैसला खनन के विरुद्ध सुनाया। अदालत ने पाया कि सरकार के जिन संबद्ध विभागों से जवाब मांगा गया, उनके जवाब में कोई तालमेल नहीं है। इस विषय पर फटकार भी लगी। बाद में किंकरी देवी के खिलाफ खनन वाले लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए जहां किंकरी देवी का पक्ष ठीक ठहराया गया। अदालत ने कुछ ऐसा फैसला दिया कि आगे खनन नहीं होगा, लेकिन जितना खनन हो चुका है, उतनी सामग्री उठाने की अनुमति खनन करने वालों को दी जाएगी।

हैरानी यह है कि 1995 के 20-25 साल बाद तक 'पुरानी' सामग्री निरंतर उठाई जाती रही। सवाल यह है कि इतनी सरकारें हुईं, पुरानी सामग्री कितनी है, यह देखने का अवकाश किसी को नहीं मिला। अपने हस्ताक्षर तक न कर सकने वाली बेहद साधारण महिला किंकरी देवी की मुरीद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन भी रहीं।

वास्तव में सरकार किसी की भी रही हो, खनन एक ऐसा विषय है जिस पर सबकी निगाहें रहती हैं। पहला कारण यह है कि किसी को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता। सामग्री प्राकृतिक है, ताकतवर किसी को भी उसके दोहन की अनुमति दे सकता है। दूसरा यह है कि एक एम फार्म होता है, जिसे माल उठाने या ले जाने की अनुमति मान लें... वह कितनी बार प्रयोग हो जाए कोई नहीं जानता। समझा तो यह जाना चाहिए कि जब सड़क के लिए पहाड़ की खोदाई होती है, उसमें भी पत्थर और मिट्टी जैसी सामग्री निकलती है, फिर अतिरिक्त खनन का लोभ क्यों? यह विषय इतना संवेदनशील है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नौकरशाह उद्योग विभाग में गिने चुने दिन ही काट पाए थे। कारण यह था कि किसी राजमार्ग का काम देना था। नियम यह कहते थे कि जो सबसे पहले आएगा, उसे काम मिलेगा। प्रविधान यह देखने का भी था कि अगर कोई संगठित कंपनी काम लेती है तो सरकार की चिंता पर्यावरण ही नहीं, हर दृष्टि से कम हो जाती है। दबाव ऐसा बनाया गया कि कंपनी के बजाय एक विशेष व्यक्ति को वह काम दिया जाए ताकि 'कई संबद्ध लोगों' का दरिद्र कट सके।

यह ठीक है कि विकास कार्य बिना सामग्री के नहीं होंगे। लेकिन कहीं एक रेखा तो खींचनी पड़ेगी। रेणुका-हरिपुरधार मार्ग हो या कांगड़ा जिले के बोह जैसे क्षेत्रों में दरकते पहाड़। लाहुल में आती बाढ़ हो या भागसूनाग में अतिक्रमण को हटाने आता पानी... ये सब कुछ तो कहते हैं। आखिर कौन देता है दरकने वाले क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति? विज्ञानी कह चुके हैं कि टेक्टानिक प्लेट्स के लगातार टकराने के कारण वे कमजोर पड़ चुकी हैं, इसलिए भरोसा न करें।

तो क्या यह सार निकाला जाए कि जितने पहाड़ गिरे हैं, वे सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम हैं? इससे राज्य के भूगर्भ शास्त्री पुनीत गुलेरिया सहमत नहीं हैं। तकनीकी शब्दावली से सुसज्जित उनके जवाब का सार यह है, 'मीडिया गलत सार निकाल रहा है। कुछ जगहों पर पानी पहाड़ के अंदर तक चला जाता है। पानी की कई भूमिकाएं हैं। वह ल्यूब्रिकेंट भी है। इसलिए अगर कोई पहाड़ बैठ ही गया तो इसका यह अर्थ नहीं कि वहां खनन ही कारण है। हां, ऐसे पहाड़ पर सड़क निकालते समय एलाइनमेंट का ख्याल रखना चाहिए।'

हिमाचल प्रदेश की दुविधा यह है कि यहां विकास भी चाहिए और हरियाली भी। दोनों के बीच संतुलन ही एकमात्र हल है। कागजों में हो रहा पौधारोपण अभियान काश कुछ पहाड़ों की जमीन को इस मजबूती से पकड़ ले कि पहाड़ आत्महत्या न कर सके। वरना द्विजेंद्र द्विज का कहा गूंजता रहेगा : न जाने कितनी सुरंगें निकल गईं इससे, खड़ा पहाड़ तो बस आंख का ही धोखा था।

17 अगस्त से संसदीय समिति केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पांच दिवसीय दौरा करेगी। विकास के साथ केंद्रीय सशस्त्र बलों के कामकाज की स्थितियों की समीक्षा करेगी।

उत्तराखंड

मानसून में खस्ताहाल सड़कें

उत्तराखंड में मानसून के रफ्तार पकड़ते ही चुनौती बढ़ती जा रही है। बारिश के साथ भू-धंसाव और भू-कटाव से ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकान खतरे की जद में हैं तो सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। उत्तरकाशी जिले के मस्ताड़ी गांव में कई परिवार अब अपने घरों में लौटने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल वे टेंट में रहकर जीवनयापन कर रहे हैं। गांव के लोग सरकार से विस्थापन की मांग भी करने लगे हैं। पिछले दिनों इस क्षेत्र में बादल फटने से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही प्रदेश में भूस्खलन के चलते अब भी 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। चीन और नेपाल सीमा से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करने वाले उत्तराखंड में यह स्थिति चिंताजनक ही कही जाएगी। हालत यह है कि पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग कई सप्ताह तक मलबे से अटा रहता है। यही स्थिति चमोली जिले में भारत की अंतिम पोस्ट रिमखिम को जोड़ने वाले मलारी हाईवे की भी है।

> मानसून सीजन में सड़कें खस्ताहाल हैं। हर वर्ष ये समस्या चुनौती बनती है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं तलाशा जा सका। इसके समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार हो

इस मानसून सीजन में शायद ही कोई सड़क हो जो छलनी न हुई हो। बात चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की हो, राज्य अथवा ग्रामीण सड़कों की। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही मुश्किल होती जा रही है। लेकिन इनसे भी ज्यादा खराब स्थिति ग्रामीण सड़कों की है। मलबा आने की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर सिस्टम तत्काल सक्रिय हो जाता है, लेकिन संपर्क मार्ग हफ्तों तक बंद रहते हैं। यही वजह है कि सैकड़ों गांव में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित रहती है। आलम यह है कि ग्रामीण किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने के लिए डंडी का सहारा ले रहे हैं और उन्हें कई बार 15-16 किलोमीटर की दूरी पैदल ही नापनी पड़ रही है। बात सिर्फ ग्रामीण सड़कों की ही नहीं है, शहरी क्षेत्रों में भी हालात सामान्य नहीं हैं। जगह-जगह सड़कों पर पड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। इनमें से कई सड़कें ऐसी हैं, जिनकी मरम्मत मानसून शुरू होने से पहले ही की गई।

ऐसे में सवाल उठता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में यदि छलनी सड़कों के लिए कुदरत जिम्मेदार है तो शहरों में यह जिम्मेदारी किसकी मानी जाए। सवाल यह भी है कि कंक्रीट और तारकोल से निर्मित सड़क की आयु तय होती है। ऐसे में ये सड़कें अपनी निर्धारित आयु पूरी होने से पहले कैसे खराब हो जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुदरत के कोप पर अंकुश लगाना संभव नहीं है, लेकिन डेंजर जोन और भूस्खलन प्रभावित जोन का स्थायी उपचार कर समस्या से निजात पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की जरूरत है।

बिहार

प्रभावी बने ग्राम कचहरी

प्रदेश में ग्राम कचहरी को और भी अधिक शक्तियां देने का विचार स्वागत योग्य है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि गांव-देहात के साधारण मामलों को थाने तक न ले जाना पड़े। ऐसे मामलों की सुनवाई यदि ग्राम कचहरी में होगी, तो निश्चय ही थानों और निचली अदालतों पर केस का दबाव घटेगा। इससे गांवों में मैत्रीपूर्ण माहौल बनाने में सुविधा होगी। राज्य सरकार इस दिशा में प्रभावी निर्णय ले रही है, लेकिन अभी तक अधिसंख्य ग्राम कचहरी अपने दायित्वों के पालन में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पा रही हैं।

ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने के लिए न्याय मित्रों को और अधिक सक्रिय-प्रभावी होना चाहिए। इसी तरह सरपंच, उपसरपंच व पंचों को अपने कर्तव्य-दायित्व को ठीक से समझना होगा। सभी थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर और मुंशी को भी ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इसे नियमित रूप देने की जरूरत है। अभी ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र के बहुत से मामले थानों व निचली अदालतों में अर्से से लंबित हैं। ऐसे मामलों को यथाशीघ्र ग्राम कचहरी

ग्रामीण परिवेश को बेहतर बनाने में ग्राम कचहरी की अहम भूमिका होती है। फाइल

> ग्राम कचहरी को अधिकार संपन्न बनाने से ग्रामीण न्याय व्यवस्था सशक्त होने के साथ ही गांवों में मैत्रीपूर्ण परिवेश निर्मित करने में सुविधा होगी

को हस्तांतरित कर देना चाहिए। पुलिस अधीक्षकों को सरकार ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दे रखा है। सभी को इसका सही से अनुपालन करने की जरूरत है। पुलिस यदि ग्राम कचहरी का भरपूर सहयोग करे तो मामलों के निष्पादन में काफी तेजी आएगी और थानों पर पड़ने वाला अनावश्यक बोझ कम होगा। सरकार की यही मंशा भी है। देखा जाए तो गांवों में शिक्षा की कमी एवं गरीबी के कारण आए दिन विवाद होते रहते हैं। यदि आपसी सहमति से मामला हल नहीं हुआ तो संबंधित ग्रामीण थाना का चक्कर लगाते-लगाते जटिल कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं। बाद में चाहते हुए भी आपस में समझौता नहीं कर पाते। गांव के लोगों को इस स्थिति से बचाने में ग्राम कचहरी महती भूमिका निभा सकती है। उसे विभिन्न धाराओं के तहत कई कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। इसका न्याय संगत ढंग से उपयोग करना चाहिए। ग्राम कचहरी को दायित्व है कि पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण परिवेश में समझौता कराए ताकि ग्रामीणों की मेहनत की कमाई का पैसा कानून की जटिल प्रक्रियाओं पर खर्च होने की जगह उनके विकास पर खर्च हो।

बंगाल

उफान पर नदियां व बाढ़ का बढ़ता कहर

भारी बारिश और विभिन्न बांधों से छोड़े गए जल से बंगाल कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। विभिन्न जिलों के सैकड़ों गांवों में पानी भर जाने से दीवार गिरने और करंट लगने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छह जिलों के करीब ढाई लाख लोग राहत शिविरों में समय काटने को मजबूर हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि राहत व बचाव कार्य में राज्य सरकार को सेना व राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की मदद लेनी पड़ रही है। पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना जिले के अनेक स्थानों में कमर तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियां उफान पर हैं जो बांध तोड़कर गांवों पर कहर बरपा रही है। कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए वायुसेना के हेलीकाप्टर बचाव में लगे हुए हैं।

> प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं जो बांध तोड़कर कहर बरपा रही हैं। कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए वायुसेना के हेलीकाप्टर बचाव कार्य में लगे हैं

हुगली जिले में हालात बद से बदतर है। यहां गर्दन तक पानी भर चुका है। भारी बारिश के कारण रूपनारायण नदी ने बांध तोड़ दिया है और उसका पानी गांवों में घरों तक जा पहुंचा है। कई लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं।

दरअसल, भारी बारिश की वजह से दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के विभिन्न बांधों से भी पानी छोड़ना पड़ रहा है। एक तो बारिश और दूसरा बांधों से छोड़े गए पानी से हावड़ा और हुगली दोनों जिलों में बाढ़ आ गई है। ऐसी स्थिति हर वर्ष उत्पन्न होती है। परंतु, लगभग हर साल आने वाली बाढ़ की इस समस्या से निजात पाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर साल बाढ़ आने पर केंद्र सरकार और डीवीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) या फिर झारखंड के डैमों से जल छोड़ने को लेकर मुखर होती रही हैं और केंद्र पर आरोप लगाती रही है कि डैमों की ड्रेजिंग नहीं होने की वजह से उनकी जल धारण क्षमता कम हो गई है। इसी वजह से डैम से पानी छोड़ना पड़ रहा है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। परंतु, राज्य सरकार की ओर से इस बाढ़ को रोकने के लिए अब तक क्यों नहीं एक भी कदम उठाए गए? इस सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। हर साल बाढ़ आती है और केंद्र को कोसकर खूब राजनीति होती है और बाद में वही यथास्थिति हो जाती है। अगर सामंजस्य बैठाकर केंद्र के साथ योजना बनाई गई होती और उस पर अमल किया गया होता तो शायद यह स्थिति नहीं होती। यदि समय रहते समाधान की कार्ययोजना तैयार करते हुए काम शुरू हो तो अगले साल इससे बचाव हो सकता है।

उत्तर प्रदेश

रिकार्ड टीकाकरण

उत्तर प्रदेश ने कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को 21.99 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का शानदार रिकार्ड बनाया है। इसके साथ पांच करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसके पहले एक दिन में 10.29 लाख डोज देने का रिकार्ड भी उत्तर प्रदेश ने ही बनाया था। महाअभियान के लिए जिस तरह केंद्रों को तैयार किया गया था, उसके बाद इसी तरह से सुखद परिणाम आने की उम्मीद थी। इसके पहले, जून में भी एक करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तीन हफ्ते में ही पूरा कर लिया गया था। तब, उत्साहित सरकार ने जुलाई के पहले हफ्ते में प्रतिदिन 10 लाख और उसके बाद रोजाना 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था। हालांकि, वैक्सीन की अपेक्षित आपूर्ति नहीं होने से जुलाई में कुल तीन करोड़ लोगों के टीकाकरण का सपना साकार नहीं हो पाया।

रिकार्ड टीकाकरण से महामारी के खिलाफ लड़ाई में मानसिक मजबूती बेशक मिली है लेकिन, अभी

कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत प्रदेश ने कायम किया नया रिकार्ड। फाइल

कई चुनौतियों से पार पाना बाकी भी है। बड़ी चुनौती यही है कि प्रदेश में दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी कैसे हो। सोमवार तक प्रदेश के मात्र 78.65 लाख लोगों ने ही दोनों डोज लगवाए थे। इसी कारण विशेष अभियान के दौरान दूसरा डोज लेने वालों को खास तौर पर आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया था मगर, इसके अपेक्षित परिणाम नहीं दिखे। दूसरा डोज लेने के लिए 1.70

> सरकार के साथ-साथ जनता को भी यह ध्यान रखना होगा कि कोरोना महामारी को तभी निढाल किया जा सकेगा, जब सबको टीका लग जाएगा

लाख लोग ही प्रोत्साहित किए जा सके। इतने से कतई संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। आइआइटी कानपुर के विज्ञानी भी चेता चुके हैं कि अगर शारीरिक दूरी और मास्क की अनिवार्यता का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। हालांकि, अभी डरने वाली बात नहीं है क्योंकि प्रदेश में कोरोना की कमर धीरे-धीरे टूटती जा रही है। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में 57 जिले ऐसे हैं, जहां 10 से कम रोगी हैं। बावजूद इसके, सरकार के साथ-साथ जनता को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना महामारी को तभी निढाल किया जा सकेगा, जब सबको टीका लग जाएगा।

श्रद्धा का महासावन

शिव और सोमवार

भगवान शंकर की उपासना हर दिन अलग फल प्रदान करती है। शिवमहापुराण के अनुसार स्वास्थ्य, संपत्ति, रोग नाश, पुष्टि, आयु, भोग और मृत्यु की हानि के लिए रविवार से लेकर शनिवार तक भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। सभी वारों में जब शिव फलप्रद हैं तो फिर सोमवार का आग्रह क्यों? ऐसा लगता है मनुष्य मात्र ने संपत्ति से अत्यधिक प्रेम होने के कारण शिव के लिए सोमवार का चयन किया। पुराणों के अनुसार सोम का अर्थ चंद्रमा है और चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पर अत्यंत सुशोभित होता है। भगवान शंकर ने कुटिल, कलंकी, कामी, वक्री एवं क्षीण चंद्रमा को अपराधी होते हुए भी क्षमा कर अपने शीष पर स्थान दिया। वैसे ही भगवान हमें भी सिर नहीं तो चरणों में जगह अवश्य देंगे। यह याद दिलाने के लिए सोमवार को लोगों ने शिव का दिन बना दिया। सोम का अर्थ सौम्य भी होता है। भगवान शंकर अत्यंत शांत समाधिस्थ देवता हैं। इस सौम्य भाव को देख भक्तों ने उन्हें सोमवार का देवता मान लिया। सहजता एवं सरलता के कारण ही उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। सोम का एक अर्थ होता है उमा के सहित शिव। केवल कल्याणकारी शिव की उपासना न करके साधक शक्ति की भी साथ में उपासना करना चाहता है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव का रहस्य समझना संभव नहीं। इसलिए भक्तों ने सोमवार को शिव का वार स्वीकृत किया। सोम में ऊं समाया हुआ है। शिव ओंकार स्वरूप हैं। ओंकार की उपासना के द्वारा ही साधक अद्वय स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए इस अर्थ के विचार के लिए भगवान शिव को सोमवार का देव कहा जाता है।

स्वामी यतींद्रानंद गिरि
महामंडलेश्वर, श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़ा, रुड़की

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

परीक्षण के लिए समुद्र में उतरा स्वदेश निर्मित पहला विमानवाहक पोत 'विक्रांत'

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत 'विक्रांत' का समुद्र में बहुप्रतीक्षित परीक्षण बुधवार को शुरू हो गया। नौसेना ने इस अवसर को देश के लिए गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक करार दिया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है, जिसके पास स्वदेश में डिजाइन, निर्माण और अत्याधुनिक विमानवाहक जहाज तैयार करने की विशिष्ट क्षमता है।

विमानन परीक्षण पूरा होने के बाद 'विक्रांत' को अगले साल की दूसरी छमाही में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, 'यह भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि वर्ष 1971 के युद्ध में जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हमनाम शानदार पूर्ववर्ती पोत के 50वें साल में आज यह पहली समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ।' 'विक्रांत' नामक एक पोत ने 50 साल पहले वर्ष 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। कमांडर मधवाल ने कहा कि यह 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल का एक गौरवशाली क्षण है।

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, अरब सागर में विक्रांत का चार दिनों तक परीक्षण चलेगा। इसके डिजाइन पर काम वर्ष 1999 में शुरू हुआ था, जबकि फरवरी 2009 में निर्माण को शुरुआत हुई थी। दिसंबर 2020 में बुनियादी परीक्षण पूरे हुए।

भारत के पास अभी सिर्फ एक विमानवाहक जहाज आइएनएस विक्रमादित्य है। भारतीय नौसेना, हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की चीन की बढ़ती कोशिशों के मद्देनजर समग्र रूप में अपनी क्षमता बढ़ाने पर बल दे रही है। हिंद महासागर, देश के रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत का समुद्री परीक्षण बुधवार को शुरू हो गया। एएनआइ

देश के लिए बड़ी उपलब्धि : मंत्री

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। आधिकारिक बयान के अनुसार, सोनोवाल ने कहा कि विक्रांत का समुद्री परीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' व 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का प्रतिबिंब है। पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्री ने कोचीन शिपयार्ड व भारतीय नौसेना को देश को गौरवान्वित करने के लिए बधाई दी।

प्रमुख विशेषताएं

- देश में निर्मित सबसे बड़ा व जटिल युद्धपोत है 'विक्रांत'
- 40,000 टन है इस युद्धपोत का वजन
- 23,000 करोड़ रुपये की लागत से किया गया निर्माण
- 262 मीटर लंबाई व 62 मीटर चौड़ाई व 59 मीटर है ऊंचाई
- 30 लड़ाकू विमान व हेलीकाप्टर किए जा सकते हैं तैनात
- मिग-29 लड़ाकू विमानों व केए-31 हेलीकाप्टरों का एक बेड़ा तैनात रहेगा
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है निर्माण
- 1,500 अधिकारियों व जवानों को किया जाएगा तैनात

रेलवे का होगा अपना अलग मोबाइल सिस्टम

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

ट्रेन संचालन से जुड़े रेलकर्मियों के हाथों में वाकी टाकी बहुत जल्द ही बीते दिनों की बात होने जा रही है। रेल प्रशासन मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार सेवा शुरू करने जा रहा है। इससे आपसी संवाद बेहतर होगा, जिससे ट्रेनों के संचालन में सुगमता होगी। इससे वीडियो कालिंग भी की जा सकेगी।

रेलवे ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारियों को आपस में संपर्क एवं बातचीत करने के लिए वाकी-टाकी उपलब्ध कराता है। वाकी टाकी सिस्टम में केवल ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारी ही वार्ता कर सकते हैं। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा : रेलवे ने वाकी टाकी को बंद कर ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मियों को आधुनिक संचार सिस्टम देने की योजना बनाई है। इसके लिए लांग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार सेवा शुरू करने जा रहा है। यह मोबाइल की भांति ही होगा। इस सिस्टम में भी बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। एक साथ कई कर्मचारी आपस में वार्ता कर सकते हैं। इसके द्वारा कर्मचारी वीडियो काल कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर कई कर्मचारी आपस में वीडियो कांफ्रेसिंग भी कर सकते हैं। इसके द्वारा आपस में डाटा भी भेजा जा सकता है। इसमें नेटवर्क गायब व लाइन व्यस्त होने की कोई समस्या नहीं होगी। रेलवे मंत्रालय ने देश भर में इस सिस्टम को लगाने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस योजना को पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए रेलवे ने सात सौ मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में पांच मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लेने की मंजूरी दी है। इससे ही सिस्टम चलेगा।

वाकी-टाकी

- केवल वार्ता करने की सुविधा
- एक बार में एक ही कर्मचारी बोल सकता है।
- अन्य कर्मचारी भी दूसरे कर्मचारी की आवाज सुन सकते हैं।

मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार सेवा

- काल करने की सुविधा, वाकी टाकी से वजन में हल्का
- वीडियो कालिंग व वीडियो कांफ्रेंसिंग की होगी सुविधा
- इस सिस्टम से डाटा भेजने की भी होगी सुविधा

श्रद्धालु 2023 के अंत तक कर सकेंगे रामलला के दर्शन

जासं, अयोध्या : रामभक्त 2023 के अंत तक अयोध्या के भव्य-दिव्य भवन में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। श्रीराम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष पांच अगस्त को भूमि पूजन किया था। मंदिर की नींव की 27 लेयर तैयार हो चुकी है, जबकि 44 लेयर में नींव भराई की जानी है। हालांकि, मंदिर संपूर्ण परिसर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होने की संभावना है। परिसर में संग्रहालय, डिजिटल अभिलेखागार, शोध केंद्र व रामकथा कुंज आदि का निर्माण भी किया जाना है। संपूर्ण परिसर का क्षेत्रफल करीब 70 एकड़ है, जबकि मंदिर का निर्माण पांच एकड़ में होगा।

वैकल्पिक गर्भगृह में विराजमान : रामंमंदिर के भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण के लिए रामलला को परिसर में ही वैकल्पिक गर्भगृह में विराजमान कराया गया था, जहां पूरी शास्त्रीयता और विधि-विधान से भगवान का पूजन किया जाता है। गत वर्ष 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें वैकल्पिक गर्भगृह में विराजमान कराया था। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर निर्माण के लिए मीरजापुर (उप्र) एवं बंसी पहाड़पुर (भरतपुर, राजस्थान) से पत्थर आए हैं।

लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाकर रचा इतिहास

राज्य ब्यूरो, जम्मू

पड़ोसी देश चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम बना रही भारतीय सेना को और मजबूत बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पूर्वी लद्दाख में 19300 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर विश्व कीर्तिमान बना दिया है। अब इस सड़क से सेना के टैंक और तोप उमलिंगला दर्रे को पार कर जल्द दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चुमार सेक्टर में पहुंच सकेंगे। बहुत ही दुर्गम इलाके में बनी यह सड़क 52 किलोमीटर लंबी है।

यह सड़क पूर्वी लद्दाख के दूरदराज इलाकों में विकास की नई उम्मीद भी लेकर आई है। इसके बनने से चीसुमले व डैमचोक इलाके में लोगों की आर्थिक व सामाजिक बेहतरी के साथ पर्यटन के नए मार्ग भी खुलेंगे। सर्दियों में इस इलाके में तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। आक्सीजन का स्तर भी सामान्य से 50 फीसद कम होता है। इन हालात में सीमा सड़क संगठन ने सड़क बनाकर अपने बुलंद हौसले का परिचय दिया है। इतना ही नहीं, उसने बोलीविया को पीछे छोड़ भारत को पहले नंबर ला खड़ा किया है। बोलीविया ने उतरुन्कू ज्वालामुखी तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए 18,953 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाई थी।

बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में 19300 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाई है। सौ. पीआइबी

भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में होगी और मजबूत : यह सड़क रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इसके बनने से भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में और मजबूत होगी। चीन को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना का मजबूत होना खटकता है। यही कारण है कि वह नहीं चाहता कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करे।

भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने की तैयारी : चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 16 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित चुमार सेक्टर में कई बार विवाद पैदा कर चुका है। कुछ साल पहले दोनों देशों की सेनाएं इस सेक्टर में 16 दिन आमने-सामने खड़ी रही थीं। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब अपना बुनियादी ढांचा मजबूत किया है।

प्रख्यात लेखिका पद्मा सचदेव का मुंबई में निधन

राज्य ब्यूरो, मुंबई

डोगरी की कवयित्री एवं हिंदी की कई विधाओं की प्रख्यात लेखिका पद्मा सचदेव का बुधवार सुबह मुंबई में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 10 बजे मुंबई के जोगेश्वरी (पश्चिम) में किया जाएगा।

पद्मश्री एवं साहित्य अकादमी सहित कई साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित 81 वर्षीय लेखिका पिछले कुछ समय से कई बीमारियों से ग्रस्त थीं। वह मुंबई में अपनी बेटी के साथ रह रही थीं। उनके निधन की खबर आने के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा एवं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई साहित्यकारों ने शोक व्यक्त किया है। 1940 में जम्मू के पुरमंडल गांव में संस्कृत विद्वान जयदेव बादू के घर में जन्मी पद्मा सचदेव की डोगरी में लिखी पहली कविता उनकी 14 वर्ष की उम्र में ही प्रकाशित हो गई थी। 1966 में उनका विवाह शास्त्रीय गायक सुरिंदर सिंह से हुआ था। डोगरी में उनके आठ कविता संग्रह, तीन गद्य की पुस्तकें एवं हिंदी की विभिन्न विधाओं में 19 किताबें प्रकाशित हैं। उनकी 11 अनूदित कृतियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी फिल्मों के लिए भी उन्होंने कुछ गीत लिखे थे। उन्हें 2001 में पद्मश्री एवं 2007-08 में मध्य प्रदेश सरकार के कबीर सम्मान से नवाजा गया था।

डोगरी गीतों में जिंदा रहेंगी जम्मू दी 'बोबो'

स्मृति शेष

जागरण संवाददाता, जम्मू

तूं मल्ला तूं, लोक पनन ठिकरियां, बादाम पन्ने तूं...। डोगरी के इस विख्यात गीत को शायद ही डुग्गर प्रदेश की किसी मां ने अपने लाडले को सुलाते हुए लोरी के रूप में न सुनाया हो। लता मंगेशकर के गाए डोगरी गीत को लिखने वाली जम्मू की प्रख्यात लेखिका, साहित्यकार व कवयित्री पद्मश्री पद्मा सचदेव का बुधवार को निधन हो गया। जम्मू में इन्हें 'बोबो' यानी बड़ी बहन नाम से भी जाना जाता था। तड़के करीब 4.30 बजे मुंबई में अपने निवास पर उनकी हृदय गति रुक गई। उनके परिवार में पति शास्त्रीय गायक सुरेंद्र पाल सिंह सचदेव और बेटे तेजपाल सिंह सचदेव और बेटी मीता सचदेव शामिल हैं। इसकी जानकारी उनके छोटे भाई साहित्यकार ज्ञानेश्वर शर्मा ने दी।

पद्मा सचदेव अपनी डोगरी मातृभाषा से काफी प्यार था। डोगरी भाषा, साहित्य और संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने में इनका योगदान सराहनीय रहा है। डोगरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए हुए

डोगरी की विख्यात साहित्यकार पद्मश्री पद्मा सचदेव। फाइल फोटो। जागरण आर्काइव

संघर्ष में वह हमेशा कंधे से कंधा मिला कर चलती रहीं। उन्होंने साहित्यिक सफर बेशक कविता से किया पर कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, अनुवाद से लेकर लगभग हर विधा में खूब लिखा। जम्मू वालों को उनसे हमेशा बड़ी बहन का प्रेम मिला। इसलिए अधिकतर लोग उन्हें जहां भी मिलते बोबो बड़ी बहन कर संबोधित करते और वह भी दिल से हर डोगरे से बड़ी बहन की तरह ही मिलती थीं।

उनके पिता पंडित जयदेव शर्मा हिंदी, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। जम्मू में स्कूल के समय से ही कविता के क्षेत्र में विशेष पहचान बना ली थी। उसके बाद कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक कार्यक्रमों में डोगरी का प्रतिनिधित्व किया। उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। किंतु 'मेरी कविता मेरे गीत' के लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2007-08 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान दिया। उनकी पहली शादी डोगरी के गजल सम्राट वेद पाल दीप से हुई लेकिन किन्हीं कारणों से वह ज्यादा देर साथ नहीं रह सके। वर्ष 1966 में सिंह बंधु नाम से प्रचलित सांगीतिक जोड़ी के गायक सुरिंदर सिंह से हुई। पद्मा रेडियो कश्मीर जम्मू में स्टाफ आर्टिस्ट रहीं बाद में दिल्ली रेडियो में डोगरी समाचार वाचिका की जिम्मेदारी भी निभाई। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी उन्हें सम्मानित किया। जम्मू का शायद ही कोई साहित्यिक या सांस्कृतिक संगठन ऐसा होगा जिसने उन्हें सम्मानित न किया हो। उनके निधन का समाचार सुनते ही जम्मू के साहित्य, कला जगत में शोक की लहर है। उन्हीं के कहने पर लता मंगेशकर ने डोगरी के कुछ गीत गाए, जो आज डोगरी की संस्कृति की पहचान हैं। उनके जाने के बाद अब वे गीत ही उनकी पहचान बनकर हमेशा उनके व्यक्तित्व को जीवित रखेंगे।

4 राज्यों में अमेरिका के आरएसवी (रेस्पिरेटरी सीनसीटियल वायरस) के मरीज मिल चुके हैं अब तक। इनमें दो हफ्ते से लेकर 17 साल के बच्चे शामिल हैं। इस वायरस से श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं।

सेना और तालिबान के बीच भीषण संघर्ष, 274 आतंकी मारे गए

अफगानिस्तान में तनाव ▶ काबुल में कार बम धमाके में आठ की मौत, 20 घायल

तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, उपराष्ट्रपति भी शामिल हुए

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शक्तिशाली बम विस्फोट के बाद अफगान सेना ने तालिबान आतंकियों पर जबर्दस्त हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 274 आतंकी मारे गए हैं। काबुल में कार बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या आठ हो गई है। यहां बीस लोग घायल हुए हैं। आतंकी कार्यवाहक रक्षा मंत्री बिसमिल्लाह मोहम्मदी की हत्या करने के लिए आए थे। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में चारों आतंकियों को मार गिराया।

पुलिस के मुताबिक, काबुल के ग्रीन जोन में आतंकियों ने पहले कार बम विस्फोट किया। इसके बाद कार्यवाहक रक्षा मंत्री के घर की ओर चार आतंकी फायरिंग करते हुए बढ़े, जिन्हें मार गिराया गया। हमले के बाद अफगान सेना ने रात में ही कई स्थानों पर हमले किए। विदेश मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में 274 आतंकियों को मार गिराने के साथ ही 119 आतंकी घायल हुए हैं। एएनआइ के अनुसार जौजान प्रांत में हवाई हमले में 21 आतंकी मारे गए।

काबुल में कार्यवाहक रक्षा मंत्री के घर के पास हुए विस्फोट के बाद घटना स्थल का निरीक्षण करते सुरक्षाकर्मी। एपी

तालिबान के साथ लड़ रहे हैं कई आतंकी संगठन

एएनआइ के अनुसार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अफगानिस्तान में विशेष प्रतिनिधि और अन्य देशों के राजदूतों के साथ बैठक की। इस बैठक में बताया कि दस हजार विदेशी आतंकी पाकिस्तान की सरपरस्ती में तालिबान के साथ मिलकर सेना से युद्ध कर रहे हैं। इन संगठनों में अलकायदा, टीटीपी, इस्लामिक स्टेट सहित एक दर्जन आतंकी संगठन हैं।

विस्फोट के बाद हजारों नागरिक सड़कों पर उतर आए

एएनआइ के अनुसार, काबुल में बम विस्फोट के बाद हजारों नागरिक सड़कों पर उतर आए। महिलाओं ने मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। सड़कों पर उतरे अफगान नागरिकों ने आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस रैली में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी भाग लिया। रैली में तालिबान और उनको ताकत देने वाले पाकिस्तान के नेताओं को फांसी देने की मांग की जा रही थी।

काबुल में सरकार के समर्थन में रैली निकालते लोग। रायटर

पाक आतंकियों ने खाली पड़े सेना के कैंपस पर कब्जा किया

एएनआइ के अनुसार पाकिस्तानी आतंकियों ने नूरिस्तान के कामदेश जिले में अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज के खाली पड़े कैंपस पर कब्जा कर लिया है। टाइम्स आफ इजरायल में प्रकाशित खबर के अनुसार, यहां पर रोज पचास आतंकी बढ़ रहे हैं। ये तालिबान के साथ मिलकर अफगान सेना से युद्ध कर रहे हैं।

आइएस ने काबुल के निकट अपनी स्थिति मजबूत की

प्रेट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट (आइएस) काबुल और उसके आसपास के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। तालिबान की यदि अफगान सरकार के साथ वार्ता के परिणाम नहीं निकलते हैं तो आइएस काबुल और उसके आसपास अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों पर हमले तेज कर सकता है। तालिबान ने इसीलिए विदेशी आतंकवादियों के जमावड़े को तेज कर दिया है।

तालिबान ने की सलमा बांध को बम से उड़ाने की कोशिश

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाए गए सलमा बांध को तालिबान आतंकियों ने बम से उड़ाने की कोशिश की। अफगान सेना ने आतंकियों की इस कोशिश को विफल कर दिया है। यहां सेना और आतंकियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। रक्षा मंत्री के प्रवक्ता फवाद अमान ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हेरात प्रांत में बने सलमा बांध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस बांध को भारत ने बनाया है, इसीलिए इसे भारत-अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहा जाता है। अमान ने कहा कि यहां अफगान सेना के जवाबी हमले में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। पिछले महीने भी तालिबान आतंकियों ने सलमा बांध पर हमले की कोशिश की थी। बांध के नजदीक ही राकेट के हमले और बम बरसाए गए थे। उल्लेखनीय है कि यह बांध हेरात शहर से 165 किलोमीटर दूर चिश्ती शरीफ जिले में बना हुआ है। भारत के बनाए इस बांध की क्षमता 64 करोड़ क्यूबिक मीटर जल भंडारण की है। इस बांध के माध्यम से यहां की दो लाख एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। हाल के वर्षों में यह अफगानिस्तान में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इस पर 1700 करोड़ रुपये लागत आई थी। तालिबान भारत की अन्य परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।

यूएनएससी इस्लामिक अमीरात का नहीं करती है समर्थन

▶ भारत की अध्यक्षता वाली सुरक्षा परिषद ने की हिंसा की आलोचना

न्यूयार्क, प्रेट्र : भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रही हिंसा और नागरिकों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने घोषणा की है कि वह अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की बहाली को अपना समर्थन नहीं देगी।

भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने बकौल परिषद के अध्यक्ष पत्रकार वार्ता में एक बयान भी जारी किया। इसका सभी पंद्रह सदस्य देशों ने समर्थन किया है। इस वक्तव्य में कहा गया है कि अफगान समस्या का हल हिंसा नहीं है। तालिबान और अफगान सरकार दोनों से ही वार्ता से हल निकालने की अपील की गई है। यूएनएससी ने अफगानिस्तान में 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन परिसर पर हुए हमले की भी निंदा की। इस हमले में एक गार्ड की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद

टीएस तिरुमूर्ति का फाइल फोटो। एएनआइ

अफगान समस्या का हल एक न्याय संगत और यथार्थवादी राजनीतिक समझौते में देखती है। सुरक्षा परिषद ने महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा पर भी बल दिया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने ट्वीट कर कहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विशेष सत्र बुलाने पर बात की है।

न्यूज गैलरी

अमेरिका में सड़क हादसे में सिख ड्राइवर की मौत

वाशिंगटन : अमेरिका के एरीजोना राज्य में एक 37 वर्षीय भारतीय ट्रक ड्राइवर की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। व्यस्त हाईवे पर यह भारी वाहन अपना संतुलन खो बैठा था। भारतीय ड्राइवर निर्मल सिंह हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। वह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। वह इंडियाना में रहता था जोकि सालों से अमेरिका में सिख ड्राइवरों का गढ़ माना जाता है। निर्मल सिंह की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि उसका सहयोगी राहुल अभी भी स्थानीय अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। राहुल अंबाला का रहने वाला बताया जाता है। (प्रेट्र)

23 लाख डालर के घपले के लिए भारतीय गिरफ्तार

वाशिंगटन : जांच एजेंसियों ने 23 लाख डालर के एक घपले में आरोपित भारतीय नागरिक आशीष बजाज (28) को न्यूजर्सी से गिरफ्तार कर लिया है। उसने यह धांधली अमेरिकी बुजुर्गों के बैंक खाते से की थी। आरोपित आशीष को उत्तरी कैलीफोर्निया की अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज जोइ एल.वेबस्टर की संघीय अदालत में पेश किया गया। इन आरोपों के चलते आशीष बजाज पर अधिकतम बीस साल की कैद या फिर 2.50 लाख डालर का जुर्माना लग सकता है।

भारतीय मूल के अजय दिलवारी कनाडा में सम्मानित

ओटावा : भारतीय मूल के प्रमुख कारोबारी अजय दिलवारी को कनाडा के प्रतिष्ठित अवार्ड 'आर्डर आफ ब्रिटिश कोलंबिया' से सम्मानित किया गया है। वह आटोमोटिव समूह दिलवारी ग्रुप के मालिक हैं। ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार के मुताबिक दिलवारी उन 16 दुनिया व्यक्तियों में शामिल हैं जिसे इस सम्मान से नवाजा गया है। चांसलर आफ द आर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर जेनेट आस्टिन ने कहा कि वह ब्रिटिश कोलंबिया के क्राउन के प्रतिनिधियों में दिलवारी को शुमार करते हैं। (प्रेट्र)

मलेशिया के प्रधानमंत्री यासिन का इस्तीफे से इन्कार

क्वालालंपुर : मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहीद्दीन यासिन ने अल्पमत की सरकार के बावजूद इस्तीफा देने से इन्कार कर दिया है। बुधवार को उनके सहयोगी दल ने समर्थन वापस ले लिया है। यासिन ने कहा कि वह संसद में अगले महीने अपनी सरकार का विश्वास मत हासिल करेंगे। महल में किंग सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह बैठक करेंगे। 38 सांसदों की युनाइटेड मलय नेशनल आर्गेनाइजेशन गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। (एपी)

अगालेगा द्वीप पर नौसैनिक अड्डा बना रहा भारत : रिपोर्ट

दुबई : अरब के एक मीडिया संगठन ने दावा किया है कि भारत दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में सुदूर मारीशस द्वीप अगालेगा पर नौसैन्य प्रतिष्ठान का निर्माण कर रहा है। संगठन ने मंगलवार को उपग्रह चित्रण, वित्तीय डाटा और एकत्रित जमीनी साक्ष्य का हवाला देते हुए यह दावा किया। कतर के अल जजीरा समाचार चैनल ने एक रिपोर्ट में कहा,जिन सैन्य विशेषज्ञों ने जांच इकाई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का विश्लेषण किया है, उनका कहना है कि अगालेगा में निर्माणाधीन हवाई पट्टी का उपयोग निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री गश्ती मिशन के लिए किया जाएगा। अगालेगा, लगभग 12 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा द्वीप है। मारीशस के मुख्य द्वीप से 1,100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस द्वीप पर 300 लोग रहते हैं। इस रिपोर्ट के संबंध में भारतीय नौसेना की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। (प्रेट्र)

न्यूयार्क के गवर्नर ने किया 11 महिलाओं का यौन उत्पीड़न

न्यूयार्क टाइम्स से

▶ अटार्नी जनरल की जांच रिपोर्ट से कुओमो का राजनीतिक भविष्य दांव पर

▶ राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए

न्यूयार्क : अमेरिका में न्यूयार्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो पर यौन उत्पीड़न के संबंध में चल रही जांच पूरी हो गई है। यह रिपोर्ट उनके सियासी भविष्य को गर्त में ले जाने वाली साबित हो सकती है। राज्य अटार्नी जनरल लेटीटिआ जेम्स द्वारा दी गई 165 पेज की जांच रिपोर्ट में वर्तमान न्यूयार्क गवर्नर पर मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों सहित 11 महिलाओं के यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। स्टेट असेंबली के स्पीकर ने कहा है कि वह महाभियोग चलाने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें अब पद पर रहने का अधिकार नहीं है।

न्यूयार्क गवर्नर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की जांच पांच माह से चल रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नर कार्यालय का माहौल काम करने योग्य नहीं रहा है, यहां नहीं उत्पीड़न का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने वाली पहली महिला के खिलाफ बदले की भावना से भी कार्रवाई की गई। उन पर कई महिलाओं ने

एंड्रयू कुओमो। फाइल इंटरनेट मीडिया

गलत नीयत से छूने, छेड़छाड़ और किस करने आदि के आरोप लगाए हैं।

लेटीटिआ जेम्स की जांच रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रपति बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता एंड्रयू कुओमो को गवर्नर पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है। 63 वर्षीय एंड्रयू ने एक वीडियो के माध्यम से बयान जारी कर आरोपों को नकारते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की है। एंड्रयू का गवर्नर पद पर यह तीसरा कार्यकाल है। वह लगातार 2011 से पद पर बने हुए हैं।

वायुसेना प्रमुख भदौरिया इजरायल दौरे पर

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया तीन दिनी दौरे पर इजरायल में हैं। इस दौरान वह दोनों देशों वायु सेनाओं के बीच की रणनीतिक साझेदारी व द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भदौरिया मंगलवार को यूएई से इजरायल पहुंचे हैं। उन्हें उनके प्रतिपक्षी मेजर जनरल अमिकम नोरकिन ने आमंत्रित किया था। पश्चिम एशिया में भारत के इजरायल और यूएई दोनों ही देशों से रणनीतिक साझेदारी है।

सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना प्रमुख की यह यात्रा दोनों रणनीतिक साझेदार देशों के बीच एक सामान्य व्यावसायिक आदान-प्रदान का हिस्सा है। यह यात्रा पिछले साल ही होनी थी लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें देर हो गई। वैश्विक महामारी के हालात में भी दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख यहां रक्षा सहयोग के हालात की समीक्षा करने के लिए आए हैं। भारतीय वायुसेना का कहना है कि बतौर रणनीतिक साझेदार भारत और इजरायल मजबूत, बहुआयामी रक्षा सहयोग और सैन्य स्तरीय आदान-प्रदान करते हैं। दोनों देश रक्षा सहयोग में मजबूत स्तंभ हैं।

अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार बरकरार

▶ अफगानिस्तान और चीन को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद जारी

▶ अमेरिका में पाकिस्तानी अफसरों की बैठक में रही बेनतीजा

वाशिंगटन, एएनआइ : पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मोइद योसुफ और खुफिया एजेंसी आइएसआइ के डीजी लेफ्टिनेंट फैज हमीद के प्रयासों के बावजूद इस्लामाबाद और वाशिंगटन के संबंध बेहद नाजुक दौर में हैं।

द नेशन ने कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के इन दोनों आला अधिकारियों ने अमेरिकी प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। लेकिन अफगानिस्तान और चीन को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेदों के चलते अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की तल्खियां अभी दूर नहीं हो सकी हैं।

सूत्रों ने बताया कि बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ट्वीट में अफगानिस्तान पर पूरा ध्यान केंद्रित था। लेकिन डा.मोइद योसुफ के ट्वीट में अफगानिस्तान का कोई जिक्र तक नहीं था। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच अफगानिस्तान और चीन को लेकर तनावपूर्ण संबंधों के कारण बैठकों का कोई सकारात्मक रास्ता नहीं निकला है।

अमेरिका ने पाकिस्तान से तालिबान पर दबाव डालने को कहा है जबकि पाकिस्तानी पक्ष ने कहा कि उनका तालिबान पर कोई वश नहीं है। यह घटनाक्रम तब है जब पाक सेना आतंकी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों के लिए सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराती है।

तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की मदद से नानगढ़ प्रांत में बहुत बड़े हमले किए हैं। साथ ही सीमावर्ती जिलों की कुछ सुरक्षा चौकियों जैसे आचिन और पाचेर वा अगम पर फिर से कब्जा कर लिया है। हीसरक, शेरजाद, पाचेर वा अगम, देह बाला (हस्का मीना), आचिन और सुरखरोद जिलों में तालिबानी हमले बढ़ गए हैं। तालिबान और उसके अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के घायल आतंकियों का इलाज क्वेटा शहर में हो रहा है।

ओमान की खाड़ी से हाईजैक किए ब्रिटेन के जहाज को छोड़ा

फुजैरा, एपी : ओमान की खाड़ी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तट के पास हाईजैक किए गए ब्रिटिश जहाज एजफाल्ट प्रिंसेज को छोड़ दिया गया है। इससे पहले जहाज को हाईजैक करके अज्ञात स्थान पर ले जाने की जानकारी मिली थी।

ब्रिटेन की नौसेना ने कहा है कि जहाज को ओमान की खाड़ी में छोड़ दिया गया है। अभी यह साफ नहीं है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ था। मेरीटाइम इंटेलीजेंस कंपनी ड्रायड ग्लोबल ने कहा है कि पनामा के फ्लैग वाला ग्लोरी इंटरनेशनल कंपनी के इस तेलवाहक जहाज का नाम एजफाल्ट प्रिंसेज है। ज्ञात हो कि यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब ईरान की परमाणु समझौते को लेकर पश्चिमी देशों से तनातनी चल रही है। इससे पहले मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड आपरेशंस ने चेतावनी दी थी कि एक घटना हो रही है और बाद में कहा गया कि एक जहाज को हाईजैक किया जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस घटना में ईरान की किसी भी प्रकार की भूमिका से इन्कार किया है।

भारत को वैक्सीन उत्पादन में मदद कर रहा है अमेरिका : बाइडन

▶ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा-दुनिया को कोरोना के टीके की आधा अरब खुराक देने के लिए प्रतिबद्ध

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका, भारत समेत कई देशों को वैक्सीन उत्पादन में हरसंभव मदद कर रहा है। अमेरिका दुनिया को टीके की आधा अरब खुराक देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बाइडन ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, 'हम आधा बिलियन से अधिक खुराक की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरीखे देश खुद वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम हों, इसके लिए और अधिक क्षमता प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। हम ऐसा करने में उनकी मदद कर रहे हैं।' वैसे यह मुफ्त है। हम किसी से कुछ भी नहीं ले रहे हैं और जितना संभव है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं।

उधर, अमेरिका ने बताया कि उसने अफगानिस्तान से लेकर जाम्बिया तक 60 से अधिक देशों को कोविड-19 के टीकों की 11 करोड़ से अधिक खुराकें भेजी हैं। यह जानकारी अमेरिका में कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच दी गई है, जहां डेल्टा स्वरूप का अधिक प्रभाव है।

व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। एएफपी

बाइडन ने वादा किया है कि अमेरिका दुनिया के लिए 'टीकों का शस्त्रागार' होगा। अमेरिका ने कोवैक्स नामक वैश्विक टीका कार्यक्रम के माध्यम से बड़े पैमाने पर टीकों का दान किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, अमेरिका अगस्त के अंत में फाइजर टीके की पांच लाख खुराक भेजना शुरू करेगा, जो उसने जून 2022 तक 100 कम आय वाले देशों को देने का वादा किया है। बाइडन ने जून के अंत तक विदेश में आठ करोड़ से अधिक खुराक भेजने का वादा किया था, लेकिन रसद और नियामक बाधाओं के कारण वह केवल इसका एक ही हिस्सा भेज पाने में सक्षम हुआ है।

भारतीय अमेरिकी डाक्टरों ने कोविड राहत के लिए जुटाए 50 लाख डालर

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारतीय मूल के चिकित्सकों के एक संगठन के भारतीय अमेरिकी डाक्टरों ने भारत को वैश्विक महामारी से राहत के लिए 50 लाख डालर (करीब 37.10 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। अमेरिकन एसोसिएशन आफ फिजिशियन आफ इंडियन ओरिजिन (एएपीआइ) के अध्यक्ष डा. अनुपमा गोतिमुकुला ने मंगलवार को कहा कि प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी चिकित्सकों ने इस धन का इस्तेमाल भारत में 45 अस्पतालों को 2300 आक्सीजन कान्सन्ट्रेटर, 100 वेंटिलेटर और 100 उच्च प्रवाह वाले नेजल कैनुला मशीन मंगाई गई हैं।

वुहान में तेजी से फैल रहा कोरोना, पूरा शहर किया सील

बीजिंग, एपी : चीन के वुहान शहर में फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से स्थिति खराब हो रही है। यहां सभी का टेस्ट किए जाने के दौरान शहर को सील कर दिया गया है। पूरे देश में संक्रमण को लेकर हाई एलर्ट कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने का संबंध पूर्वी शहर नानजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को माना जा रहा है। इस शहर का 17 प्रांतों से संपर्क रहता है। रायटर के अनुसार, चीन में कोरोना संक्रमण का यह कहर डेल्टा वैरिएंट के कारण शुरू हुआ है। संक्रमण बढ़ने के साथ ही स्थानीय फ्लाइट की संख्या बहुत ज्यादा कम कर दी गई है। यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

इधर ब्रिटेन में भी चिंता बढ़ने लगी है। लंदन में मार्च के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 138 लोगों की मौत हुई। 21691 नए मरीज मिले हैं। ब्रिटेन वर्तमान में डेल्टा वैरिएंट से जूझ रहा है। देश में अब 16 और 17 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जा सकती है। अमेरिका में भी तेजी से बढ़ रहे संक्रमण का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन लगाने का काम और तेज कर दिया गया है।

दक्षिण चीन सागर में चार युद्धपोत भेजेगा भारत

▶ दो महीने के लिए होगी चार युद्धपोतों की तैनाती

नई दिल्ली, रायटर : लद्दाख में दादागीरी दिखा रहे चीन को भारत उसी की भाषा में जवाब देने जा रहा है। इस कवायद में दक्षिण चीन सागर में चार युद्धपोत भेजने की तैयारी चल रही है। इनकी दो महीने के लिए तैनाती होगी। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। जबकि ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश इसका करते हैं।

नौसेना ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में दो महीने के लिए एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और एक मिसाइल फ्रिगेट समेत चार युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। बयान के अनुसार, 'भारतीय नौसेना के पोतों की तैनाती शांतिपूर्ण मौजूदगी और मित्र देशों के साथ एकजुटता जाहिर करने के साथ समुद्री क्षेत्र में व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए होगी।' नौसेना ने बताया कि भारतीय युद्धपोत तैनाती के दौरान अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ सालाना युद्धाभ्यास भी करेंगे।

बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चीन

फाइल फोटो। इंटरनेट मीडिया

के दावे को चुनौती देने के लिए अमेरिका अक्सर ही इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करता रहता है। अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के ज्यादातर दावों को अवैध करार दे चुका है। गत जून में नियमित मिशन के तहत अमेरिकी युद्धपोतों का एक बेड़ा इस विवादित जल क्षेत्र में दाखिल हुआ था। इस बेड़े में विमानवाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड भी शामिल था। जबकि इसी महीने ब्रिटेन के युद्धपोत भी फिलीपींस सागर में सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। चीन क्षेत्र में इन देशों के सैन्य अभ्यास की आलोचना करता है।

वाट्सएप पर 'व्यू वन्स' वाले नए फीचर की हुई शुरुआत

नई दिल्ली, आइएएनएस : इंटरनेट मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफार्म फेसबुक की कंपनी वाट्सएप में 'व्यू वन्स' नामक नया फीचर शुरू हो चुका है। इस विकल्प में चैट में भेजा गए फोटो और वीडियो एक बार देखने के बाद गायब हो जाते हैं। यह फीचर फोटो मैसेजिंग एप स्नैपचैट से मुकाबले के लिए तैयार किया गया है।

वाट्सएप में प्राप्तकर्ता के फोन पर यह फोटो और वीडियो फिर स्वतः ही किसी मीडिया फाइल या गैलरी में सेव भी नहीं होते हैं। वाट्सएप का कहना है कि यह फीचर उसने गैर जरूरी फोटो या वीडियो या फिर बेहद संवेदनशील जानकारी जैसे कोई पासवर्ड की सुरक्षा के लिए तैयार किया है। अगर आप कोई किसी दुकान में कोई नई ड्रेस ट्राई करने के बाद किसी को राय लेने के लिए फोटो भेजते हैं, तो सेंडर के देखने के बाद वह फोटो स्वतः ही चैट से गायब हो जाएगी। इसी तरह, वाइफाई के पासवर्ड जैसी जानकारी भी एक बार

भेजे गए फोटो और वीडियो एक बार देखने के बाद स्वतः होंगे गायब

देखने के साथ ही गायब होने से हमेशा सुरक्षित रहेगी। वाट्सएप यूजर्स से इस नए फीचर पर उनकी राय भी जानना चाहता है। इस निजी और गायब होने वाली मीडिया विकल्प के जरिये लोगों को अपने डाटा को सुरक्षित रखने और गैर जरूरी को हटाने के लिए, विशेष प्रयास नहीं करने होंगे। 'व्यू वन्स' सेंड करने के पहले एक लिखे वैकल्पिक की बटन के साथ नजर आएगा। यह बटन दबाने के बाद सेंड का बटन प्रेस करना होगा। 'व्यू वन्स मीडिया' की विशेषता यह भी होगी कि यह एंड टू एंड इनक्रिप्शन से सुरक्षित होगा। इसके तहत भेजी गई फोटो या वीडियो को देखने के बाद शेयर, फारवर्ड नहीं कर सकेंगे।

कैपिटल हिल हिंसा में दो और पुलिस अफसरों ने की आत्महत्या

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका में छह जनवरी को कैपिटल हिल (संसद) में हुई हिंसा के दौरान सुरक्षा से जुड़े दो और पुलिस अफसरों ने आत्महत्या कर ली है। इससे पहले दो पुलिस अफसर इसी तरह से अपनी जान ले चुके हैं। कोलंबिया पुलिस ने बताया कि मेट्रोपोलिटन पुलिस अधिकारी गुंथर हाशिदा अपने घर में मृत मिले हैं। उन्होंने आत्महत्या की है। गुंथर कोलंबिया पुलिस में मई 2003 में शामिल हुए थे। एक अन्य मेट्रोपोलिटन पुलिस आफिसर काइले डीफ्रेटाग की 10 जुलाई को मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार उन्होंने भी आत्महत्या की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर हुए चुनाव के परिणाम आने के बाद अपनी हार से बौखलाकर ट्रंप के भाषण के बाद उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद जिसे कैपिटल हिल कहा जाता है, पर हमला कर दिया था। यहां जमकर हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। सौ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब इस घटना की जांच चल रही है।

प्रतिभाशाली ब्रिटिश छात्रों के लिए भारत भी रोजगार का ठिकाना

▶ विदेश में पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट के लिए नई टूरिंग स्कीम

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के 40 हजार छात्र-छात्राएं विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार की टूरिंग स्कीम के तहत इन विद्यार्थियों को भारत सहित 150 स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। यह स्कीम यूरोपीय यूनियन के अलगाव के बाद ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न देशों से बात करके लागू की है। इसके स्कीम के तहत विद्यार्थी पढ़ाई के साथ काम भी कर सकते हैं।

शिक्षा विभाग ने कहा है कि एरास्मस स्कीम के तहत प्लेसमेंट के लिए न्यूनतम समय सीमा तीन महीने से घटाकर चार सप्ताह की गई है। इससे देश से बाहर जाने वाले छात्रों को सरकार बेहतर स्थितियां दे सकेगी। समाज के कमजोर वर्ग से आने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के प्लेसमेंट के लिए 48 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री गाविन विलियम्सन ने कहा है कि हमने दुनिया की सबसे अच्छी संस्थाओं के साथ समझौता कर टूरिंग स्कीम लागू की है। इससे ब्रिटिश सरकार का ब्रेक्जिट के बाद का नजरिया परिलक्षित होता है। इससे नई पीढ़ी को यूरोप की सीमाओं के बाहर सुनहरे अवसर मिलेंगे। पहले इस तरह का समझौता यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ ही था।

विलियम्सन ने कहा, घर से दूर दूसरे देश में पढ़ाई के साथ काम करने से दिमाग विकसित होता है। यह जीवन की बड़ी उपलब्धि भी बन सकती है। ब्रिटेन के 120 विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों को टूरिंग स्कीम के तहत आवेदन भेजने के लिए कहा गया है। यह स्कीम मार्च महीने से लागू हो चुकी है। इस स्कीम को फादर आफ माडर्न कंप्यूटिंग एलन टूरिंग का नाम दिया गया है, जिन्होंने अमेरिका की प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के उपरांत द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी के नाजी इनिग्मा कोड को समझने में सफलता हासिल की थी।

भारतीय अमेरिकियों ने मनाया अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जश्न

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारतीय अमेरिकियों ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर एक सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर उनके एक समूह ने कहा,जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 40 फीसद की कमी आई है।

कैपिटल हिल में 'कश्मीर : मूविंग फारवर्ड इन डेनजरस जोन' विषय पर हिंदू पालिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव ने परिचर्चा की मेजबानी की। इसमें अमेरिका के विश्व हिंदू परिषद और ग्लोबल कश्मीरी पंडित डिस्पोरा के साथ ही कश्मीरी व अफगान समुदाय के सदस्यों ने भी शिरकत की है। कार्यक्रम में अमेरिकी कांग्रेस के अधिकारी, एनजीओ के नेता शामिल हुए और पाकिस्तान की सेना व खुफिया एजेंसियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया। ज्ञात हो, विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के भारत दौरे के मद्देनजर 29 जुलाई को 'हैशटैग कश्मीर फारवर्ड' का दो हफ्ते का कार्यक्रम शुरू किया गया था।

रवि ने आखिरी मिनट में पिन फाल मारकर पदक किया पक्का

आज स्वर्ण के लिए लड़ेंगे दहिया

चीबा (जापान), प्रेट्र : युवा भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलिंपिक में हारी हुई बाजी जीतकर फाइनल का टिकट कटा लिया। उन्होंने आखिरी मिनट में पिन फाल मारकर 57 किग्रा फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में कजाखस्तान के नूरइस्लाम सानायेव को शिकस्त दी। नूरइस्लाम ने इस मुकाबले के दौरान रवि के हाथ में दांत से काटकर खुद को बचाने की भी कोशिश की लेकिन भारतीय पहलवान टस से मस नहीं हुआ। इससे पहले रवि ने अपने पहले दौर के मुकाबले में कोलंबिया के टिगरेरोस उरबानो आस्कर एडवर्डो को 13-2 से और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बुल्गारिया के जार्जी वेलेंटिनोव वेंगेलोव को 14-4 से पराजित किया। हरियाणा के रवि अब स्वर्ण पदक के मुकाबले में गुरुवार को मौजूदा विश्व चैंपियन रूस के जावुर युगुएव से भिड़ेंगे, जिनसे वह 2019 विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हार गए थे।

पिन फाल ने दिलाई जीत : सेमीफाइनल में दहिया के पास पहले दौर के बाद 2-1 की बढ़त थी, लेकिन सानायेव ने उनके बायें पैर पर हमला बोलकर तीन बार उन्हें पलटने पर मजबूर करते हुए छह अंक ले लिए। फिर एक समय दहिया 2-9 से पीछे हो गए और ऐसा लग रहा था कि दहिया हार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय पहलवान ने संयम नहीं खोते हुए वापसी की और एक मिनट में बाजी पलट दी। उन्होंने विरोधी पहलवान के दोनों पैरों पर हमला किया और उसे कसकर पकड़ लिया। इसके बाद उसे जमीन पर पटखनी देकर पिन फाल से मुकाबला जीत लिया। इसमें अगर कोई पहलवान विरोधी के दोनों कंधे जमीन पर लगा दे तो मैच वहीं खत्म हो जाता है। दहिया ने सभी मुकाबले तकनीकी दक्षता के आधार पर अपने नाम किए थे।

सेमीफाइनल के दौरान कजाखस्तान के नूरइस्लाम ने रवि के दाहिने हाथ में काटा जिसके निशान आसानी से देखे जा सकते हैं • एपी

ओलिंपिक के बाद शादी करेंगे

नंदकिशोर भारद्वाज • सोनीपत

भारतीय पहलवान रवि दहिया ओलिंपिक के बाद शादी करेंगे। रवि के पिता राकेश दहिया ओलिंपिक से पहले उनके लिए लड़की देख रहे थे, लेकिन रवि ने मना कर दिया था। अब पदक जीतकर लौटने के बाद रवि की शादी पर उसके पिता राकेश दहिया विचार करेंगे। वहीं, रवि की जीत के बाद बुधवार शाम को उनके गांव नाहरी (सोनीपत) में ग्रामीणों ने दीये जलाकर दीपावली मनाई। इसके बाद युवाओं की टोली ने पूरे गांव की गलियों घूमते हुए ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया। इसके बाद गांव में घी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई। गांव में दिनभर उत्सव जैसा माहौल बना रहा। गांव नाहरी की चौपाल में बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। रवि के जीतते ही भारत माता की जय, रवि जिंदाबाद, हमें स्वर्ण चाहिए के नारे गूंजते थे। राकेश पेशे से किसान हैं। आर्थिक तंगी से जूझते हुए राकेश ने रवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। राकेश दूसरे बेटे पंकज को भी पहलवान बना रहे हैं। इससे पहले रवि ने कुश्ती से पहले मंगलवार को अपने छोटे भाई पहलवान पंकज और चचेरे भाई पहलवान साजन से वीडियो काल पर बात की थी। रवि ने दोनों से कहा था कि ऐसा प्रदर्शन करूंगा की दुनिया देखती रह जाएगी।...और रवि ने सचमुच ऐसा ही खेल दिखाया। रवि के तीनों कुश्ती जीतते ही दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती देख रहे पंकज और साजन ने साथी पहलवानों के साथ जश्न मनाया।

1952 के हेलसिंकी ओलिंपिक में केडी जाधव भारत को कुश्ती में पदक दिलाने वाले पहले पहलवान थे जिन्होंने कांस्य पदक जीता था

2016 रियो ओलिंपिक में महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कांस्य पदक हासिल किया था

2008 बीजिंग ओलिंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। फिर 2012 लंदन ओलिंपिक में उन्होंने रजत जीता था। इस ओलिंपिक में योगेश्वर दत्त ने भी कांस्य पदक जीता था

> मुझे सानायेव को उतनी बढ़त लेने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। मैं इससे खुश नहीं हूं। मैं उसे दो बार पहले भी हरा चुका हूं तो मुझे पता था कि पिछड़ने के बावजूद वापसी कर सकता हूं। यह करीबी मुकाबला था और मुझे बढ़त गंवानी नहीं चाहिए थी। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं यहां एक लक्ष्य लेकर आया हूं और वह अभी अधूरा है। **रवि दहिया**

2012 में सुशील कुमार लंदन ओलिंपिक के फाइनल में पहुंचे थे और फाइनल में पहुंचने वाले रवि दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। सुशील ने तब रजत पदक जीता था

सेमीफाइनल जीतने के बाद शान से खड़े रवि और जमीन पर पड़े नूरइस्लाम • रायटर

हाकी में पदक जीतने का मौका

टोक्यो, प्रेट्र : सेमीफाइनल में मिली हार को भुलाते हुए भारतीय पुरुष हाकी टीम को 41 साल बाद ओलिंपिक में पदक जीतने का सपना पूरा करने के लिए गुरुवार को रियो ओलिंपिक की कांस्य पदक विजेता जर्मनी के खिलाफ तीसरे चौथे स्थान के प्लेआफ मुकाबले में अपने डिफेंस को मजबूत रखना होगा । दुनिया की तीसरे नंबर की टीम भारत को सेमी फाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम ने 5-2 से हराया। बेल्जियम का फोकस पेनाल्टी कार्नर बनाने पर था और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल कर चुके एलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने हैट्रिक लगाई। भारत पर शुरू ही से दबाव बनाते हुए उन्होंने भारतीय रक्षण को भी छितर बितर कर दिया। पूरे मैच में भारत ने 14 पेनाल्टी कार्नर गंवाए जिनमें से आठ आखिरी क्वार्टर में गए। आठ बार की चैंपियन भारतीय हाकी टीम ने ओलिंपिक में आखिरी पदक 1980 में मास्को में जीता था। भारतीय डिफेंडरों को अब जर्मनी के खिलाफ ऐसी गलती करने से बचना होगा जो उन्होंने बेल्जियम के खिलाफ की। टीम में चार विश्वस्तरीय ड्रैग फ्लिकर रूपिंदर पाल सिंह, उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह, वरुण कुमार और अमित रोहिदास के होते हुए भी भारतीय टीम पांच में से एक ही पेनाल्टी कार्नर तब्दील कर सकी। उसे इसमें सुधार करना होगा।

रियो के दर्द को भुलाकर टोक्यो में उतरेंगी विनेश

नई दिल्ली, जेएनएन : रियो ओलिंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट पदक के दावेदारों में शामिल थीं, लेकिन एक चोट ने उनके पदक के सपने को तोड़ दिया था। वह क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान अपने दायें पैर में चोट खा बैठीं, जिसके बाद उन्हें मैट छोड़कर रियो से वापस आना पड़ा था और अब वह अपने उस दर्द को भुलाकर टोक्यो में गुरुवार को उतरेंगी। हरियाणा की विनेश (महिला 53 किग्रा) अपनी स्पर्धा में शीर्ष वरीय पहलवान के रूप में उतरेंगी। उनका प्री-क्वार्टर फाइनल में स्वीडन की सोफिया मेडिसन से होगा। वह जापान की मायू मुकाइदा के अलावा सभी विरोधियों को हराने में सक्षम हैं। विनेश के वर्ग में प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी होगी। विनेश का डिफेंस बेहतर हुआ है और उनकी पलटवार करने की क्षमता का कोई सानी नहीं है। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में खिताब जीतने के दौरान इसे दिखाया भी है। एशियाई चैंपियनशिप और अन्य प्रतियोगिताओं में जापान और चीन की पहलवानों ने हिस्सा नहीं लिया था।

एकतरफा हारे दीपक

चीन के जुशेन को अपने जाल में फंसाए दीपक • एपी

टोक्यो : एक और भारतीय पहलवान दीपक पूनिया 86 किग्रा के सेमीफाइनल में अमेरिका के 2018 विश्व चैंपियन डेविड मौरिस टेलर से एकतरफा मुकाबले में हार गए। टेलर की तकनीकी दक्षता का पूनिया के पास कोई जवाब नहीं था। जवाबी हमले पर वह एक ही मूव बना सके, लेकिन टेलर ने उन्हें अंक नहीं लेने दिया। पूनिया का सामना अब माइलेस एमिने और अली शाबानाउ के बीच होने वाले रेपचेज मुकाबले के विजेता से होगा। उन्होंने आसान ड्रा का पूरा फायदा उठाते हुए पहले दौर में नाइजीरिया के एकेरेकेमे एगियोमोर को मात दी जो अफ्रीकी चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीन के जुशेन को 6-3 से हराया।

अंशु के पास अब भी मौका : 19 वर्ष की अंशु मलिक महिलाओं के 57 किग्रा के पहले मुकाबले में यूरोपीय चैंपियन बेलारूस की इरिना कुराचिकिना से 2-8 से हार गईं। उन्हें हालांकि पदक जीतने का एक और मौका मिलेगा क्योंकि इरिना फाइनल में पहुंच गई हैं। अब अंशु गुरुवार को रेपचेज में खेलेंगी और कांस्य की दौड़ में होंगी।

कई बार जीतते हैं, कई बार सीखते हैं

विजेंद्र सिंह
कलम से

मुक्केबाजी में भारतीय ओलिंपिक पदक विजेताओं के छोटे से क्लब में लवलीना बोरगोहेन का स्वागत करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। एमसी मेरी कोम और मुझे 2016 रियो ओलिंपिक में किसी अन्य मुक्केबाज का इस क्लब में स्वागत करने का मौका नहीं मिला लेकिन टोक्यो में एक अच्छी मुक्केबाज का अपने पहले ही ओलिंपिक में पदक जीतना और इस क्लब में शामिल होना अच्छी बात रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह 2024 के पेरिस ओलिंपिक में और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। लवलीना ने विश्व नंबर दो तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली को टक्कर दी, जिनके पास 69 किग्रा भारवर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में अच्छी योजना थी। लवलीना ने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बुसेनाज बेहतर मुक्केबाज साबित हुईं। लवलीना ये बात समझेंगी कि कई बार आप जीतते हैं तो कई आप सीखते हैं।

सवाल ये है कि एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जिनसे पहले कभी मुकाबला नहीं हुआ था, लवलीना जीतने के लिए और क्या बेहतर कर सकती थीं? ईमानदारी से कहूं तो दोनों के बीच चुनने में काफी कम अंतर था। शुरुआत में लवलीना के आक्रामक पंचों के बावजूद तुर्की की मुक्केबाज तीनों राउंड में अपनी योजना पर अमल करने में पूरी तरह कामयाब रहीं। ये बात साफ थी कि लवलीना पहले राउंड में दबदबा बनाना चाहती थीं। शुरुआती दो मिनट में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन उसके बाद बुसेनाज ने पंचों की बारिश कर दी। इसके बाद बुसेनाज को पहला गेम कब्जाने में कोई समस्या नहीं हुई।

मुझसे पूछा गया कि क्या इस मुकाबले में बुसेनाज ने खेलभावना का अपमान किया? तो मुझे लगता है कि ये खेल का हिस्सा है और हमें इसका जवाब एक मुस्कुराहट से ही देना चाहिए और किसी चीज से नहीं। मैं कहूंगा कि लवलीना ने मुक्केबाजी टीम को टोक्यो से खाली हाथ लौटने से रोक दिया। हालांकि मुझे अमित पंघाल और विकास के प्रदर्शन से निराशा हुई। (टीसीएम)

भारत के आज के मैच

पदक के मुकाबले

कुश्ती : रवि कुमार (स्वर्ण पदक का मुकाबला), शाम 4:00 बजे के बाद
- दीपक पूनिया (कांस्य पदक का मुकाबला), शाम 4:00 बजे के बाद
- अंशू मलिक (रेपचेज दौर), सुबह 7:30 बजे के बाद

हाकी (पुरुष) : कांस्य पदक का मैच, सुबह 7:00 बजे से, बनाम जर्मनी

एथलेटिक्स : 20 किमी पैदल चाल (पुरुष वर्ग) : फाइनल, दोपहर 1:00 बजे

खिलाड़ी : केटी इरफान, राहुल रोहिल्ला, संदीप कुमार

अन्य मुकाबले

कुश्ती : विनेश फोगाट, अंतिम-16, सुबह 8:00 बजे

गोल्फ : महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 2, सुबह 4:00 बजे से

खिलाड़ी : अदिति अशोक और दीक्षा डागर

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

शीर्ष पर रहकर नीरज फाइनल में पहुंचे, शिवपाल बाहर

टोक्यो, प्रेट्र : भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने ओलिंपिक की भाला फेंक प्रतियोगिता के क्वालीफाइंग में बुधवार को यहां शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई, लेकिन शिवपाल सिंह लचर प्रदर्शन करते हुए पदक की दौड़ से बाहर हो गए। ओलिंपिक पदार्पण कर रहे चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में भाले को 86.65 मीटर की दूरी तक फेंककर 83.50 मीटर का क्वालीफिकेशन स्तर हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई और पदक की उम्मीद जगाई।

एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों व एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद अपने बाकी दो प्रयास नहीं करने का फैसला किया। क्वालीफिकेशन में तीन प्रयास का मौका मिलता है जिसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रयास को गिना जाता है। भाला फेंक में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी से 83.50 मीटर का स्वतः क्वालीफिकेशन स्तर हासिल करने वाले खिलाड़ियों सहित शीर्ष 12 खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल सात अगस्त को होंगे। विश्व जूनियर चैंपियन चोपड़ा ग्रुप-ए व बी में 32 खिलाड़ियों में शीर्ष पर रहे। उनका निजी व सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 88.07 मीटर है जो उन्होंने मार्च 2021 में पटियाला में इंडियन ग्रांप्रि-3 में बनाया था। वहीं, शिवपाल ने निराश किया। वह अपने पहले प्रयास में 76.40 मीटर, दूसरे में 74.80 मीटर और तीसरे प्रयास में 74.81 मीटर की दूरी ही तय कर पाए और 27वें स्थान पर रहे।

शिवपाल 86.23 मी के अपने निजी सर्वश्रेष्ठ व 81.63 मी के सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। ग्रुप-ए से रियो ओलिंपिक में चौथे स्थान पर रहे और टोक्यो खेलों में खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे जर्मनी के योहानेस वेटर (85.65 मी) व फिनलैंड के लेसी एटलेटालो (84.50 मी) भी क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहते हुए क्वालीफिकेशन स्तर हासिल करने में सफल रहे। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी व 2017 के विश्व चैंपियन वेटर ने अंतिम प्रयास, जबकि लेसी ने पहले ही प्रयास में फाइनल में जगह बनाई। एटलेटालो का यह प्रयास उनका सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वेटर ने इससे पहले कहा था कि चोपड़ा के लिए ओलिंपिक में उन्हें हराना मुश्किल होगा, लेकिन क्वालीफिकेशन में भारतीय खिलाड़ी जर्मनी के खिलाड़ी पर भारी पड़ा।

विजयी मुद्रा में नीरज चोपड़ा • प्रेट्र

पदक तालिका

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
चीन	32	22	16	70
अमेरिका	25	31	23	79
जापान	21	7	12	40
ग्रेट ब्रिटेन	15	18	15	48
आस्ट्रेलिया	15	4	17	36
आरओसी	14	21	18	53
जर्मनी	8	8	16	32
फ्रांस	6	10	9	25
इटली	6	9	15	30
नीदरलैंड्स	6	8	9	23
भारत	0	1	2	3

नोट: भारत तालिका में 65वें स्थान पर है। आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति)

हारने के बावजूद टोक्यो में देश की बेटियों ने बिखेरी चमक

मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बनीं लवलीना

टोक्यो, प्रेट्र : भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई (69 किग्रा) को महिला वेल्टरवेट वर्ग (69 किग्रा) के सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ हार के साथ कांस्य से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही ओलिंपिक में भारतीय मुक्केबाजों का अभियान एक कांस्य पदक के साथ खत्म हुआ।

ओलिंपिक में पदार्पण कर रही लवलीना के खिलाफ बुसेनाज ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और सर्वसम्मति से 5-0 से जीत दर्ज करने में सफल रहीं। लवलीना का पदक पिछले नौ वर्षों में भारत का ओलिंपिक मुक्केबाजी में पहला पदक है। असम की मुक्केबाज को कई चेतावनियों के बावजूद रेफरी के निर्देश नहीं मानने के लिए दूसरे दौर में एक अंक की कटौती का सामना भी करना पड़ा। लवलीना ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने जो योजना बनाई थी, उसे लागू नहीं कर पाई।' लवलीना ओलिंपिक मुक्केबाजी प्रतियोगिता फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनने के लिए चुनौती पेश कर रही थीं, लेकिन विश्व चैंपियन बुसेनाज ने उनका सपना तोड़ दिया। लवलीना के पास बुसेनाज के मुक्कों का कोई जवाब नहीं था। लवलीना ने मुकाबले की अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन लेकिन बुसेनाज अपने दमदार हुक और शरीर पर जड़े मुक्कों से धीरे-धीरे हावी होती चली गईं। तीसरा दौर पूरी तरह एकतरफा रहा जिसमें लवलीना को दो बार दमदार मुक्के खाने के बाद आठ काउंट (रेफरी मुकाबला रोकर आठ तक गिनती गिनता है) का सामना करना पड़ा। लवलीना हालांकि क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन नीन चिन चेन को हराकर पहले ही पदक पक्का करके इतिहास रच चुकी थी।

लवलीना बोरगोहाई • प्रेट्र

लवलीना के कारण बन रही है गांव की सड़क

गुवाहाटी, एएनआइ: मुक्केबाज लवलीना की वजह से उनके गांव में कई वर्षों बाद सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। राज्य सरकार गोलघाट जिल में उनके घर तक सड़क बनाने का काम शुरू कर चुकी है। सड़क निर्माण कार्य से उत्साहित उनके गांव की एक लड़की ने बताया कि कई वर्षों के बाद सड़क का निर्माण हो रहा है। इससे पहले असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने रविवार को प्रदेश के गोलाघाट जिले में लवलीना के नाम पर एक खेल अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं, लवलीना का सेमीफाइनल मैच देखने के लिए असम विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए रोक दी गई। सदन में मौजूद सभी ने उनका मैच देखा।

भारतीय महिला हाकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारी

टोक्यो, प्रेट्र : दिलेरी व जुझारूपन से इतिहास रच चुकी भारतीय महिला हाकी टीम का ओलिंपिक में पहली बार स्वर्ण जीतने का सपना दुनिया की दूसरे नंबर की टीम अर्जेंटीना ने बुधवार को सेमीफाइनल में 2-1 से जीत के साथ तोड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों के दिल इस हार से जरूर टूटे होंगे, लेकिन उनका सिर फख्र से ऊंचा होगा क्योंकि ओलिंपिक जाने से पहले किसी ने उनके अंतिम-चार में पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी। भारत के पास अभी भी कांस्य पदक जीतने का मौका है जिसके लिए शुक्रवार को उसका सामना ग्रेट ब्रिटेन से होगा।

भारत के लिए गुरजीत कौर ने दूसरे मिनट में गोल किया, लेकिन अर्जेंटीना के लिए कप्तान मारिया बारियोनुएवा ने 18वें और 36वें मिनट में पेनाल्टी कार्नर तब्दील किए। इससे पहले भारतीय टीम ने तीन बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय टीम 1980 के मास्को ओलिंपिक में छह टीमों में चौथे स्थान पर रही थी। उस समय पहली बार ओलिंपिक में महिला हाकी को शामिल किया गया था और राउंड राबिन प्रारूप में मुकाबले खेले गए थे । फाइनल में अर्जेंटीना का सामना नीदरलैंड से होगा।

हार के बाद निराश भारतीय खिलाड़ी • प्रेट्र

बिजली गुल होते ही दूसरे मोहल्ले की ओर दौड़ीं नेहा की मां : सोनीपत शहर के वेस्ट राम नगर की रहने वाली हाकी खिलाड़ी नेहा गोयल के घर उनकी मां सावित्री देवी स्वजन, पड़ोसियों व मीडियाकर्मियों के साथ बैठी मैच देख रही थीं। अचानक ही मोहल्ले की बिजली गुल हो गई। कुछ देर बिजली सप्लाई चालू होने का इंतजार किया। किसी ने बताया कि तकनीकी खामी की वजह से बिजली गायब हुई है और दूसरे मोहल्ले में बिजली सप्लाई चालू है। नेहा की मां तुरंत ही दूसरे मोहल्ले की ओर दौड़ पड़ीं। किसी को कुछ समझ नहीं आया। पड़ोसी के घर जाकर मैच देखने की बात समझ आई तो स्वजन व मीडियाकर्मी भी पीछे चल पड़े।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
संयम और संकल्प का
गुरुवार, 5 अगस्त, 2021

जीवनशैली

सार्थक जीवन का मंत्र है अनुशासन

जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं, तो उसके पीछे किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा होती है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें समय के साथ अनुशासन एवं धैर्य जैसे गुणों को भी आत्मसात करना पड़ता है। चाणक्य ने कहा है कि जो अनुशासित नहीं, उसका न तो वर्तमान है और न भविष्य। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की उम्र के इस पड़ाव पर सक्रियता की एक प्रमुख वजह अनुशासित जीवन ही तो है। आज भी वह अपने प्रोजेक्ट या फिल्मों के लिए बड़ी शिद्दत से मेहनत करते हैं। अपने निर्देशकों एवं साथी कलाकारों के प्रति उनका रवैया सहयोगात्मक होता है। इतनी सफलता प्राप्त करने के बावजूद उनका निश्चित समय पर सेट पर पहुंचना जारी है। तभी तो सिनेमा की बेहद प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में वे इतने वर्षों से एक सम्मानजनक स्थान बनाए हुए हैं। ओलिंपिक में दूसरी बार पदक जीतने वाली पीवी सिंधू को आइसक्रीम, मीठा दही बहुत पसंद है। लेकिन जब वे ओलिंपिक या किसी बड़ी चैंपियनशिप की तैयारी में लगी होती हैं, तो उन्हें यह सब नहीं मिलता है। अपने पास फोन रखने की इजाजत भी नहीं होती। बड़ी बात यह है कि सिंधू को इस बात का कोई मलाल नहीं होता है। वे अपने पूर्व कोच पुलेला गोपीचंद के दिशा-निर्देश एवं सुझाव को मानकर एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करती रही हैं। परिणाम सबके सामने है।

फुटबाल कोच अनादि बरुआ कहते हैं, खिलाड़ियों की तरह हर किसी के जीवन में अनुशासन आवश्यक है। यह हमारी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों की ओर मोड़ता है। उसे सार्थक दिशा देता है। मैंने देखा है कि कैसे एक लक्ष्यविहीन युवा भी अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाकर मानसिक रूप से सशक्त बन सकता है। रेजिंग ए मैथमेटिशियन फाउंडेशन के संस्थापक विनय नायर का मानना है कि जीवन में अनुशासन न होने का मतलब है कि दुविधा एवं ऊहापोह में रहना। एक स्टूडेंट के लिए यह और भी घातक हो सकता है। अनुशासन में रहकर ही हमारा दिमाग हर नियम-कानून को मानने के लिए तैयार होता है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें, तो सभी प्राकृतिक संसाधनों में वास्तविक अनुशासन के उदाहरण मिलते हैं। सूरज और चांद अपने निर्धारित समय पर उगते व अस्त होते हैं। ऋतु नियत समय पर बदलती है।

अंशु सिंह

कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन की गोलाबारी में मेजर देवेंदर पाल सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। किसी तरह जान तो बच गई, पर उनका जख्मी पांव काटना पड़ा, पर अंदरूनी शक्ति से उन्होंने अपना जीवन गौरवपूर्ण बनाया और अपने जैसे दिव्यांग साथियों में हिम्मत भरने लगे। आज वह कहते हैं कि कोरोना है तो क्या हुआ, चुनौतियां किसके सामने नहीं आतीं, हमें अपनी जिजीविषा से इतना मजबूत होना है कि समस्याएं हमारे सामने घुटने टेक दें। मुश्किलों के बावजूद हमें चलते ही जाना है ...

फोटो : इमेजेज बाजार

जिंदगी में संतुष्टि ढूंढ़ें, कमी नहीं

हम अपने जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हमें जो भी प्राप्त हुआ है, हम उसमें कमी ढूंढ़ते हैं। जो मिला है उसी में हम संतुष्ट हों। आनंद की अनुभूति करें। जब हम दूसरे का सुख देखकर दुख महसूस करते हैं, तो हमें अपने सुख की भी अनुभूति नहीं होती। हम सोच से तालमेल नहीं बिठा पाते और मानसिक रोगी बन जाते हैं। अगर आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो शारीरिक तौर पर भी दुखी ही रहेंगे। मन व शरीर एक-दूसरे पर आश्रित हैं। मन खुश, तो तन खुश। मन का प्रभाव शरीर पर, तन का प्रभाव मन पर होता है। मैं हर वक्त उन्मुक्त रहता हूं। अपने आप में स्वतंत्र। किसी बंधन में नहीं हूं। जिम्मेदारियां भी पूरी करता हूं। परमात्मा मेरे निकट रहता है। मैं अपने आप में संतुष्ट व्यक्ति हूं, जिसे कोई तनाव नहीं है।

प्रो. ईश्वर भारद्वाज
डीन एकेडमिक्स, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार

चोट ने संवार दी जिंदगी

सौ.- स्वयं

कारगिल युद्ध के दौरान मैं अखनूर सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर एक पोस्ट पर अपने जवानों के साथ देश की रक्षा कर रहा था। दुश्मन की पोस्ट अस्सी मीटर दूर थी। दुश्मन को मैं तंग करता था, तो उन्होंने दो दिन तक गोलाबारी रोककर मेरी पोस्ट की रेकी की। दो दिन बाद जब गोलाबारी हुई, तो पहला गोला मेरे पास नहीं आया, लेकिन दूसरा मेरे नजदीक आकर ही फटा, जिसके कुछ छर्रे मेरे शरीर में धंस गए। कुछ काटकर चले गए। 73 छर्रे अभी भी मेरे शरीर में मौजूद हैं। मैं युद्धक्षेत्र में लहूलुहान हो गया। बेहोश हो गया। सात डोगरा रेजिमेंट के मेरे शूरवीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेलते हुए मुझे युद्धक्षेत्र से उठाकर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया। ढाई घंटे लगे थे अस्पताल पहुंचने में। तब तक बहुत सारा खून बह चुका था। इस बीच मुझे दिल का दौरा भी पड़ गया। सर्जन ने बोल दिया कि यह मृत शरीर है, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल राजिंदर सिंह, जो एनेस्थिसिस्ट थे, उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझमें कुछ जान महसूस की और निर्जीव बता दिए गए शरीर को जीवित कर दिया। बस उसी दिन से मेरी बदली जिंदगी शुरू हो गई और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। जो कुछ मैंने हासिल किया है, वह चोट लगने की वजह से ही हासिल किया है। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा क्या हुआ है? तो मैं गर्व से कहूंगा कि मेरा घायल होना, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी संवार दी।

बस चलते ही जाना है...

उजाले की ओर

मेजर देवेंदर पाल सिंह
थलसेना के पूर्व अधिकारी एवं मोटिवेशनल स्पीकर

युद्धक्षेत्र में घायल होने के बाद मेरा जीवन बचाने के लिए चिकित्सकों को मेरी एक टांग काटनी पड़ी। बेशक एक कमी आ गई, लेकिन मैंने इस परिस्थिति को स्वीकार किया। क्योंकि जीवन में तरक्की करने और शांत रहने के लिए नियम है कि आपको अपनी हकीकत को स्वीकार करना ही है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, आप में कोई कमी है, अपने अंग को या अपने प्रिय व्यक्ति को खोया है, इसे स्वीकारना होगा। यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। जब तक इन्हें नकारते रहेंगे, आपके जीवन में अशांति और तनाव रहेगा। इसलिए सबसे पहला मंत्र है कि जो जैसा है, अच्छा है। उसे गले लगाइए। इससे बहुत शांति मिलेगी। इस महामारी में आपने जो भी खोया है, उसे स्वीकार कीजिए। मेरी बदली हुई जिंदगी में पहला कदम था स्वीकार्यता।

जगाएं अपनी अंदरूनी शक्ति: इस क्रम में दूसरा कदम है आप जहां है, जैसे हैं, जितनी भी समस्याओं के बीच में हैं, उसमें अपने प्रयासों से अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाएं। आप अपनी मेहनत से समस्याओं को छोटा बना दीजिए। हमें समस्याओं के खिलाफ लड़ना नहीं है। किसी के खिलाफ लड़ने का मतलब है कि आप पहले ही उसके आगे कमजोर पड़ गए। आपको अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। अंदर से इतने मजबूत हो जाइए कि समस्याएं आपके सामने स्वतः घुटने टेक दें। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार का जो सिद्धांत है, वह सत्य है। जब आप मन से जीतते हैं तो जग को जीत लेते हैं, लेकिन अगर मन से हारते हैं, तो आपकी हार निश्चित है। मेरे खयाल से समस्याएं इसीलिए आती हैं, ताकि आप इनसे मजबूत बन सकें। चैंपियंस के साथ ऐसा ही हुआ है। टोक्यो ओलिंपिक में आप मीराबाई चानू और लवलीना को देख लीजिए। लोग कहते हैं इन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। मेरा कहना है कि उन्होंने समस्याएं और सीमित संसाधन होने के बावजूद अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाकर चैंपियन का तमगा हासिल किया।

प्रेरणा बन गई बदली जिंदगी: कारगिल युद्ध (1999) के दौरान दुश्मन की गोलाबारी में मैं बुरी तरह घायल हो गया। तीसरे दिन मेरे पैर में जख्म हो गया। दाहिने पैर के अंगूठे तक रक्त संचार बंद हो गया और मांस गलने लगा। मुझे अखनूर के छोटे अस्पताल से उधमपुर कमांड अस्पताल लाया गया। उससे पहले डाक्टर्स ने पैर की कांट-छांट कर दी थी। जब मैं उधमपुर पहुंचा और पैर की पट्टी खुली तो मुझे नजर आया कि मेरे पांव में घुटने तक मांस वगैरह कुछ है ही नहीं। मैं समझ गया कि पांव में कुछ बचा ही नहीं, तो यह कटेगा ही। मेरे दिल में दो खयाल आए, एक आध्यात्मिक था कि शायद इस बदली हुई जिंदगी को इस तरह जी पाऊंगा, जो मेरे लिए भी अच्छी होगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगी। आज वह खयाल सच्चाई बन गया है। जो विचार उस युवा सैन्य अधिकारी के दिमाग में आया, वह बहुत शक्तिशाली था और शायद ईश्वर का दिया हुआ था। दूसरा विचार मेरा खुद का था, जिसमें मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी जिंदगी में अपने जीवन स्तर और गुणवत्ता से समझौता नहीं करूंगा। जैसे बिंदास जिया हूं, वैसे ही आगे भी जिंदगी जिऊंगा। खुद से किए इस वादे ने मुझे उस रास्ते पर चलाया जिससे कि मेरा पहला विचार हकीकत बन सका।

चुनौतियों का करें सामना : यह सही है कि दिव्यांगता में काफी चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन हर कोई जिंदगी में चुनौतियों का सामना करता है। जिसे ड्राइविंग नहीं आती, उसके सामने वाहन चलाना चुनौती है। जिसे कुछ पकाना नहीं आता, उसके लिए खाना बनाना चुनौती है। हर इंसान के सामने अलग-अलग चुनौतियां हैं। अब आपको इन चुनौतियों का सामना करना है और इनसे जीतना है। यह आपका सोच है। सोचने की शक्ति सभी के पास है, लेकिन अगर आप नकारेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो इस बात को गर्व से कहता हूं कि मैं सबसे भाग्यशाली हूं, क्योंकि यह सोच पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में चुनौतियां मिली ही इसलिए हैं, ताकि मैं ऊपर उठ सकूं। मैं वह विशेष व्यक्ति हूं, जिसे ईश्वर ऊपर उठाना चाहते थे। मेरी एनजीओ का ध्येय वाक्य है 'आइ माइट बी स्लो, बट आइ विल कीप माई फ्लो। आइ वांट टाप, एंड आइ रीच द टाप'। इसका मतलब यही है कि जिंदगी में चलते रहना है। मैं रुकूंगा कभी नहीं, जब तक कि सर्वोत्तम ऊंचाई न पा लूं।

देश को आगे रखकर सोचा: मैं जब वर्ष 2000 में दौड़ा, तो उस समय ऐसे दौड़ने वाला कोई नहीं था, जो एक पैर के बिना दौड़े। इस तरह यह उदाहरण सेट होने लगा कि यह मुमकिन है। इसके बाद मुझे 2011 में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक कृत्रिम पैर दिया, तो मैं उससे भी दौड़ लिया। तब मुझे लगा कि यह संभव है। अब मेरे जैसे जो भाई-बहन हैं, उन्हें मुझे नया नजरिया देना है। उन्हीं दिनों मेरा भी मन हुआ कि मैं पैरालिंपिक्स में जाऊं, लेकिन उस समय भारत में पैरालिंपिक कमेटी निष्क्रिय थी। मेरी उस तरफ जाने की इच्छा तो थी, लेकिन मुझे लगा कि इससे बेहतर है कि अपने जैसे भाई-बहनों को तैयार करूं। जब एक से सौ और सौ से हजार बनेंगे तो मांग बढ़ेगी और व्यवस्था में विकास होगा। दूसरी बात थी कि उस समय जो कंपनियां कृत्रिम पांव बनाती थीं, उनका सोच भी तिरस्कार से भरा होता था कि जैसा मिल रहा है, वैसा ही ले लो। हम और कुछ नहीं कर सकते। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस संकुचित सोच को बदलने के लिए भी मुझे मांग बढ़ानी थी। एक तरफ तो था कि मैं पैरालिंपिक में चला जाऊं और दूसरा था कि ऐसा माहौल बनाऊं कि हजारों और जाने लायक हो जाएं। लेकिन एक सैनिक हमेशा देश के बारे में सोचता है। मैंने भी देश को आगे रखकर सोचा।

2011 में 'द चैलेंजिंग वंस' नाम से एक समूह बनाया, जिसमें भारतीय दिव्यांगों को फौजी जुझारू दिमाग और विचार देने के बारे में सोचा। धीरे-धीरे उनके अंदर आग पैदा की, जुनून पैदा किया और आज बदलाव सामने हैं। दिव्यांग गर्व से घूमते हैं, बाइकिंग, हाइकिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग कर रहे हैं। अगर मेरी टांग नहीं कटती तो शायद मैं इस तरफ नहीं बढ़ पाता।

सोच को दें सकारात्मक मोड़: जिंदगी में स्वावलंबन कुछ हद तक अच्छा होता है, लेकिन कहीं न कहीं हमें उच्च शक्ति की ओर झुकना आना चाहिए। बड़े से बड़ा पेड़ भी तूफान के आगे झुकता है। हमारे किसी भी ग्रंथ को देखिए, उसमें लिखा गया है कि जीवन नाशवान है, जिसे एक दिन खत्म होना ही है। भौतिकता की ओर भागने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई है और हम नकारात्मकता में रहते हैं। जो हुआ है, उसको नकारते रहते हैं या फिर किसी को दोष दे देते हैं। यहां तक कह देते हैं कि जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो ईश्वर कहां है? मुझे लगता है कि कोई तो सुपर पावर है, जो प्रकृति में संतुलन लाता है, तो बवंडर भी लाता है और उससे आपको बचाता भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर कभी नकारात्मक सोच नहीं आता। मुझे भी गुस्सा आता है, निराशा होती है लेकिन उन पलों को अपने स्वस्थ सोच व विचारों से बदलने की कोशिश करता हूं। मैं नकारात्मक विचार को रोकता नहीं, बल्कि उसे सकारात्मक में बदल देता हूं। जब आप नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलने की कोशिश करेंगे, तो धीरे-धीरे यह आदत बन जाएगी और आप नकारात्मक विचारों में रहना कम कर देंगे। जब आपको सकारात्मक विचार बनाने आ जाएंगे, तो आपको उस सोच के अनुसार जिंदगी बनानी भी आ जाएगी।

प्रस्तुति : यशा माथुर

खुश रहने से नहीं होती थकावट

मनोदशा

अरुणा लाडवा
अंतरराष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर

छोटे हों, बड़े या बुजुर्ग। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो यह शिकायत न करता होगा कि मैं थक गया? मुझे थकावट महसूस हो रही है। हर कोई इसका अनुभव करता है। लेकिन प्रश्न है कि हम किस चीज से थक जाते हैं? क्या कोशिश करने से थक जाते हैं? रोजमर्रा के जीवन में आने वाले तनाव एवं परेशानियों से संघर्ष करते-करते थक जाते हैं या जीवन से ही थक गए हैं? अगर आपके भी ये सारे सवाल हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जीवन को सही मायने में समझा ही नहीं है। अगर हम जीवन को एक खेल की तरह देखेंगे, उसका आनंद लेंगे, तो थकावट जैसी शिकायत कभी होगी ही नहीं। दिक्कत तब शुरू होती है, जब हम जटिल या अयथार्थवादी योजनाओं के पूर्ण न होने के कारण प्रश्नों में उलझ जाते हैं और जीवन बोझिल लगने लगता है। कभी आप बच्चों को खेलते हुए देखें। वे खेल में इतने डूबे होते हैं कि हर क्षण का आनंद लेते हैं। इसके अलावा, वे कई सारे सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। लेकिन सीखने की प्रक्रिया को जैसे ही हम हद से ज्यादा औपचारिक बना देते हैं, तब जीवन में भी जकड़न आने लगती है और हमारी खुशी छिन जाती है। हम जीवन रूपी खेल के खेलने का आनंद नहीं ले पाते हैं।

खुशी कभी भी जीतने में नहीं होती, बल्कि खेल में भाग लेकर ही असल मजा लिया जा सकता है। जब हम किसी चीज में रुचि लेते हैं, तो थकावट महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसे दिल से, बिना किसी दबाव के करते हैं। वैसे, थकने के कुछ अन्य शारीरिक व जीवनशैली से जुड़े कारण हो सकते हैं। कुछ मानसिक एवं भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं। सब कुछ हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जरूरत से अधिक या नकारात्मक सोचने से ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए जीवन जीने का रवैया बदलना चाहिए।

इट्सटाइमटुमेडिटेट ब्लाग से साभार

जीने की राह

पलगा रिनपोचे
बौद्ध शिक्षक एवं दार्शनिक

परिवर्तन को करें स्वीकार

आपने कीड़े-मकोड़ों, जीव-जंतुओं को साथ में रहते देखा है। वे आपस में कितने प्रेम के साथ रहते हैं। वे हमें सीख देते हैं कि कैसे प्रेम भाव के साथ खुशी से रहा जा सकता है। आज मानवता के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं। मनुष्य, मनुष्य का ही शत्रु बन गया है। लोग राग-द्वेष-ईर्ष्या के वशीभूत हो गए हैं। जो हमारे सामने होता है या दिखाई देता है, उसे ही हम सत्य मान लेते हैं। उसके पीछे के कारणों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इन दिनों हमें हर चीज से डर लग रहा है। इसलिए जो स्थायी नहीं होता है, हम उसे खारिज कर देते हैं। हम सब कुछ स्थायी होने की अपेक्षा रखते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग नहीं होना चाहते हैं। इस कारण मृत्यु को भी नकार देते हैं। हमारे बाल सफेद हो रहे होते हैं, लेकिन हम उसे डाई करते रहते हैं, क्योंकि हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते या नहीं करना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हम अपने जीवन में करते हैं, जबकि यह अटल सत्य है कि जो इस धरती पर आया है, उसे वापस जाना है। फिर क्यों न स्वयं को यह याद दिलाते रहें कि एक दिन सब छूट जाएगा। यही सत्य है। अगर हम भिक्षुओं की बात करें, तो वे रात्रि में सोने से पहले अपना कप उलट कर सोते हैं। क्योंकि उन्हें स्मृति होती है कि संभव है कि अगली सुबह वह उस कप में चाय या काफी का सेवन करने के लिए जीवित न रहें। सभी को जाना है। ऐसे में क्यों न परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करें। आप दूसरों को जितना देंगे, उतना ही पाएंगे। इसलिए सबके प्रति दया एवं उदारता का भाव रखें। कर्म करें और धैर्य रखें। एक-दूसरे को समझें, सहयोग करें, खुशियां बांटें। बौद्ध धर्म ने हमें यही सिखाया है कि दूसरों के दुख को दूर करो।

(हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ आल्टरनेटिव लर्निंग व ओमनिवर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए संबोधन से)

अपनी राय हमें जरूर बताएं : feature@jagran.com

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 5 अगस्त, 2021 गुरुवार श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वादशी का राशिफल।
आज का राहुकाल: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक।
आज का दिशाशूल: दक्षिण।
पर्व एवं त्योहार: प्रदोष।
विशेष: मंगल अस्त पश्चिम में।

कल 6 अगस्त का पंचांग

कल का दिशाशूल: पश्चिम।
भद्रा: शाम 06:29 बजे से 07 अगस्त को प्रातः 06:56 बजे तक।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 18 घंटे 29 मिनट तक, तत्पश्चात् चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र 06 घंटे 37 मिनट तक, तत्पश्चात् पुनर्वसु नक्षत्र वज्र योग तत्पश्चात् सिद्धि योग मिथुन में चंद्रमा 25 घंटे 54 मिनट तक तत्पश्चात् कर्क में।

मेष: व्यावसायिक प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें, जबकि बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। राजनैतिक योजना में कुछ व्यवधान आ सकते हैं।

वृष: पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

मिथुन: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कर्क: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

सिंह: पिता या घर के मुखिया से तनाव मिल सकता है। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कन्या: जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं। संयम से काम लें। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। गृह उपयोगी वस्तुओं में आशातीत वृद्धि होगी।

तुला: महिला अधिकारी से सहयोग लेने में सफल होंगे। आर्थिक तनाव रहेगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। दांपत्य जीवन सुखमय होगा।

वृश्चिक: व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। चल या अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

धनु: रिश्तों में मधुरता आएगी, लेकिन संतान के व्यवहार से चिंतित हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

मकर: व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कुंभ: यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है। जीवनसाथी का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। दांपत्य जीवन सुखमय होगा।

मीन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

वर्ग पहेली-1658

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
[illegible]

ऊपर से नीचे
[illegible]

कल का हल

[illegible]

जागरण सुडोकू-1658

3							2	4
		7		5	2			
2	5			4	8	6		9
	3				1	9		
7		9	8				5	
	6			9				3
		5				1	3	
9			5		7			
	1	4	2	6		7		5

कल का हल

7	1	4	5	2	3	9	6	8
8	6	2	7	9	4	1	3	5
3	9	5	8	6	1	2	4	7
6	5	3	4	8	2	7	1	9
1	2	9	6	7	5	4	8	3
4	7	8	3	1	9	5	2	6
5	3	1	9	4	8	6	7	2
2	8	6	1	5	7	3	9	4
9	4	7	2	3	6	8	5	1

मौसम

हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा तथा एक-दो स्थानों पर मध्यम वर्षा संभव है। पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर गरज के साथ मध्यम वर्षा तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहेगी।

कल पढ़ें

यह बदलाव भी जरूरी है

अभिनेता मनोज बाजपेयी लगातार डिजिटल प्लेटफार्म पर नजर आ रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म डायल 100 होगी। अपने सफर, डिजिटल, किरदार, कोरोनाकाल में आए बदलाव और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मनोज से बातचीत...

हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं लीला सेठ

1991 में आज ही जस्टिस लीला सेठ ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। वह किसी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थीं। 1978 में दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने का तमगा भी उनके नाम है।

अमेरिका में लगा दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल

वर्ष 1914 में आज ही अमेरिका के ओहायो में क्लीवलैंड के ईस्ट 105 स्ट्रीट और यूक्लिड एवेन्यू के बीच दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई थी। इसमें हरा और लाल रंग था। लाइट बदलने से पहले संकेत के लिए बजर लगा हुआ था।

अटलजी भी दोहराते थे शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियां

प्रसिद्ध लेखक, कवि और शिक्षक शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म आज ही 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की। माधव महाविद्यालय उज्जैन में प्राचार्य और कुलपति रहे। उनकी लिखी पंक्ति 'क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं' को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर दोहराया करते थे। मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1974 में पद्मश्री और 1999 में पद्मभूषण मिला। 27 नवंबर, 2002 को उज्जैन में उनका निधन हो गया।

घर के भीतर पहुंच रहा प्रदूषण का खतरा

लाकडाउन के कारण कई शहरों की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। धुंधलके में बमुश्किल नजर आने वाला इंडिया गेट दूर से ही दिखने लगा था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही थमने से स्माग आश्चर्यजनक रूप से कम हो गया था। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ने और रहन-सहन में बदलाव से एक बात तय है कि घर के भीतर की वायु गुणवत्ता बहुत अहम होने जा रही है। यह खतरा कितना बड़ा होगा और इससे निपटने के क्या रास्ते हैं, इस बारे में अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि हालात बताते हैं कि इस दिशा में समय रहते सोचना होगा। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी आफ यार्क के निकोला कार्सला और डेविड कार्सला ने इस संबंध में कुछ सवालों के जवाब दिए हैं।

साफ-सफाई के दौरान घर को महकाने वाले रसायन भी कई तरह के प्रदूषण कण बनाते हैं।

स्वच्छ ईंधन की भी चुनौतियां

दशकों से वाहन दुनियाभर में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण रहे हैं। हालांकि अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार से जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल का प्रयोग कम होने लगा है। इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से सक्रिय गैस नाइट्रोजन आक्साइड का स्तर भी कम होगा, जो असल में उद्योगों से निकलने वाले ओजोन को न्यूट्रलाइज करता है।

ओजोन ने बढ़ाई चिंता

ऐसा होने से शहरी इलाकों में ओजोन की मात्रा बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन गैस खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन सतह पर यह एक प्रदूषण कण जैसा प्रभाव रखती है। इसलिए वातावरण में ओजोन गैस की अधिकता अस्थमा और सांस की अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है।

चारदीवारी के भीतर की गतिविधियां भी बढ़ाती हैं मुश्किल

घर के भीतर प्रदूषण के मामले में खतरा सिर्फ ओजोन से ही नहीं है। खाना बनाने, ज्यादा तापमान पर मांसाहार पकाने जैसी प्रक्रियाओं में भी कई तरह के प्रदूषण कण पैदा होते हैं। साफ-सफाई के दौरान घर को महकाने वाले रसायन भी कई तरह के प्रदूषण कण बनाते हैं। मोमबत्ती जलाने से नाइट्रोजन आक्साइड और कुछ प्रदूषण कण बनते हैं। इनमें से कुछ प्रदूषण कण स्वयं में ही नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो कुछ ऐसे हैं, जो ओजोन के साथ क्रिया करके नया प्रदूषण कण बना देते हैं। घर की चारदीवारी का प्रदूषण इसलिए चिंता का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि अब लोगों का ज्यादा समय घर के भीतर ही बीतने लगा है। एक अध्ययन के मुताबिक, ब्रिटेन में बच्चे दिनभर में बमुश्किल एक घंटे का समय घर के बाहर बिताते हैं। जाहिर है कि बाहर के मुकाबले घर के भीतर के प्रदूषण कणों से हमारा सामना ज्यादा होता है।

दरवाजे पर खड़ा संकट

ओजोन से हमारा सामना केवल बाहर ही नहीं होता है, बल्कि वातावरण में मात्रा बढ़ने के साथ यह घरों में भी आसानी से प्रवेश करती जाएगी। खिड़कियां, दरवाजे और दीवार की हल्की दरारें भी इसके अंदर आने का रास्ता बन सकती हैं। कंप्यूटर माडल के आधार पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि लाकडाउन के दौरान घर के भीतर ओजोन की मात्रा 50 फीसद तक बढ़ गई थी। ओजोन घर में सफाई आदि में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उत्पादों में मौजूद रसायनों से क्रिया करके नए तरह के प्रदूषण कण भी बना सकती है। इनमें कुछ घातक प्रदूषण कण भी शामिल हैं।

आसान नहीं है पहेली

खिड़कियां और रोशनदान अंदर बनने वाले प्रदूषण कणों को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं, लेकिन वही खिड़कियां ओजोन जैसे प्रदूषण कण को घर में ला सकती हैं। ऐसे में यह पहेली बहुत जटिल हो गई है। इस बारे में जागरूकता लाने और गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि कौन सा प्रदूषण कितना घातक है। उसी के अनुरूप कदम उठाना होगा। नाइट्रोजन आक्साइड और अन्य प्रदूषण कणों के नुकसान पर तो बहुत अध्ययन हुआ है, लेकिन घर के भीतर के बहुत से प्रदूषण कणों के नुकसान पर अब तक ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इनपुट : प्रेट्र जागरण इन्फो

इधर-उधर की

पार्किंग में खड़ी कार का गेट खोलकर अंदर घुसा भालू

सीसीटीवी में कैद हुई घटना, वायरल हो रहा वीडियो • इंटरनेट मीडिया

कैलिफोर्निया, एजेंसी : थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक घटना यही सीख देती है। वहां पार्किंग में खड़ी कार का गेट खोलकर भालू अंदर घुस गया। यह संयोग ही है कि कार में कोई मौजूद नहीं था और भालू बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। वीडियो साझा करते हुए अधिकारियों ने कहा, 'यह वाकया चेताने वाला है। कार का दरवाजा सही तरह से बंद रखें। लापरवाही जानलेवा हो सकती है।' घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायु प्रदूषण बढ़ाता है डिमेंशिया का खतरा

शोध ▸ पीएम 2 .5 या उससे छोटे आकार के प्रदूषक कण बनते हैं कारक

प्रति घन मीटर में एक माइक्रोग्राम की वृद्धि से 16 फीसद बढ़ता है जोखिम

प्रदूषण से एक और खतरा। फाइल फोटो

वाशिंगटन, एएनआइ : वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान के संबंध में एक नया अध्ययन हुआ है। इसके अनुसार, हवा में प्रदूषकों के अत्यंत छोटे कण (फाइन पार्टिकुलेट) डिमेंशिया के उच्च जोखिम से जुड़े पाए गए हैं। बता दें कि डिमेंशिया कई लक्षणों के समूह को कहते हैं, जिनसे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता। चूंकि शरीर को दिमाग ही नियंत्रित करता है, इसलिए डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति अपने नियमित काम ठीक से नहीं कर पाता है।

यूनिवर्सिटी आफ वाशिंगटन के शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण और डिमेंशिया के बीच संबंध जानने के लिए पूर्व में किए गए दो अध्ययनों के डाटा का इस्तेमाल किया। एक अध्ययन में वायु प्रदूषण को मापा गया था और दूसरे में डिमेंशिया के जोखिम वाले कारकों की पड़ताल की गई थी। ताजा अध्ययन का निष्कर्ष इन्वायरमेंटल हेल्थ पर्स्पेक्टिव्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यूनिवर्सिटी आफ वाशिंगटन के इस अध्ययन के मुताबिक, हवा में फाइन पार्टिकल (पीएम 2.5 या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे) की थोड़ी सी भी मात्रा सिएटल क्षेत्र में बढ़ जाने के कारण वहां के निवासियों में डिमेंशिया का जोखिम बढ़ गया। शोधकर्ता और अध्ययन के मुख्य लेखक राचैर शाफर ने बताया, हमने पाया कि इस प्रदूषक की मात्रा प्रति घन मीटर में एक माइक्रोग्राम बढ़ने से डिमेंशिया का जोखिम 16 फीसद तक बढ़ जाता है। यही संबंध डिमेंशिया के एक रूप अल्जाइमर के साथ भी पाया गया।

अध्ययन के लिए सिएटल क्षेत्र के चार हजार से ज्यादा निवासियों को 1994 में एडल्ट चेंजेज इन थाउट (एक्ट) के तहत सूचीबद्ध किया गया था। इनमें से करीब एक हजार लोगों को किसी न किसी समय में डिमेंशिया के लक्षणों से ग्रस्त पाया गया। डिमेंशिया के इन रोगियों की पहचान होने के बाद शोधकर्ताओं ने उनके क्षेत्र में औसत वायु प्रदूषण का आकलन करते हुए यह पता लगाया कि पीड़ित व्यक्ति में किस उम्र में बीमारी का पता चला।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति में 72 साल की उम्र में डिमेंशिया का पता चला तो शोधकर्ताओं ने अन्य लोगों के मामले से इसकी तुलना की कि एक दशक बाद जब वे 72 साल के होंगे तो प्रदूषण के कारण कितना जोखिम होगा। इसके अलावा विश्लेषण में इसका भी आकलन किया गया कि दशक के विभिन्न वर्षों में जब प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई तो क्या असर रहा। अपने अंतिम विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रति घन मीटर में मात्र एक माइक्रोग्राम के अंतर होने पर रहवासियों में डिमेंशिया का जोखिम 16 फीसद तक बढ़ गया।

शाफर ने बताया कि हम जानते हैं कि डिमेंशिया के लक्षण दिखने में वर्षों का समय लगता है और जांच में दशकों बाद पकड़ में आता है। इसलिए जरूरी है कि इस संबंध में अध्ययन दीर्घावधिक होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि डिमेंशिया का जोखिम जहां खानपान, व्यायाम और आनुवंशिकता से भी जुड़ा है, वहीं अब यह बात भी सामने आई है कि वायु प्रदूषण भी जोखिमों के प्रमुख घटकों में शामिल है। इसके मुताबिक, इस बात के सुबूत मिले हैं कि वायु प्रदूषण का असर न्यूरोडिजेनेरेटिव (तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव) के रूप में सामने आता है। इसलिए वायु प्रदूषण वाले स्थानों पर रहने से बचकर डिमेंशिया के जोखिमों को कम कर सकते हैं। पहले यह माना जाता था कि वायु प्रदूषण का असर सांस संबंधी समस्याओं तक ही सीमित होता है, लेकिन बाद में यह भी सामने आया कि इसका दुष्प्रभाव हृदय रोगों में भी होता है और अब इसके प्रमाण मिले हैं कि इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ रहा है।

बच्चों पर कोरोना का लंबे समय तक नहीं रहता असर

अनुसंधान

संक्रमण से जल्दी ठीक होते हैं बच्चे। फाइल

कोरोना के वयस्क मरीजों में ठीक होने के बाद तमाम मामले ऐसे मिले हैं, जिनमें इसके प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं। एक नए अध्ययन में सामने आया है कि बच्चों के मामले में ऐसा नहीं है। बच्चों में कोरोना वायरस का लंबे समय तक असर नहीं रहता है।

मेडिकल पत्रिका लैसेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ में इसको लेकर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार किंग्स कालेज लंदन द्वारा किए गए शोध में यह जानकारी मिली है कि 20 में से केवल एक बच्चे में चार सप्ताह तक कोरोना के लक्षण देखने को मिले। आठ सप्ताह में तो सभी बच्चे पूरी तरह से ठीक हो गए। बच्चों में इस दौरान आमतौर पर सिरदर्द और थकान की शिकायत रही। इन सभी बच्चों में गले में खराश, गंध की कमी, चक्कर आना या दौरे जैसे गंभीर लक्षण नहीं दिखे। शोध के जो नतीजे सामने आए हैं, वह बच्चों के अभिभावकों को राहत देने वाले हैं। अध्ययन करने वाले दल का नेतृत्व करने वाली किंग्स कालेज, लंदन की प्रोफेसर एम्मा डंकन ने बताया कि अधिकांश बच्चों पर कोरोना का असर बहुत कम रहा। टीम ने 5 से 17 वर्ष के ढाई लाख बच्चों या उनकी देखभाल करने वाले परिवारों पर यह अध्ययन किया। कोरोना पाजिटिव बच्चों में हल्के लक्षण पाए गए। अधिकांश में कोरोना के लक्षण पांच दिन तक रहे। कई में चार सप्ताह में कोरोना का असर पूरी तरह समाप्त हो गया। आठ सप्ताह तक तो सभी बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए थे। -आइएएनएस

स्क्रीन शॉट

मिर्ची वाले डंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं अनुपम

अमेरिका में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं अनुपम।

इंटरनेट मीडिया कई बार बहुत नकारात्मक जगह तब बन जाती है, जब स्टार्स लाइव आते हैं और ट्रोलर्स उन्हें भला-बुरा लिखना शुरू कर देते हैं। कई बार सितारे उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बात करें अगर अभिनेता अनुपम खेर की तो उनका मानना है कि ऐसे लोगों को मिर्ची वाले डंडे की जरूरत होती है। बुधवार को अनुपम अमेरिका से अपने फैंस से इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से जुड़े। वह अमेरिका में अपनी 519वीं फिल्म शिव शास्त्री बल्बोआ शूट कर रहे हैं। फिल्म में नर्गिस फाखरी और नीना गुप्ता भी हैं। इस लाइव के दौरान बुरा कमेंट करने वाले एक यूजर को अनुपम ने कहा कि तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची वाला डंडा लगाने की जरूरत है। इस लाइव के बाद मैं तुम्हारा नाम जरूर नोट करके रखूंगा। इस बीच, अनुपम के भाई राजू खेर भी लाइव जुड़ गए। उन्होंने भी कहा कि ऐसे यूजर्स को इस तरह का जवाब देना बहुत जरूरी है। अनुपम कई लोगों के साथ लाइव वीडियो पर जुड़ रहे थे, जिसमें से एक उनके डाक्टर विशाल सावंत भी थे। अनुपम ने बताया कि वह चार-पांच साल पहले डिप्रेशन से गुजर रहे थे। ऐसे वक्त में डाक्टर विशाल ने उनकी मदद की थी। उन्होंने आगे कहा कि डिप्रेशन इतनी बुरा बात नहीं है। अगर आप डाक्टर की मदद लेते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी।

रमेश सिप्पी ने बताया- बिना कुछ कहे, शोले का वह सीन बन गया था रोमांटिक

साल 1971 में फिल्म अंदाज के निर्देशन से अपना करियर शुरू करने वाले निर्देशक-निर्माता रमेश सिप्पी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर के 50 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्मों में अपनी हाफ सेंचुरी पर उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं करियर शुरू करने से पहले यूरोपियन, फ्रेंच, इंग्लैड, हालीवुड और बालीवुड का सिनेमा देखा करता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विमल राय, महबूब खान, राज कपूर, गुरु दत्त के सिनेमा से प्रभावित था। मैं जानता था कि अगर अच्छा सिनेमा बनाना है, तो इन मास्टर्स के काम को फालो करते हुए अपने तरह का सिनेमा बनाना होगा। मैंने अंदाज के बाद सीता और गीता फिल्म बनाई थी। आज से 50 साल पहले फिल्मों में हीरो को ही डबल रोल में देखना दर्शक पसंद करते थे। मैंने सोचा क्यों न महिला कलाकार को लीड में रखा जाए। मैं अपना हर काम पूरी योजना बनाकर करता था। शोले फिल्म में जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बीच एक सीन है, जिसमें वह माउथ आर्गन बजा रहे हैं और बालकनी में आकर जया का किरदार लैंप की लौ को कम कर रही है। उस एक सीन के लिए हमने सूर्यास्त का इंतजार किया था। सेट वैसा बनाया गया था, बालकनी वाला बंगला, सामने आउट हाउस। हमने जया के किरदार का बेडरूम नहीं सेट किया था, क्योंकि फिल्म में उसकी जरुरत नहीं थी। शोले के कैमरामैन ने मुझे कहा था कि बेस्ट इफेक्ट तभी मिलेगा जब सूरज डूबेगा। सूर्यास्त कुछ मिनटों का होता है। हमने लंच से पहले दूसरे सीन्स शूट किए। लंच के बाद पूरा सेटअप लगाया, रिहर्सल की। शाम साढ़े पांच बजे के करीब सूर्यास्त होने लगा। नेचुरल लाइट में लैंप को बुझाने की टाइमिंग भी सही थी। बिना कुछ कहे, सीन रोमांटिक बन गया था।

रमेश सिप्पी ने हिंदी सिनेमा में पूरे किए 50 साल।

संस्कृति और ठेठपने का समावेश होगा हंसते रहो विथ राजू

पिछले कई दशकों से अपनी कामेडी से लोगों को हंसाने वाले कामेडियन राजू श्रीवास्तव करीब सात वर्ष बाद एक बार फिर से टीवी पर नजर आएंगे। वह अपने कामेडी शो हंसते रहो विथ राजू से टीवी पर वापसी कर रहें हैं। राजू इस शो को अकेले होस्ट करेंगे तथा हर एपिसोड में उनके साथ उनके साथ एक नया कलाकार मेहमान के तौर पर भी जुड़ेगा। राजू के साथ तबला वादक सुरिंदर समेत कई अन्य कलाकार भी इस शो का हिस्सा होंगे। अपने इस नए शो के बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में राजू ने बताया, 'हम इस शो को डिजिटल प्लेटफार्म के लिए बना रहे थे। इसी बीच कुछ चैनल वाले हमारा शो देखने आए थे। उन्होंने हमें चैनल के लिए आफर कर दिया तो अब संभव है कि हमारा शो डिजिटल प्लेटफार्म की बजाय टीवी पर चला जाए। शो नया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें नई बातें और नए किरदार होंगे। इस शो में देसीपन बहुत होगा। शो में हमारे देश की संस्कृति और गांवों की ठेठपने का समावेश होगा। हमने इस शो के लिए सिर्फ मेट्रो सिटी को टार्गेट नहीं किया है, इसमें गांवों की बातें ज्यादा होंगी। शो में पारितोष त्रिपाठी, सुगंधा मिश्रा, डाक्टर संकेत भोसले जैसे कई कलाकार मेहमान के तौर पर भी उपस्थित रहेंगे। इस महीने के अंत तक इस शो का प्रसारण शुरू होने की संभावना है।' हालांकि अभी इस शो को प्रसारित करने वाले चैनल के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राजू आखिरी बार साल 2017 में फिल्म फिरंगी में मेहमान भूमिका में नजर आए थे।

करीब सात वर्षों बाद टीवी पर वापसी कर रहे हैं राजू।

उदयपुर में अनुष्का सेन ने मनाया अपना बर्थडे

अनुष्का के मम्मी-पापा ने उन्हें दिया सरप्राइज।

रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 की प्रतियोगी और टीवी अभिनेत्री अनुष्का सेन बुधवार को 19 साल की हो गईं। अपना बर्थडे अनुष्का ने उदयपुर में मनाया। इसकी प्लानिंग उनके पापा ने की थी। बर्थडे पर अनुष्का इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के जरिये प्रशंसकों से जुड़ीं। उनके मम्मी-पापा भी उनके साथ लाइव पर जुड़े। अनुष्का के पापा ने बताया कि मैं पिछले दिनों अनुष्का के साथ खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के लिए केप टाउन गया था। मुझे अनुष्का के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था, लेकिन अनुष्का की मम्मी को कहीं जाने का मौका नहीं मिला था। अनुष्का के बर्थडे पर हमने सोचा कि अच्छा होगा कि पूरा परिवार एक साथ वक्त बिताए। उदयपुर हमने देखा नहीं था, इसलिए यहां आ गए। अनुष्का ने कहा कि अपने बर्थडे पर मैं हर किसी के लिए खुशियां चाहती हूं। अपने क्राफ्ट पर और मेहनत करना चाहती हूं। खुद को अपने किरदारों के जरिये और तलाशना चाहती हूं। अपने माता-पिता को दुनिया घुमाने के सपने को पूरा करना चाहती हूं। अनुष्का ने अपने फैंस को भी यही सलाह दी कि जीवन में जब भी कंफ्यूजन की परिस्थिति आए, तो अपने दिल की सुनें। किसी के लिए अपने सपनों को मत हारने दें। जब भी अच्छा न लगे, अपने माता-पिता से बात करें। आपके माता-पिता आपको हमेशा सही राय देंगे। अनुष्का के मम्मी-पापा इस बात को लेकर बेहद खुश और संतुष्ट नजर आए कि अनुष्का स्टार बनने के बाद भी उनकी बातें सुनती हैं, इसलिए वह अपने अच्छे संस्कार उनमें डाल पा रहे हैं।

(सभी फोटो इंस्टाग्राम से)

वेल बाटम फिल्म में अक्षय कुमार के साथ लारा दत्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखेंगी। वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी।

बेल बाटम में लारा को पहचानना हुआ मुश्किल

कई शहरों में सिनेमाघरों के खुलने की अनिश्चितता के बीच मंगलवार को अक्षय कुमार अभिनीत जासूसी थ्रिलर फिल्म बेल बाटम का ट्रेलर लांच किया गया। फिल्म में लारा दत्ता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। ट्रेलर का आगाज वर्ष 1984 में एक विमान के अपहरण से होता है। एक दृश्य में इंदिरा गांधी अपने सहयोगियों से इस संकट को हल करने पर विचार विमर्श कर रही हैं। ट्रेलर में लारा को पहचानना मुश्किल है। अपने किरदार को लेकर लारा ने दिल्ली में ट्रेलर लांच के मौके पर बताया कि फिल्म निर्माताओं ने उनसे पूर्व प्रधानमंत्री का किरदार निभाने के लिए संपर्क किया था। यह स्क्रिप्ट को सुनने के पहले की बात है। जब आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसे किसी व्यक्तित्व को पर्दे पर उतारने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मेरे लिए किरदार के बाडी लैंग्वेज को आत्मसात करना चुनौती थी। यह फिल्म उनके कार्यकाल के दौरान हुई एक अपहरण की घटना से संबंधित है। वह मामले के केंद्र में थीं और वहां कोई नाटकीयता नहीं थी, इसलिए उसे उस रूप में चित्रित करना महत्वपूर्ण था। इस मौके पर अक्षय कुमार ने कहा, मुझे बड़े पर्दे पर कुछ भी देखे हुए दो साल हो चुके हैं। हम टीवी पर चीजें देख रहे हैं। अब समय लोगों के थिएटर आने का है। साथ ही अक्षय ने लोगों से सुरक्षा और सावधानी बरतने को भी कहा। रंजीत तिवारी निर्देशित बेल बाटम 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बेल बाटम में अक्षय कुमार के साथ दिखेंगी लारा दत्ता • इंस्टाग्राम

इनट्रैप्ड वास्तविक घटना से प्रेरित

फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं अध्ययन सुमन • इंस्टाग्राम

वक्त के साथ फिल्मकार सिनेमा में अलग-अलग प्रयोग करते रहते हैं। कुछ ऐसे ही प्रयोगात्मक कदमों के तहत फिल्म निर्देशक समीर जोशी ने फिल्म इनट्रैप्ड बनाई है। इस फिल्म में अभिनेता अध्ययन सुमन और अभिनेत्री शीतल काले मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म के बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में समीर ने बताया, 'इनट्रैप्ड एक समकालीन थ्रिलर फिल्म है। इस जानर की पूरी फिल्म को किसी एक छोटे कमरे, बाक्स या किसी अन्य छोटी जगह पर फिल्माया जाता रहा है। हमारी पूरी फिल्म एक कार की डिक्की में फिल्माई गई है। इसकी कहानी दो युवाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मस्ती-मजाक में एक कार की डिक्की में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। यह कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, जो मैंने आठ साल पहले अखबार में पढ़ी थी। मैं पिछले पांच साल से इस फिल्म को बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरी मुलाकात प्रोड्यूसर गियोवानी कर्ल से हुई। उन्हें कहानी पसंद आई और वह फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गईं। आडिशन के जरिये अध्ययन सुमन को लिया गया। वह अच्छे कलाकार के साथ वास्तविक जीवन में भी क्लास्ट्रोफोबिक हैं, मतलब उन्हें बंद जगहों में डर लगता है। इस फिल्म के लिए वह उपयुक्त कलाकार थे। इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। आगामी दो-तीन महीनों में यह डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज हो सकती है।'

शाह रुख संग दिखेंगे आशुतोष

सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान में शाह रुख खान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में डिंपल कपाड़िया खुफिया एजेंसी की मुखिया के किरदार में होंगी। खबर है कि रा की इस टीम में एक और सदस्य आशुतोष राणा को जोड़ा गया है। वह इस जासूसी थ्रिलर में सीनियर आफिसर के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जान अब्राहम भी अहम भूमिका में हैं। जान इसमें खलनायक की भूमिका में होंगे। आशुतोष पहले भी वार फिल्म में रा अफसर के रूप में दिखे थे। सूत्रों के मुताबिक आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ का आइडिया था कि अभिनेता पठान में अपनी भूमिका को दोबारा दोहराएं। अभिनेता ने कुछ दिनों पहले अंधेरी के यशराज स्टूडियो में शाह रुख और डिंपल के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग भी की थी। खबरों के मुताबिक डिंपल और आशुतोष के किरदार उस मिशन का मास्टरमाइंड होंगे, जिसमें नायक जान के साथ भिड़ेगा। बताया जाता है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के साथ, आदित्य चोपड़ा वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों के रूप में कपाड़िया और राणा के पात्रों को स्थान देना चाहते हैं, जो जासूसी फ्रेंचाइजी में उनकी भविष्य की फिल्मों में शामिल होंगे। यह तिकड़ी तब पूरी होगी जब निर्माता को यशराज फिल्म्स के बैनर की एक और जासूसी ड्रामा टाइगर 3 में सलमान खान के आन-स्क्रीन बास की भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त अभिनेता मिल जाएगा। दिवंगत नाटककार-अभिनेता गिरीश कर्नाड ने एक था टाइगर (2012) और टाइगर जिंदा है (2017) में रा प्रमुख की भूमिका निभाई थी।

रा अफसर के किरदार में दिखेंगे आशुतोष • जागरण आर्काइव

तमन्ना भाटिया ने साइन की अपनी पहली हिंदी वेब सीरीज

नवाजुद्दीन के साथ फिल्म बोले चूड़ियां में भी नजर आएंगी तमन्ना • जागरण आर्काइव

हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा के सितारे भी डिजिटल प्लेटफार्म की बढ़ती लोकप्रियता से अछूते नहीं हैं। एक तरफ जहां तमिल अभिनेता विजय सेतुपति और तेलुगु अभिनेत्री राशि खन्ना शाहिद कपूर के साथ निर्देशक जोड़ी राज निदिमोरू और कृष्णा डीके द्वारा निर्देशित अनाम वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के भी निर्माता दिनेश विजन की प्रोडक्शन कंपनी मैडाक फिल्म्स के अंतर्गत बन रही वेब सीरीज करने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, तमन्ना को इस शो का कहानी पसंद आई और उन्होंने निर्माता दिनेश विजन से मिलकर अपनी पहली हिंदी वेब सीरीज साइन भी कर ली है। शो में तमन्ना केंद्रीय किरदार में होंगी। अगर सब कुछ सही रहा तो तमन्ना इस महीने के अंत तक इस वेब सीरीज की शूटिंग भी शुरू कर सकती हैं। हाल ही में तमन्ना को मैडाक फिल्म्स के आफिस के बाहर भी देखा गया था। इससे पहले बाहुबली फेम अभिनेत्री तमन्ना ने हाल ही में हाटस्टार प्लस डिज्नी पर रिलीज हुई तमिल और तेलुगु वेब सीरीज नवंबर स्टोरी में काम किया था। हिंदी फिल्मों की बात करें तो तमन्ना आगामी दिनों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म बोले चूड़ियां में नजर आएंगी।